लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
8
Parliament Library

चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)
Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)
(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

1353

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 9 शुक्रवार, 2 जून, 1967/12 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 9 Friday, June 2, 1967/Jyaistha 12, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
241	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हानि	Loss in Hindustan Steel Ltd.	1115-1119
242	रेलवे मैडिकल आफिसर संस्था	Railway Medical Officers' Association	1119-1121
243	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textiles ..	1121-1126
244	ऊन के धागे का मूल्य	Price of Woollen Yarn	1126-1127
245	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant	1127-1128
अ. सू. प्रश्न S. N. Q.			
6	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	1129-1132

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
246	पूंजीगत माल का आयात	Import of Capital Goods	1132-1133
247	चाय उद्योग	Tea Industry	1133
248	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	Lakshmi Rattan Cotton Mills, Kanpur	1133-1134
250	मिलों को कपास का वितरण	Distribution of Cotton to Mills	1134
251	भारत-संयुक्त अरब गण-राज्य यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग	Indo-UAR Yugoslavia Economic Co-operation	1134-1135
252	दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित किया जाना	Dry Port in Delhi ..	1135
253	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of N. C. D. C. Employees	1135
254	कृषि में मशीनों के प्रयोग से औद्योगिक विकास	Industrial Development with Mechanised Agriculture	1136
255	हथकरघा से बने माल का बिन बिका स्टाक	Unsold Stock of Handloom Products	1136

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

256	इंजीनियरी के सामान के निर्यातकों को इस्पात का दिया जाना	Supply of Steel to Exporters of Engineering Goods	1136–1137
257	इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Steel .. .. — ..	1137
258	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निर्यात व्यापार	Export Business of Hindustan Steel Ltd. ..	1137–1138
259	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	1138
260	रुई कताई कारखाने	Cotton Spinning Units	1138–1139
261	इन्जीनियरी उद्योग	Engineering Industries	1139
262	सिगरेट उद्योग	Cigarette Industry	1139–114
263	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	1140
264	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in U. P...	1140–1141
265	पटसन और चाय पर निर्यात शुल्क	Export duty on Jute and Tea	1141–1142
266	सी. आई. स्लीपर	C. I, Sleepers .. —	1142
267	राजस्थान में टंगस्टन धातु निकालना	Mining of Tungesten in Rajasthan	1143
268	एल्यूमिनियम की माँग और उत्पादन	Demand and Production of Aluminium	1143–1144
269	सूत के मूल्य	Prices of Yarn	1144–1145
270	प्राकृतिक साफ्ट कोक	Natural Soft Cock .. —	1145
अता. प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
1251	हिम्मत नगर और उदयपुर के बीच मीटर गेज लाइन पर रेलवे स्टेशन	Railway Stations on M. G, Line between Himmatnagar and Udaipur	1145–1146
1252	सरकारी क्षेत्र के समवायों का बोर्ड	Board of Companies in Public Sector	1146–1147
1253	मैसर्स इंडियन एलक्ट्रिक वर्क्स लि०, कलकत्ता	M/s. Indian Electric wo ks Ltd., Calcutta	1147
1255	मुज़फ्फरपुर और दरभंगा के बीच शाखा लाइन	Branch line between Muzaffarpur and Darbhanga	1148
1256	नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन	Narsinghpur Railway Station	1148–1149
1257	रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाझा	Railway Higher Secondary School, Jhajha	1149
1258	रेलवे की भूमि पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन	Holding of Public Meetings on Railway Grounds	1149

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1259	जन सम्पर्क अधिकारी (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का कार्यालय	Office of Public Relations Officer (S. E. Rly.)	1150
1260	इटारसी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे)	Itarsi Railway Station (Central Railway)	1150-1151
1261	बिहार में औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना	Issue of Industrial Licences in Bihar	1151
1262	दक्षिणी अफ्रीका तथा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार	Trade with South Africa and other Asian Countries	1151-1153
1263	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	1153
1264	नेपा अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Nepa Newsprint Factory	1153
1265	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिल	Textile Mills in M. P.	1154
1266	तिरुनेलवेली और त्रिवेन्द्रम के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Tirunelveli and Trivandrum	1154
1267	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	1154-1155
1268	जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Jessop & Co. Ltd., Calcutta	1155
1269	फरीदाबाद की फर्म के लिए अमरीकी ऋण	U.S. Loan for Faridabad Firm	1155
1270	कागज तथा लुगदी तैयार करना	Manufacture of Paper and Pulp	1155-1156
1271	अमरीका तथा रूस के साथ व्यापार	Trade with USA and USSR	1156
1272	ठेकेदार के नियन्त्रणाधीन हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाना	Change of Contractor Halt Station into Flag Station	1156-1157
1273	उड़ीसा में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Orissa	1157
1275	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के कारखाने	H. M. T. Factories	1157–1158
1276	राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ का ज्ञापन	Memorandum by National Coal Organisation Employees Association	1158
1277	एशियाई आर्थिक विकास तथा योजना संस्था	Asian Institute of Economic, Development and Planning	1158
1278	आयात लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Import Licences	1158-1159

1279	महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Factory in Maharashtra	1159-1160
1280	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	1160
1281	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में बेकार पड़ी वस्तुएं	Inventoriesin the H. E. C. Ranchi ...	1160–1161
1282	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड को मशीनों की सप्लाई	Supply of Machines by H. E. C. Ranchi to Bokaro Steel Ltd.	1161
1283	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने को माल की सप्लाई	Supply of Material by H. E. C. Ranchi to Bhilai Steel Project	1161–1162
1284	गैर-स्नातक राजपत्रित रेलवे अधिकारी	Non-Graduate Gazetted Railway Officer	1162
1285	वियतनाम (लोकतन्त्रीय गणराज्य) के साथ व्यापार	Trade with Democratic Republic of Vietnam ..	1162
1286	ट्रक चालकों तथा रेलवे में प्रतियोगिता	Competition between Truck Operators and Railways .. ... — ...	1162
1287	चावल की भूसी से तेल निकालना	Extraction of Oil from Rice Bran	1163
1288	आयातित मशीनी औजार	Imported Machine Tools	1163
1289	राज्य व्यापार निगम के लिये जूते बनाना	Shoe Making for State Trading Corporation	1164
1290	कम्प्रेसरों का निर्माण	Manufacture of Compressors .. ... —	1164
1291	रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के कर्मचारी	Workers in Railway Electrification Project .. .. — ...	1164-1165
1292	नारियल जटा पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Coir ..	1165
1293	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर	Mining & Allied Machinery Corporation Ltd. Durgapur	1165-1166
1294	बिड़ला समवाय समूह की लाइसैंसों का दिया जाना	Issue of Licences of Birla Group of Firms ..	1166
1295	कोयना में एल्यूमिनियम प्लांट	Aluminium Plant at Koyana —	1166-1167

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1296	कटनी में डीजल स्टोर में आग लगने की घटना	Fire in Diesel Store at Katni	1167
1297	ऊनी धागे का उत्पादन	Production of Woolen Yarn	1167-1168
1298	आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग	Collaboration with Australia ..	1168-1169
1299	चाय परिषदें	Tea Councils	1169
1300	प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign exchange to priority Industries ..	1169-1170
1301	निरीक्षण निदेशालय	Directorate of Inspection	1170-1171
1302	मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Golcha properties (P) Ltd. Delhi	1172
1303	भोजन यान के साथ चलने वाले कर्मचारी	Running Staff attached to Dining Cars	1172
1304	बिहार सरकार द्वारा केन्द्र को खनिजों की सप्लाई	Supply of Minerals to Centre by Bihar Government	1172-1173
1305	हरियाना में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant in Haryana	1173
1306	हरियाणा में खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey in Haryana	1173
1307	इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड, कलकत्ता	Indian Oxygen Ltd., Calcutta	1173-1174
1308	गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की क्षमता को प्रयोग में लाना	Utilisation of Capacity of Private Sector Steel Plants	1174
1309	उड़ीसा में फेरोक्रोम कारखाना	Ferrochrome Plant in Orrisa ..	1175
1310	खेल के सामान का आयात	Import of Sport Goods	1175
1312	रेलवे के लेखा कार्यालयों में राजपत्रित पद	Gazetted posts in Railway Accounts Offices ..	1175-1176
1313	रेलवे विभाग में मशीनों से हिसाब लगाने की पद्धति	Mechanical system of accounting on Railways	1176-1177
1314	हिसाब करने वाली मशीनों का किराया	Rent on Accounting Machines ..	1177

1315	रेलवे विभाग में मशीनों से हिसाब कराने की प्रणाली आरम्भ करने के परिणामस्वरूप रेलवे की आय में कमी	Shortfall in Railway Earnings resulting for Mechanisation of Accounting System on Railways	1177
1316	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	1178
1317	इस्पात की उत्पादन लागत और कीमत	Cost and price of steel...	1178-1179
1318	आविष्कार सवर्धन बोर्ड	Invention Promotion board	1179-1180
1319	इस्पात का मूल्य	Price of steel	1180-1181
1320	दिल्ली-मद्रास जनता और सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ लगाये जाने वाले डिब्बे	Coaches attached to Delhi Madras Janata and Southern Express Trains	1181
1321	जी. टी. एक्सप्रेस रेलगाड़ी	G. T. Express Train	1181-1182
1322	कपड़े के मूल्य	Cloth prices	1182
1325	रेलवे सैलून	Railway Saloons	1183
1326	खुरदा रोड़ स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर	Quarters for Railway Staff at Khurda Road Station	1183-1184
1327	कपड़े के मूल्य	Prices of cloth	1184
1328	ब्रजराजनगर स्टेशन पर गाड़ियों की टक्कर	Collision at Brajarajnagar Railway station	1185
1329	उप्पल (केरल) में डाक गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Mail Trains at Uppala, (Kerala) ...	1185
1330	भोपाल अहमदाबाद रेलगाड़ी में चोरी	Theft in Bhopal-Ahmedabad Train...	1185-1186
1331	अल्वाये रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बे	Wagons at Alwaye Railway Station	1186
1332	काली मिर्च के व्यापार में सट्टेबाजी	Speculation in Pepper Trade ..	1186
1333	मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाएं	Railway Projects in Madhya Pradesh ..	1187
1334	नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई	Water Supply at Narsinghpur Railway Station	1187-1188
1335	केरल में नारियल जटा बनाने वाले उद्योग	Coir Manufacturing Industries in Kerala	1188

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

1336	बिजली तथा डीजल इंजनों का निर्यात	Export of Electric and Diesel Locomotives	1188
1337	हाजीपुर और बालमीकी नगर के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Hajipur and Balmiki Nagar	1189
1338	पश्चिमी रेलवे के गार्डों का स्थानान्तर	Transfer of Railway Guards on western Railway	1189
1339	मैसूर राज्य में इंगलदल में खानों की खोज	Prospecting of Mines at Ingaldal, Mysore	1189-90
1340	झज्झर तथा जींद के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण	Over-Bridges at Railway Crossing Jhajjar and Jind	1190
1341	रेलवे के कुली	Railway Porters	1190-1191
1342	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के रेलवे कर्मचारी	Rai'way Employees of Chittaranjan Locomotive Workshop	1191
1343	रेलवे के कुशल श्रमिकों के वेतन मान	Pay Scales of skilled labour on Railways ...	1191-1192
1344	पटसन की कमी	Shortage of jute ..	1192-1193
1345	मैंगनीज का निर्यात	Export of manganese	1193-1194
1346	रेलवे के शिकायत रजिस्टर	Railway Complaint Books ..	1194-1195
1347	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of coal	1195-1196
1348	झाझा के माल गोदाम को अन्य स्थान पर ले जाना	shifting of goods shed at Jhajha ..	1196
1349	झाझा में रेलवे भूमि का रेलवे कर्मचारियों को अलाटमेंट	Allotment of Railway Land at Jhajha to Railway Employees	1197
1350	राजस्थान में पलाना में लिग्नाइट कोयले की खानें	Lignite Coal Mines in Palan, Rajasthan ..	1197-1198
1351	घग्गर नदी की बाढ़ों से रेलवे लाइन को हुई क्षति	Damage Caused to Railway Lines by Floods in Ghaggar River	1198
1352	गुण मक्सी रेलवे परि-योजना	Guna-Maksi Railway Project	1198-1199
1353	महेंशी रेलवे स्टेशन	Maheshi Railway Station	1199
1354	खुरदा रोड़ में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of Local People at Khurda Road	1199
1355	सीमेंट का मूल्य	Price of Cement	1200
1356	नारियल जटा के धागे के लिये रेल के माल डिब्बों का न यिलना	Non availability of Railway wagons for Coir Yarn	1200

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1357	मुद्रण सम्बन्धी मशीनों का श्रायात	Import of Printing Machinery ..	1200-1201
1358	केरल में सूक्ष्म औजार उद्योग	Precision Industry in Kerala ..	1201
1359	मैसूर और उत्तर केरल के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Mysore and North Kerala	1201
1360	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale industries in Orissa	1201-1202
1361	इस्पात का श्रायात	Import of Steel	1202
1362	उड़ीसा में भारी उद्योग	Heavy Industries in Orissa	1203
1363	छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण	Training in Small Scale Industries ...	1203
1364	उड़ीसा को सीमेंट की आवश्यकता	Requirement of Cement by Orissa ...	1203-1204
1366	राज्य खाद्य बोर्ड	State Khadi Board...	1204-1205
1367	श्रलाभप्रद कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of 'Sick' Textile Mills ...	120 -1206
1368	राजस्थान में औधोगिक विस्तार सेवा	Industrial Extension Serviee in Rajasthan ...	1206-1207
1369	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Rajasthan ...	1207
1370	राजस्थान में भारी उद्योग	Heavy Industries in Rajasthan	1208
1371	राजस्थान में औधोगिक कारखाने	Industrial Units in Rajasthan	1208
1372	निर्माताओं को स्टैनलैस स्टील की सप्लाई	Supply of Stainless Steel to Manufacturers	1208-1209
1373	मद्रास में पुल निरिक्षक श्रनुभाग	Bridge Inspectors Spection in Madras	1209
1374	पूर्वोत्तर रेलवे के तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class III and IV Staff of N. E. Railway	1209
1375	रेलवे वर्कशाप, समस्तीपुर का मैकेनिकल विभाग	Mechanical Department of Railway workshop Samastipur	1210
1376	अशोक पेपर मिल्स, लिमिटेड	Ashoka Paper Mills Ltd.	1210-1211

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1377	1966-67 में उड़ीसा में खानों का पट्टे पर दिया जाना	Lease of Mines in Orissa in 1966-67	1211
1378	तलचर औद्योगिक केन्द्र	Talcher Industrial Complex	1211-1212
1379	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train on N. E. F. Railway	1212
1380	कलकत्ता के निकट इस्पात का कारखाना	Steel Plant near Calcutta .. — ..	1212
1381	मिलिट्री स्पेशल रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Military Special	1212-1213
1382	दौराला से हस्तिनापुर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Daurala to Hastinapur	1213
1383	मेरठ सिटी जंक्शन पर भारी इंजन	Heavy Engines at Meerut City Junction ..	1213-1214
1384	पैसेंजर कारों का निर्माण	Manufacture of Passenger Cars	1214
1385	सेलम इस्पात संयंत्र	Salem Steel Plant	1214
1386	कुलियों के लाइसेंसों का उनके लड़कों के नाम किया जाना	Transfer of Porters' Licenses to their sons	1215
1387	कपास की वसूली	Procurement of cotton ...	1215-1216
1388	चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Czechoslovakia	1216-1217
1389	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को ठेके देना	Contracts to Chittaranjan Locomotive works	1217
1390	वाराणसी भटनी यात्री गाड़ी की दुर्घटना	Accident of Varanasi-Bhatni Passenger train	1217-1218
1391	भिलाई इस्पात कारखाने को उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment to Bhilai Steel Plant ..	1218
1392	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. रांची में ढलाई तथा गढ़ाई का कार्य	Casting and Forging work in HEC Ranchi	1218-1219
1393	भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची	Heavy Machine Tool Plant, Ranchi... ..	1219

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1394	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. रांची का चेयरमैन	Chairman of H. E. C. Ranchi	1219–1220
1395	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा प्रयोग में लाई गई भूमि	Land Utilised by Diesel Locomotive Works, Varanasi	1220
1396	पंजाब मेल से सेना के जवान का गिरना	Falling of a jawan from Punjab Mail	1220–1221
1397	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली मुआफ किया जाना	Waiver of recovery of liquidated damages by the Iron and Steel controller	1221
1398	फर्मों से राशि की वसूली	Recovery from Firms	1221–1222
1399	मोटरकारों का ले जाया जाना	Transportation of Motor Cars	1222
1400	मोटरगाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Vehicles ..	1222–1223
1401	दुर्गापुर में सेवा नियोजन	Employment in Durgapur ..	1223-1224
1402	ट्रैक्टरों तथा छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Small Cars ...	1224
1403	हिन्दुस्तान प्लान्टेशन (प्राईवेट) लिमिटेड	Hindustan Plantation (P) Ltd.	1224–1225
1404	फिएट कारों का नियतन	Allotment of Fiat Cars ..	1225
1405	बिहार में पटसन का कारखाना	Jute Factory in Bihar ..	1225-1226
1406	अधिक भाड़े वाला माल	High Rated Goods	1226
1407	रेलवे एवं सरकारी उपक्रमों में चार्जमैन तथा फोरमैन	Chargemen and Foremen on Railways vis a vis public undertakings	1227
1408	रेलवे में चार्जमैनों के लिए प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus to Chargemen on Railways	1227
1409	छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Small Tractors	1227–1228
1410	सरकारी उपक्रमों द्वारा कच्चे माल की खरीद	Purchase of Raw Material by Public Undertakings	1228–1229
1411	वायदा बाजार आयोग	Forward Markets Commission	122[illegible]

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

1412	प्रबन्ध अभिकरण	Managing Agencies	1229
1413	कागज तथा गत्ते का आयात	Import of paper and board	1230
1414	आयात तथा निर्यात	Imports and Exports	1230
1415	झाझा तथा गोमोह स्टेशनों पर जल की व्यवस्था	Water Supply at Jhajha and Gomoh Stations	1230-1231
1416	सीरामपुर कोयला खान का बन्द किया जाना	Closure of Serampore Colliery	1231
1417	मनुष्य के बालों का निर्यात	Export of Human Hair...	1232
1418	निर्यात शुल्क	Export duties	1232
1419	ढाली-राजहारा दांतेवाड़ा रेलवे परियोजना	Dhali-Rajhara Dhantewara Railway Project	1232
1420	साबूदाना तथा साबूदाने के आटे के आयातकों की संस्था	Sago and Sago Flour Importers Association	1233
	गजेन्द्रगडकर प्रतिवेदन के बारे में व्यवस्था का प्रश्न	Point of order re. Gajendragadkar Report	1233
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of Urgent Public Importance	1233
	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार का इन्कार	Government's refusal to raise dearness allowance of Central Government Employees	1233
	श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerji	1233
	श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	1234-1237
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1237-1238
	सभा का कार्य	Business of the House	1238-1241
	रेलवे आय-व्ययक (1967-68) सामान्य चर्चा	Railway Budget (1967-68) General Discussion	1241-1246
	श्री सी दास	Shri C. Dass	1241
	श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh	1242
	श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	1243
	श्री तामस्कर	Shri Tamaskar	1244
	श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	1244
	श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	1246
	श्री शिंकरे	Shri Shinkre	1245
	श्री वी. ना. शास्त्री	Shri B. N. Shastri	1245

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1246
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	1246
कपड़ा उद्योग में संकट के बारे में संकल्प—जारी	Resolution Re Crisis in Textile Industry Contd	1247-1255
श्री एस्थोस	Shri P. P. Esthose ..	1247
श्री स. कु. तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	1249
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	1250
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Vedavrata Barua	1250
श्री कन्डायन	Shri Kandayan	1251
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Gani Dar	1251
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1252
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	1252
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	1253
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1254
श्री श्री अ. डांगे	Shri S. A. Danga	1254
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	1255
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	1255
इस्पात से नियन्त्रण हटाने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Steel Decontrol	1257
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	1257

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 2 जून, 1967/ 12 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Friday, June 2, 1967/Jyaistha 12, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हानि

241. श्री बाबूराव पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि में 59.3 **करोड़** रुपये की हानि दिखाई है जबकि उसमें कुल 1028.5 करोड़ रुपये की पूंजी लगी **हुई है;**

(ख) विदेशियों द्वारा विशेषज्ञ जानकारी दिये जाने तथा भारतीयों द्वारा अच्छा प्रबन्ध **किये जाने के बावजूद** बराबर हानि होते रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करके, जो हमारे **सभी इस्पात** कारखानों की जांच करे, इस लगातार हो रही हानि के कारणों का पता लगाने **का है;**

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 59. 3 करोड़ रुपये का घाटा 1958-59 से लेकर जब कि प्रथम इकाई चालू की गई थी, आज तक का कंपनी का कुल घाटा है। संचालन के प्रथम वर्ष को छोड़कर, शेष सभी वर्षों में कम्पनी को सकल लाभ हुआ है। आरंभ से लेकर आज तक का वास्तविक घाटा इसलिए हुआ क्योंकि सकल लाभ में से कम्पनी ने मूल्य ह्रास और ब्याज के रूप में 254 करोड़ रुपये की राशि की पूर्ति की। मूल्य ह्रास और सूद की रकम योजना के स्त्रोतों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1964-65 और 1965-66 में कम्पनी ने शुद्ध लाभ भी कमाया जब इसके तीनों एक मिलियन टन स्तर के कारखानों के उत्पादन में काफी स्थिरता आ चुकी थी।

(ख) शुरू के सालों में घाटा प्रमुखतः इसलिए हुआ कि कारखानों का उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम था क्योंकि नये कारखानों में क्षमता का उपयोग उत्तरोत्तर ही बढ़ा। इसके साथ साथ मूल्य ह्रास और ब्याज के रूप में भारी ऊपरी खर्च भी था। सरकार ने इस्पात नियंत्रण प्रणाली के अधीन इस्पात की कीमतों को निश्चित कर दिया था। पिछले वित्त वर्ष में देश के अन्दर मांग की कमी के कारण प्रेषण में कमी हुई जिसके फलस्वरूप लाभ कम रहा।

(ग), (घ) और (ङ) : लाभ को बढ़ाने का प्रमुख उपाय यह होगा कि उत्पादन लागत में कमी की जाय। हाल ही में श्री हरिकृष्ण महताब की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने इस बात पर पूरी तरह विचार किया है। समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है और यथा समय इनका प्रभाव पड़ेगा। जहां तक किसी एक कारखाने में अत्याधिक घाटा होने का सवाल है विशेष जांच की गई है—उदाहरणार्थ पांडे समिति ने हाल ही में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का अध्ययन किया है। इनकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। सरकारी उपक्रम समिति ने भी पिछले दो वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सभी कारखानों के काम का पुनर्विलोकन किया है। कंपनी भी देश में बिक्री को बढ़ाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है जिससे मांग में होने वाली वर्तमान कमी के कारण लाभ में कमी को रोका जा सके। इसलिए इस समय और अधिक छानबीन करने की आवश्यकता नजर नहीं आती।

श्री बाबूराव पटेल : यदि गैर सरकारी क्षेत्र की टाटा स्टील कम्पनी लगातार वर्षों तक अच्छा खासा लाभांश दे सकती हैं तो 1028 करोड़ रुपये की पूंजी से स्थापित सरकारी क्षेत्र में स्थापित हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लगातार घाटा क्यों दिखा रही है ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह कहना ठीक नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सदा घाटा उठाया है। यद्यपि प्रारम्भ उसे कई कारणों से घाटा उठाना पड़ा था, परन्तु वर्ष 1963-64 से बाद में उसे शुद्ध लाभ हो रहा है।

श्री बाबूराव पटेल : भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमचारी ने एक बार इस्पात के बारे में बड़ी बड़ी आशाएं व्यक्त की थी। परन्तु आज दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगभग बन्द होने जा रहा है। उसके उत्पादन को बेका नहीं जा रहा है। संयंत्र 75 लाख रुपये की मजूरी का भुगतान करने में असमर्थ है। इसके बन्द हो जाने से लगभग 25000 परिवार प्रभावित होंगे, क्या सरकार का इस कारखाने को बन्द करने का विचार है ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह बात ठीक नहीं है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना बन्द होने जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की गलत धारणा का निवारण करना चाहता हूँ। टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी में 1176 रुपये प्रतिटन की लागत पूँजी लगी हुई है, जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में यह 2500 रुपये है। इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी में यह लागत पूँजी केवल 950 रुपये है। गैर सरकारी क्षेत्र में कम्पनियां उस समय स्थापित हुई थी जब कि मशीन, भूमि आदि का मूल्य बहुत कम था जब कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना के समय सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ चुका था। प्रारम्भ में इसे हानि हुई। वर्ष 1964-65 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1849.2 लाख रुपये का और 1965-66 में 166.5 लाख रुपये का लाभ हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त कम्पनी को प्रतिवर्ष हानि नहीं हुई है, बल्कि उसे कुल मिलाकर घाटा हुआ है। दुर्गापुर, भिलाई और रुरकेला स्थित इस्पात के कारखानों में टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की अपेक्षा संचालन लागत (वर्किंग कॉस्ट) कम है।

Shri Sidheshwar Prasad : I would like to know the basis at which the cost-expenditure has been worked out in Hindustan Steel Limited and why the full capacity of HSL is not being utilized by now.

Dr. Chenna Reddy : As I have already said that during the period when the steel plant is in the process of development and expansion, most of the capacity of the plant remains idle or unutilized. Along with it more interest and depreciation charges bring about losses.

श्री विरेन्द्रकुमार शाह : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादन की मांग घटती जा रही है। क्या मंत्री महोदय वर्ष 1966-67 तथा चालू वर्ष के बाजार के रुख के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे।

डा० चन्ना रेड्डी : यह सच है, क्योंकि 1965-66 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण या उसके परिणाम स्वरूप मार्किट में मन्दा हो जाने के कारण अथवा सामान्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। उदाहरणार्थ, भिलाई में रेल पटरियों की कुछ अनुमानित क्षमता पांच लाख टन थी जबकि रेलवे केवल 2.25 लाख टन के लिये क्रयादेश दे सकी थी। इसलिये उत्पादन में परिवर्तन करना और बिल्लैट का उत्पादन चालू करना, जिसमें लागत अपेक्षाकृत काफी कम थी, आवश्यक हो गया था।

श्री विरेन्द्र कुमार शाह : मैं 1966-67 और चालू वर्ष में बाजार के रुख के बारे में पूछा है।

डा० चन्ना रेड्डी : चालू वर्ष में बाजार के रुख में सुधार नहीं हुआ है। हाल ही में किये गये विनियन्त्रण के बाद हमें आशा है कि उन वस्तुओं के उत्पादन में सुधार होगा जिनकी कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई है और जिनकी उत्पादन लागत काफी ऊंची थी और हमें आशा है कि दो या तीन महीनों के पश्चात बाजार के रुख में सुधार होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को भी टाटा की भांति अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है?

डा० चन्ना रेड्डी : वास्तव में विशेष अन्तर नहीं है। 1964 में विनियन्त्रण के बावजूद बाज़ार में भाव लगभग नियन्त्रित हैं और कीमतों में समानता है ।

Shri Madhu Limaye : Just now the hon. Minister, in reply to a supplementary stated that since the Tata Factory was constructed before the war broke out, therefore their cost of production is very much less. In view of the fact that the raw material for the finished steel have to be imported from abroad in Japan, what are the reasons for comparatively lower cost of production in Japan ? Have any steps been taken to streamline the working of Public Sector Factories ?

Dr. Chenna Reddy : I can give the figures of other steel producing countries. The sale value on the capital invested is 3.5 as against 9 in most of the steel plants in different countries. This is one of the major factors. Because of its foreign exchange component and the need to enhance the capacity we have to spend more in the initial establishment as compared to Japan. Apart from that over-staffing and low standards of efficiency of labour also counts for our high prices. Because of the heavy capitalisation in our country, we have first of all to achieve our rated capacity. If our rated capacity falls below 95 percent, it entails a loss to us. Therefore, if we compare the internal domestic price between India and Japan, India has a cheaper price for domestic consumption.

Shri Manubhai Patel : How does the production and economic charaeter of the Tata Factory during the first ten years of its inception compare with Hindustan Steel ?

Dr. Chenna Reddy : It is correct that Tata had to undergo many difficulties so much so that in 1920 Government of India had to give tarrif support to them, they had to subsidise per ton of steel production so that they might servive. After passing through the stresses and strains for many years, Tata has reached its present condition.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस्पात कारखानों द्वारा अधिक लाभ अर्जित न किये जाने का एक कारण यह है कि उनकी उत्पादन लागत अधिक है। श्रीमन् यदि मुझे सही तौर पर याद है, तो जब आप कार्यभारी मंत्री थे तब इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और मैं समझता हूँ कि उस समिति ने कुछ समय पहले अपना प्रतिवेदन दिया था। क्या मैं जान सकता हूं कि समिति की कौन कौन सी सिफारिशे स्वीकार कर ली गई हैं और क्या इस्पात कारखानों में उत्पादन लागत को घटाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

Dr. Chenna Reddy : Regarding the bringing down of the cost of production Government is considering reports of two Committees. One report is of Mehtab Committee, after examining the full details of which some steps have been taken. I will not be able to give its details presently. So far as the Pandey Committee report which is with regard to Durgapur, is concerned, is going to be referred in the next and it is under consideration of the Government.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सिफारिशों के आधार पर उन्होंने उत्पादन लागत को कम करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : हमने महताब समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है। व्यौरे की जांच की जा रही है और कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। चूंकि ये सब बातें इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती, इसलिये मैं सारा व्यौरा देने की स्थिति में नहीं हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I rise on a point of order. In the (c), (d) and (e) parts of the statement the hon. Minister has stated, "The major factor which would increase profits is a reduction in the cost of production. This has been investigated in detail very recently by a Committee headed by Shri Harekrushna Mehtab. The recommendations of the Committee are being implemented and should have their impact in due course". When the hon. Minister has given the details, he should also possess the information as to what recommendations have to be implemented and what not since this has a direct relevance with his statement as also with the question.

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : कुछ समय पहले हिन्दू में एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री का वक्तव्य छपा था कि इन इस्पात कारखानों के कुछ प्रबन्धक तैयार किये गये माल को निम्नस्तर का दिखा कर गैर सरकारी लोगों को बेचते हैं। क्या इस मामले की जांच की गई है, यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चन्ना रेड्डी : दुर्भाग्य से मैंने उसे देखा है।

श्री कोठारी : ब्याज अधिक होने का एक कारण यह है कि ब्लाक बहुत बड़ा है, विशेष रूप से लागत अधिक है और जब ब्लाक बनाया गया था तो कुछ अपव्यय भी हुआ था। परन्तु, उसके अतिरिक्त इस समय माल भी कुछ अधिक मात्रा में जमा हो गया है। क्या आप कृपया इस पहलू पर विचार करेंगे क्योंकि सामान्य धारणा यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और विशेष रूप से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में माल काफी बड़ी मात्रा में जमा हो गया है। तैयार उत्पादों का भंडार भी काफी बड़ा हो गया है क्योंकि बाजार की मांग अधिक नहीं है। जो माल भारी मात्रा में जमा हो गया है उससे मेरा अर्थ है फालतू पुर्जे, कच्चा माल और तैयार वस्तुएं।

श्री चन्ना रेड्डी : जहां तक तैयार उत्पादों का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने पहले बताया पिछले दो वर्षों में ही, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में मंदी आने और रेलवे के कार्य-क्रमों में गिरावट आने से स्टाक कुछ बढ़ गया है। परन्तु पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि रेल की लाइनें काफी मात्रा में निर्यात की गई हैं और विभिन्न देशों को हम 2 करोड़ रु० के मूल्य की रेलवे लाइनें प्रति मास निर्यात करते रहे हैं। जहां तक फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है यह कुछ हद तक सही है, परन्तु उनमें से कुछ पुर्जों के जमा हो जाने को रोका नहीं जा सकता है। हम इनको भी दोष रहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Railway Medical Officers' Association

***242. Shri Mohan Swarup:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shrimati Jyotsna Chanda:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Medical Officers' Association has recently passed a resolution demanding better salaries and better prospects for promotion; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Shri Sidheshwar Prasad: May I know whether there is any difference in the pay scales and service conditions of the doctors in the service of Railway and of those serving in other Ministries of the Union Government, if so, what?

श्री परिमल घोष : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के वेतन क्रमों, प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में सुधार किये जाने के बाद रेलवे ने भी रेलवे के डाक्टरों के लिए इन तीनों चीजों को लगभग समान बनाने के लिये कुछ परिवर्तन किये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों और रेलवे चिकित्सा सेवा के डाक्टरों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में डाक्टरों की कुछ श्रेणियों में कुछ अन्तर रहा है। पहले तो डीविजनल मैडिकल अफसरों की पदोन्नति के बारे में अन्तर है। वर्तमान रेलवे पद्धति यह है कि केवल एक तिहाई पद पदोन्नतियों द्वारा भरे जाते हैं और शेष सीधी भर्ती द्वारा। फिर प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में भी दोनों सेवाओं में कुछ अन्तर है। फिर, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को श्रेणी दो के डाक्टरों में रखा गया है जबकि, रेलवे मैडिकल सेवा में उनको श्रेणी तीन में रखा जाता है, यद्यपि वेतन क्रम और अन्य बातें लगभग वे ही हैं, जो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में हैं।

Shri Sidheshwar Prasad: Are the demands of the Railway doctors being examined by the ministry itself or a committee has been appointed for this purpose and by what time a decision will be taken in this regard?

श्री परिमल घोष : रेलवे मैडिकल अफसरों ने चार मांगें रखी हैं और ये चारों की चारों अब सरकार के विचाराधीन हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे के डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने दिया जाता है और यदि नहीं तो, क्या प्रतिक्रात्मक भत्ता दिया जाता है?

श्री परिमल घोष : प्रतिक्रात्मक भत्ता भी दिया जाता है। परन्तु उनको सीमित निजी प्रैक्टिस भी करने दिया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachwai; In view of the fact that in some of the railway zones there is overstaffing of medical officers while in others they are in inadequate numbers, may I know what steps are being taken to meet the shortage in the latter case. Do Government propose to introduce medical facilities for the passengers, especially in the long journey trains?

श्री परिमल घोष : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, यदि इस प्रकार की कोई मांग आई, तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

Shri Ramavtar Shastri; What is the maximum time upto which a medical officer can stay at one particular place? What are the reasons for their being stationed for 6 or 7 years despite the prescribed period limit?

श्री परिमल घोष : जैसा कि मैंने पहले बताया रेलवे के डाक्टरों और स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की सेवा की शर्तें बिलकुल एक ही हैं।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

\+

243. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कपड़ा मिल कितने हैं जो या तो चल नहीं रहे थे अथवा बन्द कर दिये गये थे और तदुपरांत उनका नियन्त्रण पिछले दो वर्षों में सरकार ने अपने हाथ में लिया है;

(ख) क्या उन कारखानों से बाद में मुनाफा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(घ) क्या वे कारखाने अब उनके मालिकों को दे दिये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : 1965-66 तथा 1966-67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आठ मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया था। नियन्त्रण में लिये गये आठ मिलों में से दो मिलें वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द पड़ी हैं। किन्तु सम्बन्धित राज्य सरकारें उनको फिर से चलाने के लिये कार्यवाही कर रही हैं। बाकी छः में से दो हाल ही में चालू हो गई हैं और उनके लाभ तथा हानि लेखे अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी चार मिलों के लेखा-परिक्षित सन्तुलन-पत्र भी अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्राधिकृत नियन्त्रकों से प्राप्त नियत-कालिक प्रतिवेदनों से यह पता चलता है कि चार मिलों में से एक मिल अर्थात इंडिया युनाइटेड मिल्स में निरन्तर घाटा हो रहा है यद्यपि घाटे की राशि प्रत्येक मास अलग अलग है। अन्य तीन मिलों अर्थात मयूर मिल्स लि०, कानपुर, स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर तथा हीरा मिल्स लि० उज्जैन में किसी महीने घाटा तथा किसी महीने लाभ हो रहा है।

Shri B.S.Sharma: What is total number of mills closed state-wise and whether they were producting coarse cloth or fine cloth?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): At present 27 mills are closed. I have in my possession the information about their state-wise location and Mr. Speaker, I will send the same to you.

Shri George Fernandes : Amongst the mills mentioned by the minister is a Bombay mill known as the Indian United Mills. In view of the fact that these mills are running into loss, will the Government make arrangements to use the cloth manufactured at these mills for its own use, secondly to use it in the army and thirdly to export its cloth to countries where this may have a demand and to forgo excise duty ? I have this question before me that demand for the removal of cloth of this mill is made by the mills of the private sector and many people in Bombay have got proof about it.

Shri Dinesh Singh : It is said that certain people create difficulty in the sale of cloth of this mill. The hon. member met me and I want to know from him about the condition there and what we can do about it. Whatever we come to know we will fully inquire into that. The removal of excise duty is no solution of this problem. About the India United Mills going into loss, a committee also inquired into its affairs and the recommendations of that committee go deep into the affairs and they are being inquired into. We will have to decide how to rectity these mills is a complicated question.

Shri S. R. Damani : Will the Government do something to restart the Spinning Mills of Sholapur in which 10,000 persons are working and which is closed for the last four years and which has affected the population of the city ?

Shri Dinesh Singh : This has been mentioned in the House several times. It is not sufficient to re-start the mills but to see to it that they go on working. It is also to be seen as to what responsibility devolves on the Government. People open mills and they have to stop them due to mismanagement or due to misuse of money or due to some other reason. Some of the mills are very old. When these mills are closed, people ask the Government to run them. Had it been so easy the mill owners themselves would have then continued. It would be proper for the Government to run them if the same would have been closed due to mismanagement or where the people's money is involved. The important question is that the mills go on working and the people employed in them may not be put to difficulty. I have stated that we are bringing a Bill according to which the mills which we take over should not be handed over back but be continued to be run by us. This work may be done by establishing a corporation in the public sector.

Shri S. C. Jha : Is it not a fact that Lokanathan Committee made a study of the condition of the cotton mills of Coimbatore and found some mills sick ? Is Government prepared to take over those mills or not ?

Shri Dinesh Singh : I have discussed it in detail just now.

श्री शिवनंजप्पा : मेसूर में कुछ मिलों को लेने की बात हो रही है। क्या मैं उनके नाम जान सकता हूँ ?

श्री दिनेश सिंह : जब हम उन्हें लेंगे तो सदस्य महोदय को सूचना दे देंगे।

श्री श्री० अ० डांगे : बम्बई स्थित इंडियन यूनाईटेड मिल्स जिसमें 20,000 कर्मचारी काम करते हैं के बारे में क्या मंत्री महोदय, बतायेंगे कि इन मिलों के कार्य करने के बारे में दो जांच प्रतिवेदन थे जिनमें एक ने 96 लाख रु० का धोखा पता लगा है। क्या सरकार ने उन संचालकों से तथा अन्यों से जिन्होंने यह धन हजम किया है, वह धन वसूल करने के बारे

में प्रयत्न किया और यदि पहले यह प्रयत्न किया गया तो यह धन वसूल करने के लिए अब प्रयत्न किया जायेगा।

श्री दिनेश सिंह : मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि क्योंकि अब उन्होंने इसके बारे में बताया है मैं इसकी पड़ताल करूंगा और वह धन वसूल करने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Tulsidas Jadhav : The minister just now replied about the old mill. At present the mill contains property worth Rs. 2 to 2½ crores which is at the disposal of High Court. The Government is ready to take over that, workers are also ready and Government has got money also for that. Now it is the duty of the Central Government to run those mills with the help of state governments. Six thousand workers are employed there and the mill is lying closed for the last 3 years then Why does not the Government think about it ?

Shri Dinesh Singh : I will advise the hon. member to wait for three months more when they have already waited for three years and let this corporation be formed.

श्री पीलु मोडी : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे कपड़े के मिलों को अपने हाथ में लेने वाले हैं तथा वह इसे अस्थाई रूप में लेने में सन्तुष्ट न होंगे बल्कि उसे स्थाई रूप से लेना चाहते हैं क्योंकि यह मिल ठीक रूप से नहीं चलाये जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय सार्वजनिक क्षेत्र में जो बहुत से मिल ठीक रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें निजी क्षेत्र को देने पर भी विचार करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मं० रं० कृष्णा : शोलापुर स्थित नरसिंहीरजी मिल्स को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था तथा उसका प्रबन्ध एक विशेष समिति को सौंप दिया था। मुझे पता चला है कि नया व्यवस्थापन भी घाटे में जा रहा है। मिल की वर्तमान स्थिति क्या है ?

Shri S. M. Joshi : Will the hon. minister tell the loss per month which the India Mills is incurred ?

Shri Dinesh Singh : I do not have monthly statistics with me at the moment.

श्री कन्डप्पन : क्या यह सच है कि कपड़े के उत्पादन व्यय के बढ़ने से आन्तरिक मंडी में कपड़े के उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि हां तो सरकार, उत्पादन व्यय को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो एक बड़े विस्तार का प्रश्न हैं जिसमें आन्तरिक वेतन तथा व्यय के ढांचे का भी प्रश्न आता है। यह प्रश्न काल के थोड़े से समय में मै समझा भी नहीं सकता।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के कुछ उन मिलों की ओर गया है जो 12000 तकलियों के हिसाब से आरंभ किये थे वह लाभ पर नहीं चल रहे हैं तथा

उन्होंने प्रस्ताव किया है कि यदि उनमें तीसरी पारी चला दी तो वह लाभ पर चल सकेंगे और यदि ऐसा नहीं किया गया तो मिल बन्द होने के करीब होंगे। यदि हां, तो क्या सरकार तीसरी पारी पर इन मिलों को चला कर लाभ में चलने की अनुमति देगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमें मिलों की पारियों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कठिनाई कपास की कमी की है। हमारे पास मिलों को तीसरी पारी पर चलाने के लिए कपास नहीं है। इसी कारण हमने नई तकली लगाने पर भी कुछ नियन्त्रण, लगा दिया है। जैसे ही कपास की स्थिति में सुधार होता है हम उन्हें और अधिक पारियों पर चलने की अनुमति दे देंगे।

श्री० स० मो० बनर्जी : मुझे इस वक्तव्य से प्रसन्नता है कि कुछ मिलों को ले लेने का सरकार ने निश्चय किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके मन में कानून द्वारा एक कपड़ा निगम बनाने का है और यदि हां तो क्या वह विधेयक इसी सत्र में आयेगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां।

श्री समर गुहे : क्या सरकार बता सकती है कि आसनसोल स्थित ढाकेसबरी कपड़ा मिल को क्यों बन्द कर दिया है। सरकार ने इसे इस शर्त पर कुछ सहायता दी थी कि वह पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को काम पर लगायेंगे। वह मिल बंद पड़ा है। क्या सरकार इस मिल के चलाने का वचन दे सकती है ताकि वह उसमें शरणार्थियों को काम पर लगाया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्रीमति लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि कपड़े के ऊंचे मूल्य तथा लोगों के खरीदने की कम शक्ति कपड़ा उद्योग में रोक के लिए जिम्मेदार है और यदि हां तो क्यों सरकार नियन्त्रित मूल्यों पर कपड़ा वितरण करने पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : बहु संख्यक लोगों के उपभोग के कपड़े पर पहले ही नियन्त्रण है और हमें उस दिशा में किसी कठिनाई का पता नहीं चला है।

Shri Jagannath Rao Joshi : The textile mill which was taken over by the Gevernment in February 1966 under the Bhopal Relief Act was closed in July 1966 itself for an indefinite period. I want to know why this was closed as 2000 workers have been rendered unemployed and they have not got even the Provident Fund ?

Shri Dinesh Singh : It is a fact that the New Bhopal Textile Mill was taken over and work begun on that but it could not be run and had to be closed. I understand the state government is looking into it and will soon try to run it.

Shri Hukam Chand Kachwai : The mill owner of the mill has given free bungalow to the Chief Minister to live in. What will the Government do about it as the Chief Minister is mainly responsible for its closure ?

Shri Dinesh Singh : The hon. member is unnecessarily angry with me.

Shri Kanwar Lal Gupta : The question which he has not replied is that the Provident Fund has not been given.

Shri Dinesh Singh : The hon. member has levelled charges against the Chief Minister who is not here to reply to those charges and as such the same should be made.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यदि इन्हें दोहराया गया तो यह ठीक नहीं होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The provident Fund which was to be given to 2000 workers has not been given will government do nothing about it ?

Shri Dinesh Singh : I will enquire into it.

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : राजरत्नम मिल्स, पेटलाद जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है गत 1½ वर्ष से बन्द है । श्री ओझा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी तथा उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार को क्या उत्तर दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य व्यक्तिगत मिलों के बारे में मुझ से प्रश्न कर रहे हैं । यदि वे मुझे इनके कारण बता दें तो उन्हें प्रसन्नता से तथ्यों को बता सकता हूं । परन्तु व्यक्तिगत मिलों के बारे में दिये गये प्रतिवेदन तथा अन्य आंकड़े एकत्रित करना मेरे लिए बहुत कठिन है ।

श्री राममूर्ति : पांडीचिरी केन्द्र के अधीन है । भारती कपड़ा मिल्स, पांडीचिरी के सम्बन्ध में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी तथा उस समिति ने 10 मास पहले अपनी सिफारिश दे दी है कि केन्द्रीय सरकार उसे अपने अधिकार में ले ले । उस संसदीय समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि सदस्य महोदय को पूरा पता नहीं है । मिल को जून 1966 में लिया गया था तथा फरवरी 1967 से यह कार्य कर रहा है ।

Shri D. N. Tiwary : The hon. minister had stated that after the formation of the corporation the mills which are running into losses or whose management is not good' will be taken over permanently. Will Government give compensation to these mills after taking them over because after taking over arrangements will be made that they do not go into loss and their management should also be improved.

Shri Dinesh Singh : I have not stated that we will take over all the mills. We will take over only what is reasonable for us. The hon. members here will decide about the compensation or the liquidation price to be or the way in which that would be done.

Shri Madhu Limaye : The hon. minster stated that he would bring a bill for formation of a Textile Corporation. I want to know whether while so doing he would see that it does not become a white elephant due to high administrative expenditure. Secondly the Textile Corporation will have no meaning till arrangements for the distribution and sale of things produced are made. I want to know whether arrangements about these would be made in the Bill ?

Shri Dinesh Singh : We have not yet decided about distribution nor it is necessary to do so. But we will give thought to the first part of the question.

ऊन के धागे का मूल्य

***244. श्री अब्दुलगनी डार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन का धागा भारतीय बाजारों में नियन्त्रण मूल्य से दुगनी दरों पर बिक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फर्मों अथवा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो धागा चोर बाजार में बेच कर अधिभार, आयकर और बिक्री कर की बचत कर रहे हैं; और

(ग) गत छ: महीनों में इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितनों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वास्तविक प्रयोग-कर्ताओं को दिये गये लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित कच्ची ऊन से तैयार किये गये वर्सटिड धागे पर मूल्य नियन्त्रण लागू है। किन्तु इस धागे पर वितरण नियन्त्रण भी लागू है और यह धागा विकेन्द्रित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को परमिटों पर देने के लिये होता है और खुले बाजार में प्राप्य नहीं होता। भारतीय ऊनी धागे पर भी मूल्य नियन्त्रण लागू है और वह ऊंचे दामों पर नहीं बिक रहा। निर्यात संवर्द्धन लाइसेंसों के अन्तर्गत अथवा राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित ऊन से तैयार किये गये वर्सटिड धागे पर मूल्य नियन्त्रण अथवा वितरण नियन्त्रण लागू नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Abdul Ghani Dar : The Minister says that the imported wool is being sold at fixed rates. But I would like to point out that such wool is being sold at double the price, which has been fixed by the Govt. It is not true ?

Shri Shafi Qureshi : I stated that distribution and the rates of the imported wool of Marino type is controlled by the Govt., while there is no control on the distribution and prices of the wool which was imported earlier under Export Promotion Scheme or National Defence Remittance Scheme. So there may be a little difference in prices of controlled and uncontrolled varieties of wool. As regards the controlled varieties of wool, they are being sold at fixed prices.

Shri Abdul Ghani Dar : The Textile Commissioner has done a discrimination in respect of giving permission of making wool yarns to various Woollen Spinning Mills. Some have been allowed to make 60% of wool yarn required by them and the others have been allowed to make wool yarn to meet their total requirement. May I know whether the Govt. is aware of this discrimination ?

Shri Shafi Qureshi : Probably there are few mills which have been making wool yarn 5% or 10% more than others. We are aware it and the existing discrimination will be eliminated soon.

श्री रा० कृ० बिड़ला : अवमूल्यन का आयातित ऊन पर भी पड़ा है परन्तु सरकार ने उन तीनों प्रकार के ऊनी धागों के, जो आयातित ऊन से तैयार किये जाते हैं, दाम अवमूल्यन के बाद पुनः स्थिर क्यों नहीं किये हैं ?

श्री शफी कुरेशी : माननीय सदस्य को पता है कि मूल्य पहले से ही निर्धारित किये हुए हैं। जहाँ तक मूल्य, वितरण, उत्पादन और नियंत्रण का प्रश्न है इनसे सम्बन्धित तथा शाह समिति द्वारा दिये गये एक प्रतिवेदन का सरकार अध्ययन कर रही है। इसके बाद कुछ निर्णय किया जायेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन

***245. श्री मधु लिमये :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में हुई कमी के बारे में श्री जी० पांडे की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट और सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 505/67]

Shri Madhu Limaye : We came to know through the statement that the management of Durgapur Steel Plant did not fulfil their responsibilities properly in respect of maintenance, control on quality of products, checking staff indiscipline and operation etc. May I know whether the guilty officers have been penalized for it; if not, whether Govt. intends to do so in future ?

Dr. Chenna Reddy : The Report of the Pandey Committee was received in the last week of April and the comments of Hindustan Steel Limited thereon have been received very recently. The whole matter is being considered carefully.

Shri Madhu Limaye ; But it has been done so even after "ample warnings". So the action might have been taken earlier without waiting for this Report.

Dr. Chenna Reddy : It is one of the findings of Pandey Committee Report that it happens so after "ample warnings". That is why we have invited the comments in this respect from Hindustan Steel Limited. We will take into account of the aspect brought into light by hon. Minister.

Shri Madhu Limaye : The Report further says that there have been a large number

of thefts in the plant. May I know whether the Govt. came to know of these thefts after the receipt of Pandey Committee Report and whether the thieves have been penalized and whether the Govt. have taken the necessary steps to check such kind of thefts ?

Dr. Chenna Reddy : There are some cases of thefts. I do not know the circumstances, in which the thefts were committed. A Report was received by the Govt. that the condition of Durgapur Steel Plant is very bad. Thereafter, the Cabinet passed a resolution, in consultation with the Hindustan Steel Limited, for appointing this Committee.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या दुर्गापुर, इस्पात कारखाने में उच्च प्रबन्धक (टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन) है और क्या वहाँ उत्पादन लागत कम करने हेतु कोई स्थायी समिति को नियुक्त कर दी गयी है ?

डा० चन्ना रेड्डी : समिति की सिफारिशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। तथा स्थायी समिति को नियुक्त करने के सम्बन्ध में भी निर्णय बाद में किया जायेगा।

Shri George Fernandes - From the Report it appears that there is no management at all in Durgapur Steel Plant. If it is there, it is totally mismanagement. It is due to the fact that the plant is controlled by a General Manager of I. A. S. or I. C. S. cadre. May I know whether the Govt. is preparing a plan for replacing these I. A. S. or I. C. S. Officers by those technical experts ?

Dr. Chenna Reddy : Though it is difficult to express the views about such a plan, yet the Industrial Management Pool constituted by the Govt. is a step in this direction.

श्री सूपकार : रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कार्यकुशलता में कमी आ जाने के कारण अत्यधिक घाटा हो रहा है। सरकार ने इस कमी को दूर करने तथा श्रमिकों सम्बन्धी झगड़े समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि उक्त कारखाने का प्रबन्ध प्रभाव पूर्ण नहीं है और उत्पादन घटकर 64% तक आ गया है। इसी कारण से पांडे समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति की सिफारिशों और प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने बताया है कि घाटे का कारण दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। इन सभी इस्पात कारखानों का नियंत्रण हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार प्रत्येक इस्पात कारखाने को स्वायतशासी निगम में बदलने का विचार है जिससे उनके प्रशासन में सुधार आ सके।

डा० चन्ना रेड्डी : इस सुझाव में कुछ जान प्रतीत होती है। जहाँ तक इस कारखाने का मामला है, इसके प्रबन्धकों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी हुई थी परन्तु फिर भी काम ठीक नहीं हुआ और इसी वजह से इस समिति की स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

+

6. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास : श्री चक्रपाणि :
श्री वि० कु० मोदक : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्य खनन कार्यकारी अधिकारी श्री नारगूंदकर ने इस निगम के लिये काम करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में कुछ खनन इंजीनियर तथा कार्यकारी अधिकारी (ऐग्जीक्यूटिव) उन से कलकत्ता में मिले थे और उन्होंने त्यागपत्र देने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय । श्री नारगूंदकर हाल में बीमारी की छुट्टी पर हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, महोदय ।

(घ) नहीं, महोदय ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा पता चला है कि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के दूर-मुद्रक के माध्यम से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्य खनन कार्यकारी अधिकारी, श्री नारगूंदकर के नाम एक संदेश भेजा था जिससे चिढ़कर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है । क्या यह सच है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उस दूर-मुद्रक संदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच नहीं है कि श्री नारगूंदकर ने संयुक्त सचिव द्वारा भेजे गये दूर-मुद्रक-संदेश से उत्पन्न मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया है। दूसरे, मंत्रालय से कोई ऐसा दूर-मुद्रक-संदेश श्री नारगूंदकर को नहीं भेजा गया है जिससे वह नाराज हो गये हों ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की 6 करोड रुपये की राशि ऐसी है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

श्री प्र० च० सेठी : इस पूरक प्रश्न का सम्बन्ध मूल प्रश्न से बिल्कुल भी नहीं है । फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि कोयला-खानों की ओर इस निगम का बहुत सा धन बकाया है ।

श्री भगवान दास : अखबारों में यह खबर छपी थी कि श्री नारगूंदकर इस पक्ष में थे कि श्रमिक संघ के सभी झगड़ों को किसी न किसी प्रकार सुलझा दिया जाये परन्तु वह इस सम्बन्ध में मंत्रालय को राजी न कर सके ।

यह भी कहा गया है कि खान तथा धातु मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा उनको एक अपराधात्मक टेलीप्रिन्टर संदेश भेजा गया था। क्या यह खबर सच है; यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में पहले से बिगड़े हुए औद्योगिक संबंध और अधिक नहीं बिगड़ गये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तक स्वायत्त शासी संगठन है और इसलिये इस विशिष्ट संगठन द्वारा उठाई गई मांगों और विवादों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये प्रबन्धक निदेशक को पूरी शक्ति प्राप्त थी। यह कहना सही नहीं है कि इसके कारण सम्बन्ध और खराब होने की कोई संभावना है क्योंकि बोर्ड ने पहले ही, इसके सामने रखी गई विशिष्ट मांगों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे रखा है।

श्री गणेश घोष : क्या यह सच है कि रखे गये लक्ष्य और उत्पादित मात्रा में अन्तर के कारण श्री नारगूंदकर और सरकार के बीच कुछ मतभेद रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी, नहीं। वास्तव में यह एन० सी० ओ० ई० ए० के बारे में है। लक्षित उत्पादन या बिक्री के बारे में कोई मत भेद नहीं है।

श्री चक्रपाणी : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कुछ क्षमता 1.5 करोड़ टन है और इस निगम ने केवल 10 लाख टन ही पैदा किया है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री नारगूंदकर ने, जिस तरीके से इस निगम का प्रबन्ध चलाया जा रहा था उसको अच्छा नहीं बताया ? ऐसी स्थिति से बचने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये थे और क्या अधिकार और मंत्रालय के बीच झगड़े का यह भी एक कारण था ?

श्री प्र० चं० सेठी : निश्चय ही तृतीय योजना के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उत्पादन लक्ष्य 1.7 करोड़ टन रखा गया था, परन्तु मांग की कमी के कारण गैर कोकिंग कोल का उत्पादन हमें कम करना पड़ा था। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है कि नारगूंदकर इससे असंतुष्ट थे, क्योंकि यह प्रबन्धक निदेशक थे और उन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। यह आश्चर्य की बात है कि इन पांच महीनों के दौरान श्री नरगूंदकर वहां पर मुश्किल से 31 दिन के लिये उपस्थित थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपने पहले उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि श्री नारगूंदकर बीमारी की छुट्टी पर थे। बाद में उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह माना कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। मैं नहीं जानता कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं, परन्तु यह एक तकनीकी मामला है। क्या सरकार इसको आश्चर्य जनक नहीं समझती कि श्री नारगूंदकर, जिनको इस देश का चोरी का खान इंजीनियर समझा जाता है, प्रबन्धक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के पांच महीने के भीतर ही त्यागपत्र देने का फ़ैसला कर लें क्या हम यह समझें कि ऐसा साधारण रूप में ही हुआ है और मंत्रालय के अधिकारियों या अन्य किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : श्री नारगूंदकर निःसन्देह ही एक बहुत अच्छे तकनीकी अधिकारी हैं। उपलब्धों या लक्ष्यों या इस प्रकार की अन्य किसी चीज के सम्बन्ध में उनके और मंत्रालय के बीच में किसी मतभेद का प्रश्न नहीं है। अन्य कारण होंगे जिनका उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है और वहां पर उनके केवल कुछ ही दिन ठहरने से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पर वह पहले काम कर रहे थे उस स्थान के साथ उनका सम्बन्ध ही उसका कारण होगा और कोई, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है या वह बीमारी की छुट्टी पर हैं ?

डा. चन्ना रेड्डी : उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों पर छुट्टी के लिये प्रार्थपत्र दिया था। अब हमने उनको एक महीने के लिये छुट्टी मंजूर की है। जहां तक उनके त्यागपत्र का सम्बन्ध है, इसका अनुमोदन नहीं किया गया है।

श्री प्र० के० घोष : क्या यह सच है कि कर्मचारियों की पुरानी शिकायतों के प्रति श्री नारगूंदकर का असंतोष जनक रवैया मंत्रालय के हस्तक्षेप के लिये जिम्मेदार था ? क्या यह सच है कि बोनस की अदायगी की जटिल समस्या को मंत्रालय के हस्तक्षेप से हल कर लिया गया था और यह कि सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव ने नारगूंदकर को आदेश दिया था कि वह अन्य समस्याओं को 8 मई को कर्मचारियों की संघ के साथ बातचीत करके हल करें और चूंकि श्री नारगूंदकर कर्मचारियों से बातचीत नहीं करना चाहते थे, इसलिये वह छुट्टी पर चले गये ?

श्री चन्ना रेड्डी : मुख्यालय के लगभग 100 कर्मचारियों की संस्था ने कुछ मांगें रखी थीं और वे मांगें स्थानीय प्रबन्ध के विचाराधीन थीं। यह सही है, कि जैसा कि अभी बताया, महा प्रबन्धक या प्रबन्धक निदेशक के काफी समय तक वहां पर न रहने से भी शायद इस में विलम्ब हुआ हो। परन्तु मंत्रालय ने केवल तब ही हस्तक्षेप किया जब घेरे डाले गये और तालाबन्दी की गई। तब खान विभाग का सचिव मुख्य सचिव से परामर्श करके व्यक्तिगत रूप से पटना गया और पुलिस के महानिदेशक ने सारी स्थिति का जायजा लिया और मांगों के ब्योरे की जांच की और श्री नारगूंदकर को बातचीत जारी रखने का काम सौंपा गया था।

श्री कार्तिक ओरांओं : क्या प्रबन्ध और श्रमिकों में सम्बन्ध इतने खराब हो गये कि श्री नारगूंदकर ने महसूस किया कि उनके लिये वहां पर अधिक ठहरना ठीक न होगा, और क्या सरकार उत्पादन की कीमत पर श्रमिकों की मांग की अवहेलना कर सकती है ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह कहना सही नहीं होगा कि श्रमिकों के रवये के कारण प्रबन्धक निदेशक ने उस स्थान को छोड़ा। वास्तव में, ब्यौरों की जांच की गई थी और उनमें सूझबूझ का आधार था। ब्यौरे अब भी विचाराधीन हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : जब माननीय मंत्री कर्मिक संघों के प्रतिनिधियों से मिले थे तो उनके साथ बातचीत के दौरान या उनके ज्ञापनपत्र में क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि केवल एक या दो दिन पूर्व, 4 मई को, कर्मिक संघों के प्रतिनिधियों और मजदूरों को, जो अपने उचित कष्ट निवारण के लिये लड़ रहे थे, सबक सिखाने के लिये कुछ

कुख्यात गुंडों को लाया गया था और इस ओर कि उन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अतिथि गृह में ठहराने पर श्री नरगूंदकर ने आपत्ति उठाई थी जिसके बाद उन्हें त्यागपत्र देने पर बाध्य किया गया था ? संयुक्त सचिव ने एक पत्र लिखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सचाई क्या है।

श्री प्र० चं० सेठी : मामला स्थानीय पुलिस के पास पहुंच चुका है और इसकी जांच कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है अथवा नहीं कि उन्हें बिहार की पुलिस द्वारा कोयला निगम के अतिथि गृह से गिरफ्तार किया गया था ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह हमें पता नहीं है कि दो व्यक्तियों का चालान किया गया है। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती और चालान अदालत के सामने नहीं रखे जाते, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : माननीय मंत्रीने कहा कि श्री नारगूंदकर का अपने पूर्व स्थान से सम्बन्ध है। क्या अब भी श्री नरगूंदकर इन दोनों पदों पर बने हुए हैं और वह कब तक इन पदों पर रहेंगे ?

डा० चन्ना रेड्डी : उन्होंने यहां पर अपना त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने सिग्नेरी कोयला खान को भी अपना त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से सहमत हो गई है कि यह केवल 15 मई तक होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूंजीगत माल का आयात

*** 246. श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे पूंजीगत माल, पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये जाते हैं जो या तो देश में उपलब्ध होते हैं या जिनके उत्पादन की औद्योगिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) इस प्रकार के आयात के कारण प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि जो उपकरण तथा कच्चा माल देश में उपलब्ध है अथवा देश में तैयार किया जा सकता है उसका आयात न किया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयात की अनुमति देने से पहले देश में किसी वस्तु की मांग, स्वदेशी उत्पादन तथा अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार किया जाता है।

चाय उद्योग

* 247. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की समस्याओं पर विचार करने तथा उसका उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर

* 248. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकार इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के केन्द्र के प्रस्ताव से सहमत हो गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : भारत सरकार कुछ बन्द मिलों या बन्द होने वाली मिलों को अपने हाथ में लेने की शक्ति प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही जो विधेयक पुर : स्थापित करना चाहती है, उसके पारित होने तक, उसका विचार किसी सूती मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का नहीं है।

यदि राज्य सरकार मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहे तो भारत सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और राज्य सरकार को इस बात से अवगत करा दिया गया है।

मिलों को कपास का वितरण

*** 250. श्री काशी नाथ पांडे :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री न० प्र० यादव : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि मिलों को कपास के ठीक तरह से वितरण के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण बन्द होने वाले मिलों से श्रमिकों को आर्थिक दृष्टि से हानि उठानी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि सभी मिलों को कपास का युक्तियुक्त आधार पर वितरण हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) मिलों को कपास के वितरण का विनियमन इस प्रकार किया जाता है कि कपास के लाने ले जाने पर और गत वर्ष की खपत के आधार पर स्वदेशी कपास के स्टाक पर नियंत्रण रखा जाता है। यह इसलिये किया जा रहा है ताकि सभी मिलों को कपास के उपलब्ध सम्भरण का सम्यक वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सूती कपड़ा मिल बंद नहीं हो सकती। इसके अलावा जहां कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव होता है वहां वस्त्र आयुक्त यथा सम्भव कपास का अधिग्रहण करके सहायता करने का प्रयत्न करता है।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य-युगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग

*** 251. श्री एस० आर० दामानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग शुरू करने के उद्देश्य से एक प्रशुल्क अधिमान अध्ययन दल स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या ऐसे अध्ययन दल की कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां तो क्या इस अध्ययन दल द्वारा कोई सिफारिश की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तीनों देशों के अधिकारियों के एक कार्यकारी दल को, जिसकी स्थापना व्यापार के विस्तार के लिये उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिये की गई थी, परस्पर अधिमानों के आदान-प्रदान के विषय में बातचीत करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) कार्यकारी दल की एक बैठक काहिरा में 14 तथा 23 फरवरी, 1967 के बीच हुई थी।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा निकाले गये एक सम्मत दृष्टिकोण तथा उसके द्वारा अपनाये गये आधारभूत नियमों के आधार पर प्रारम्भिक बातचीत हो चुकी है ये वार्ताऐं अगली बैठक में, जिसके शीघ्र ही होने की सम्भावना है, जारी रहेंगी।

दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित किया जाना

* 252. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर अभी सम्बन्धित मन्त्रालयों से सलाह लेकर विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की मागें

* 253. **डा० रानेन सेन** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों ने मांग की एक सूची प्रस्तुत की थी जिसमें बोनस के भुगतान, उपदान, दूसरे वेतन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की मांग तथा अन्य मामले भी शामिल थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) ये मामले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसी स्वायत निगमों के सीमान्तर्गत हैं। स्थापित केन्द्रिय श्रम प्रबन्ध की सहायता से निगम इस मामले में रांची में कर्मचारियों के संघ से बात चीत कर रही है।

यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसे मामलों में कोई समय की हद निर्धारित नहीं की जा सकती।

कृषि में मशीनों के प्रयोग से औद्योगिक विकास

* 254. श्री हु० प० चटर्जी :
श्री दत्तात्रेय कुन्ते :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में 9 अप्रैल, 1967 से आरम्भ हुई फोर्ड फाउन्डेशन की गोष्ठी में अगले बीस वर्षों में पश्चिम बंगाल में मशीनों द्वारा खेती करके नगरीकरण तथा औद्योगिक विकास को संतुलित करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या क्या निश्चित सुझाव दिये गये थे; और

(ग) क्या यह सच है कि इस विकास योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग रांची से लेकर दुर्गापुर तक बिहार-पश्चिम बंगाल उद्योग-समूह का समन्वित चित्र तैयार करना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) समझा जाता है कि बिहार सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से 9 और 10 अप्रैल, 1967 को पटना में नागरिक विकास पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस गोष्ठी में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनके बारे में बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह जैसे ही उपलब्ध होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हथकरघा से बने माल का बिन बिका स्टाक

*255. श्री कृष्णमूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास राज्य में हथकरघा से बने माल का बिन बिका स्टाक काफी मात्रा में पड़ा हुआ है; और

(ख) मद्रास राज्य में पड़े हुए बड़े स्टाक को बेचने के लिए उपयुक्त विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 510/67]

इन्जीनियरी के सामान के निर्यातकों को इस्पात का दिया जाना

* 256. श्री गरणेश :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० स्थोस :
श्री उमा नाथ :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरी का सामान निर्यात करने वालों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध कराने का है ;

(ख) इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए सरकार कितनी आर्थिक सहायता देगी ; और

(ग) इस समय इस्पात के "अन्तर्राष्ट्रीय" और 'भारतीय' मूल्यों में प्रति टन क्या अन्तर है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित की गई योजना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। (पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 506/67)

(ख) यह खर्च सरकार नहीं वरन उत्पादक सहन करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंजीनियरी साज-सामान के निर्माता कितना माल निर्यात करते हैं।

(ग) इस्पात की किस्म (केटेगरी) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय मूल्यों में 30 रु० से लेकर 200 रुपये तक का अन्तर है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

* 257. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का वित्त पर क्या प्रभाव होगा ; और

(ख) इस्पात का प्रयोग करने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और उपक्रमों पर इसका किस सीमा तक प्रभाव होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां। इस्पात के मूल्य में लगभग 53 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे के मूल्य में 22 रुपये प्रति टन की औसतन वृद्धि हुई है। सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों को इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निर्यात व्यापार

*258. **श्री एस० एन० माइति** :
श्री स० चं० सामन्त

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निर्यात व्यापार बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

+

259. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है; और

(ख) आवश्यकता की पूर्ति के लिए ट्रैक्टरों के निर्माताओं को क्या सुविधाएं दी गई हैं जिससे विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात न किया जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । लक्षित कृषि उत्पादन को प्राप्त करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1,50,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) ट्रैक्टर निर्माण करने वाले वर्तमान एककों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है और उन्हें अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा नियत कर दी गई है । फिर भी 1967-68 में उत्पादन आवश्यकता से कम होने की आशंका है और इसलिए कुछ आयात करना अनिवार्य होगा ।

रूई कताई कारखाने

*** 260. श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में हाल ही में मंजूर किये गये रूई कातने के दस कारखानों में कब उत्पादन शुरू होगा;

(ख) क्या इसी अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई मिश्रित कारखाना भी मन्जूर किया गया है;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र में मिश्रित तथा कताई कारखानों की संख्या कितनी थी;

(घ) इनमें से कितने कारखानों ने उत्पादन शुरू किया है; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में दोनों प्रकार के कितने कारखाने लगाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

वाणिज्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह : (क) इन कारखानों में से किसी में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) तीन मिश्रित (कम्पोजिट) कारखानों को लाइसेंस दिये गये थे।

(ग) तथा (घ) केवल सहकारी कताई मिलों के लिये 47 लाइसेंस दिये गये थे जिनमें से 12 कारखानों में उत्पादन शुरू हो चुका है।

(ङ) ऐसा अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र में लगभग 3·25 लाख तकुए तथा निजी क्षेत्र में 17.5 लाख तकुए तथा 20,000 करघे स्थापित किए जायेंगे।

इंजीनियरी उद्योग

***261. डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरिंग उद्योगों की फालतू क्षमता, कच्चे माल का आत्यधिक अभाव तथा मांग में कमी जैसी समस्याओं की ओर दिलाया गया है,

(ख) इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सभी एककों में अधिक से अधिक उत्पादन हो; और

(ग) क्या सरकार का विचार खेती के उन औजारों का निर्माण प्रारम्भ करने के लिये जिनकी खाद्य उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तत्काल आवश्यकता है, कुछ एककों को प्रोत्साहन देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Cigarette Industry

* 262. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign companies have monopolised the cigarette industry;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to abolish the said monopoly ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There are 13 cigarette manufacturing units in the country with an annual installed capacity of 45,228 million pieces of cigarettes. Share of foreign firms in the total production of cigarettes is of the order of about 70%. The foreign investment in this industry is 80% of the total investment.

(b) The foreign companies have been the pioneers in the cigarette industry in the country and have been manufacturing cigarettes for a very long time.

(c) The production of cigarettes by Indian firms has increased from 14.7% in 1955 to 29.4% of the total production during 1966. Indian Cigarette firms are being encouraged to augment their production and thereby have an increased share in the expanding market. Additional capacity has been approved in favour of firms who are 100% Indian.

नेपाल के साथ व्यापार

+263. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री आर० के० सिन्हा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल सरकारों में दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों के बारे में गम्भीर मतभेद है; और

(ख) क्या दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार सम्बन्ध कायम करने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) नेपाल तथा भारत के बीच व्यापार पहले की तरह ही चल रहा है । पर दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं तथा इसी उद्देश्य से, व्यापार बढ़ाने एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोनों सरकारों के बीच समय समय पर बातचीत होती रहती है ।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना

*264. श्री उमा नाथ :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुगलसराय के निकट जीवथपुर में एक ट्रैक्टर कारखाना बनाने का पहले निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां तो इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार इस कारखाने को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले के रामनगर नामक स्थान पर चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कृषि ट्रैक्टरों और औजारों का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है किन्तु इसे कार्यान्वित करने के बारे में अन्तिम निर्णय चेकोस्लोवाकिया की फर्म मेसर्स मोटोकोव से कारखाने के तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जायगा । परियोजना के आर्थिक संभाव्यता से सम्बन्धित प्रतिवेदन का प्रथम भाग 22-5-67 को प्राप्त हुआ था और उसकी जांच की जा रही है परियोजना पर अन्तिम निर्णय प्रतिवेदन की विस्तृत जांच करने के बाद ही किया जायेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता

पटसन और चाय पर निर्यात शुल्क

*265. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री श्री गोपाल साबू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के लिये पटसन, चाय तथा अन्य ऐसी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क कम कर देने के कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह सुझाव भी मिला है कि पश्चिम यूरोप में खुले नीलाम के स्थान पर भारतीय काफी के लिये मुहरबन्द टेंडर मांगने की पद्धति लागू की जाये ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी देशों के लिये मुहरबन्द टेंडर प्रणाली शुरू करने के लिये काफी बोर्ड के पास सुझाव आया है । इस सुझाव पर बोर्ड की विपणन समिति आगामी बैठक में, जो शीघ्र ही होने वाली है, विचार किया जायेगा ।

(ग) जूट, चाय, मेंगनीज तथा लौह अयस्कों (बढ़िया) पर निर्यात शुल्क बजट प्रस्तावों में, जो पहले ही सभा के सामने हैं, कम कर दिये गये हैं । 9 मई, 1967 को कच्ची ऊन पर

भी निर्यात शुल्क कम कर दिया गया था। इस वर्ष अभी तक किसी अन्य वस्तु के म.मले में कोई कमी नहीं की गयी है। उपर्युक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट सुझाव पर काफी बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

सी० आई० स्लीपर

***266. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री श्री गोपाल साबू :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1956 में 14,000 टन सी० आई० स्लीपरों के निर्माण तथा संभरण के लिये एक फर्म को आदेश दिया था ;

(ख) क्या इस ठेकेदार को दिया गया कच्चा लोहा उस मात्रा से बहुत अधिक था जितना उसे देना तय हुआ था ;

(ग) क्या इस ठेकेदार द्वारा यह कार्य 7 वर्ष की अवधि में थोड़ा-थोड़ा करके पूरा किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे ने उपर्युक्त फर्म से न तो अतिरिक्त कच्चा लोहा ही वापिस लिया था और न ही उससे क्षतिपूर्ति ली थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा तथा इस मामले में रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। फर्म को 879 टन कच्चा लोहा अधिक दे दिया गया था लेकिन ऐसा पूरी लागत का भुगतान हो जाने के बाद ही किया गया था क्योंकि ठेके के अनुसार कच्चे लोहे की लागत फर्म को ही देनी थी।

(ग) जी नहीं। ठेका देने के दो वर्ष से भी कम समय के भीतर यह काम पूरा हो गया था।

(घ) जी नहीं। बाद में 1961 में एक और आर्डर देते समय उस आर्डर से तदनुरूप कम कच्चा लोहा सप्लाई करके इस बढ़ती का समंजन कर लिया गया।

(ङ) और (च) जब अधिक सामान जारी किये जाने की सूचना मिली, तो रेलों ने इसकी विशेष रूप से जांच की। बाद में एक और आर्डर देते समय उस आर्डर से तदनुरूप कम कच्चा लोहा सप्लाई करके इस बढ़ती का समंजन कर लिया गया। कच्चा लोहा 1961 में भी नियंत्रित वस्तु था और 1957 से 1961 के बीच इसके नियंत्रित मूल्य में कोई अन्तर नहीं था।

राजस्थान में टंगस्टन धातु निकालना

* 267. श्री देवेन सेन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से राजस्थान सरकार द्वारा अथवा उसके नियंत्रणाधीन एक समवाय द्वारा टंगस्टन धातु निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह धातु समय समय पर गैर-सरकारी लोगों को किन दामों पर बेचा गया था ;

(ग) क्या यह धातु कभी केन्द्रीय सरकार को अथवा उसके प्रतिरक्षा संस्थान को भी बेचा गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितना धातु और किन दरों पर बेचा गया ; और

(ङ) गैर-सरकारी लोगों से तथा सरकार से लिये गये मूल्यों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राजस्थान सरकार के खान तथा भौमिकी विभाग द्वारा टंगस्टन का खनन किया जाता है ।

(ख) बेचने की दरें प्रति टन ये थीं—9-8-63 से 26-8-65 तक के समय में 9, 000 रुपये, 27-8-65 से 22-5-66 तक के समय में 13, 500 रुपये, 21-5-66 से 26-2-67 के समय में 17, 200 रुपये और 27-2-67 से आगे 24,000 रुपये।

(ग) और (घ) 27-8-63 से 20-5-66 के काल में 13,500 रुपये प्रति टन की दर से केन्द्रिय सरकार के विभागों को 6. 25 टन बेचे गए ।

(ङ) एक ही समय में निजी वर्गों तथा सरकार के विभागों को दिये जाने वाले टंगस्टन के संकेन्द्रितों के बेचने के मूल्य में कोई अन्तर नहीं है ।

एल्यूमिनियम की मांग और उत्पादन

* 268. श्री निहाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी चार वर्षों में एल्यूमिनियम की कितनी मांग होने का अनुमान है तथा उसके उत्पादन का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ;

(ख) क्या कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि बिजली, केबल तथा अन्य उद्योग एल्यूमिनियम के स्थान पर तांबा प्रयोग करें ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पृथक-पृथक क्या उत्पादन होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सन् 1970-71 तक एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग 3, 30,000 मीट्रिक टन है (इसमें निर्यात के लिए 30,000

मीट्रिक टन भी सम्मिलित हैं)। उत्पादन के लक्ष्य भी इसी स्तर पर निर्धारित किये गये थे परन्तु बाद में संशोधन करके यह 2, 63, 300 मीट्रिक टन कर दिये गये। एल्यूमिनियम का प्रयोग करने वाले तथा अन्य उद्योगों की मांग में सम्भावित कमी को दृष्टि में रख कर मांग और उत्पादन के लक्ष्यों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ख) केबल उद्योग में काफी अधिक सीमा तक एल्यूमिनियम के स्थान पर तांबे का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम पर आधारित मिश्रित धातुओं को विकसित किया जा रहा है तथा तांबा, जस्ते और सीसे जैसी अलौह-धातुओं के प्रयोग के स्थान पर एल्यूमिनियम के प्रयोग के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

(ग) यह आशा की जाती है कि सन् 1970-71 तक निजि क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में उत्पादन क्रमशः 2, 38, 300 मीट्रिक टन और 25,000 मीट्रिक टन होगा।

सूत के मूल्य

* **269. श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों, हथकरघा तथा शक्तिचालित संगठनों के प्रतिनिधियों की तदर्थ समिति सूत के मूल्यों को उचित स्तर पर रख सकी है ; और

(ख) इस तदर्थ समिति की नियुक्ति के बाद विभिन्न काउन्ट के सूत के मूल्यों में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सूत के भावों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

सूत के भाव बढ़ जाने की खबरें मिलने पर वस्त्र मिलों, हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा संगठनों, सूत के व्यापारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बम्बई में 7-9-1966 को एक बैठक हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि वस्त्र उद्योग, हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा संगठन, राज्य सरकारों और वस्त्र आयुक्त के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति की स्थापना की जाये ताकि वह सूत के भाव को उचित स्तर पर रखने के लिये मार्ग सुझाए। समिति सूत के भाव को नीचे स्तर पर रखने में समर्थ नहीं हो सकी है क्योंकि ऐसे प्रमुख तत्वों पर, जिनसे भाव बढ़ते हैं जैसे (क) कपास के भाव बढ़ने और (ख) कपास की कमी के कारण मशीनों के चलने को कम करने, पर समिति का कोई नियन्त्रण नहीं है।

कोयम्बटूर के बाजार में 7 सितम्बर 1966 से 19 मई 1967 तक सूत के प्रमुख काउण्टों के बाजार भावों में उतार चढ़ाव का औसत प्रतिशत नीचे दिया जाता है :-

काउण्टस्	
10	+ 0.0 प्रतिशत
20	+ 14. 2 प्रतिशत

30	+ 13. 4 प्रतिशत
40	+ 12. 9 प्रतिशत
60 भारतीय धुनी हुई	— 5. 1 प्रतिशत
60 भारतीय साफ की हुई	+ 2. 1 प्रतिशत
80 मिस्री धुनी हुई	+ 15. 1 प्रतिशत
80 मिस्री साफ की हुई	+ 21. 7 प्रतिशत
100 धुनी हुई	+ 5.5 प्रतिशत
100 साफ की हुई	+ 6.2 प्रतिशत

प्राकृतिक साफ्ट कोक

*** 270. श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने ऐसा संकेत दिया है कि भारत में लगभग 200 मिलियन टन प्राकृतिक साफ्ट कोक उपलब्ध है जिसे निर्मित साफ्ट कोक से सस्ता बेचा जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी खोज करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) क्या यह इतना ठोस होता है कि लदान में इसका बहुत अधिक ह्रास नहीं होता ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) 1966-67 के क्षेत्र सम्बन्धी चालू मौसम में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने झरिया के कोयला क्षेत्रों के प्राकृतिक साफ्ट-कोक के विभिन्न क्षितिजों को चित्रण करने के अन्वेषण कार्य को हाथ में ले लिया है । आशा है कि यदि वर्तमान अन्वेषणों के परिणाम आशा वर्धक हुए तो अन्य कोयला क्षेत्रों में भी यह कार्य किया जायेगा ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

हिम्मत नगर और उदयपुर के बीच मीटर गेज लाइन पर रेलवे स्टेशन

1251. श्री चं० चु० देसाई : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिम्मत नगर और उदयपुर के बीच मीटरगेज लाइन पर रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं और यह रेलवे लाइन कितने कस्बों अथवा बड़े गांवों से होकर जाती है तथा रेलवे स्टेशन तथा उपर्युक्त गांवों अथवा कस्बों के बीच कितनी दूरी है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह रेलवे लाइन तितोई के बड़े कस्बे से जाती है किन्तु रेलवे स्टेशन छः मील की दूरी पर है और उसका नाम शामलजी रोड है तथा इस स्टेशन पर के यात्रियों के लिए कोई सड़क परिवहन उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तितोई गांव की सीमा में रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है क्योंकि यहां से रेलवे लाइन गुजरती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हिमतनगर और उदयपुर के बीच स्थित रेलवे स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं :-

(1) हिमतनगर
(2) वीरावाडा
(3) रायगढ रोड
(4) सुनोख
(5) शामलाजी रोड
(6) लूसडीया
(7) जगाबोर
(8) बिछीवाड़ा
(9) श्री भवनाथ
(10) डूंगरपुर
(11) कोटाणा
(12) रखबदेव रोड
(13) समारी
(14) सुरखंड का खेड़ा
(15) जयसमंद रोड
(16) पाडला
(17) जावर
(18) खरवाचांदा
(19) उमड़ा
(20) उदयपुर सिटी

हिमतनगर-उदयपुर लाइन जिस क्षेत्र से होकर गुज़रती है, उसमें 600 से अधिक गांव या शहर पड़ते हैं। लेकिन इसमें केवल 4 शहर या बड़े गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है, वे हैं हिमतनगर, डूंगरपुर, सालंबर और उदयपुर। रेलवे स्टेशनों और उनके साथ के गांवों या शहरों के बीच की दूरी के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रेलवे लाइन तितोयी और शामला जी गांवों से गुज़रती है। शामाला जी रोड स्टेशन से तितोयी गांव केवल 2 मील दूर है।

(ग) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र के समवायों का बोर्ड

1252. श्री चं० चु० देसाई :
श्री म० ग्रमरसे :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के समवायों के बोर्डों के चेयरमैनों। मैनेजिंग डायरेक्टरों तथा डायरेक्टरों की नियुक्तियों के बारे में सरकार की नीति क्या है,

(ख) वर्तमान चेयरमैनों, मैनेजिग डायरेक्टरों तथा डायरेक्टरों में से कितने लोग सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे पदों पर सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में सरकार की नीति क्या है :

(ग) क्या इन सरकारी उपक्रमों से सेवा निवृति की कोई आयु-सीमा है ;

(घ) इन में से किन-किन चेयरमैनों अथवा मैनेजिंग डायरेक्टरों को दिल्ली में रहने की अनुमति है और उन के दिल्ली में रहने का औचित्य क्या है जब कि सरकारी उपक्रम अन्य स्थानों पर हैं : और

(ङ) सरकारी उपक्रमों में नियुक्त इन सेवा निवृत वार्धक्यता प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं और उन की सेवा की अवधि कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : सरकार की नीति यह है कि वह सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों तथा निदेशकों के पदों पर नियुक्ति करने में पद विशेष को ध्यान में रखते हुए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों से उपलब्ध व्यक्तियों में से अत्यन्त उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाय। इस कार्य के लिये यदि कोई उपयुक्त सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी मिल जाता है तो उसकी विशेष रूप से उपयुक्त पद पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जाता है। इस समय कितने सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) सरकारी उपक्रमों में अध्यक्षों तथा निदेशकों के सेवा निवृत्त होने के लिए आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है अपितु कम्पनियों से पूर्ण कालिक कर्मचारियों को सामान्यतः 60 वर्ष की आयु के पश्चात् नहीं रहने दिया जाता है।

(घ) तथा (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स इंडियन एलक्ट्रिक वर्क्स लि०, कलकत्ता

1253. श्री राम किशन गुप्त :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द्र कछवाय :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडियन एलैक्ट्रिक वर्क्स लि०, कलकत्ता के कार्य कलापों की जांच करने के लिये स्थापित की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मैसर्स इण्डिया एलैक्ट्रिक वर्कस लिमिटेड, कलकत्ता के मामलों की जांच करने के लिये स्थापित की गई तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और सरकार ने उसपर विचार कर लिया है। मामले में अन्तिम निर्णय की शीघ्र ही घोषणा की जायेगी।

Branch Line Between Muzaffarpur And Darbhanga

*1255. **Shri K.M. Madhukar**: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether a survey was conducted with a view to construct a direct branch line between Muzaffarpur and Darbhanga of the North Eastern Railway;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) when the work connected therewith would be started?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Preliminary Engineering and Traffic Surveys for Muzaffarpur-Darbhanga (63-KMs.-M.G.) rail link were carried out in 1957-58 and 1956-57 respectively.

(b) The cost of the line was then assessed at Rs. 2.32 crores, and it was expected to yield a return of 0.13% that is, it was unremunerative. Moreover, the Survey Reports also revealed that this line would not serve the main purpose for which it was intended, namely, that of relieving the congestion on the busy Samastipur-Darbhanga section. The proposal was therefore dropped.

(c) Does not arise.

नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन

1256. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) में कोई उच्च श्रेणी महिला प्रतीक्षालय नहीं है ;

(ख) क्या सामान्य प्रतीक्षालय छोटा है और उसमें पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है तथा सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर पार्सल छुड़ाने का कार्यालय नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पार्सल प्लेटफार्मों पर पड़े रहते हैं और यात्रियों को असुविधा होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्टेशन पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं । ऊंचे दर्जे के यात्री यातायात की वर्तमान मात्रा, जो 4 यात्री प्रति दिन है, के लिए ऊंचे दर्जे का मिला-जुला प्रतीक्षालय पर्याप्त आकार का है और उसके साज-सज्जे पर्याप्त हैं । इस में सफाई का भी उचित प्रबन्ध है ।

(ग) जी हां । यहां अलग से कोई पार्सल घर नहीं है, लेकिन मूल्यवान पार्सलें टिकट घर के पीछे एक 30 फुट × 20 फुट कमरे के अन्दर रखे जाते हैं । दूसरी पार्सलें प्लेटफार्म पर रखे जाते हैं और इन से यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि इस स्टेशन पर बहुत थोड़ा पार्सल-यातायात होता है ।

(घ) ऊपर भाग (ख) और (ग) में दिये गये उत्तरों को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाझा

1257. श्री केदार पास्वान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने झाझा, पूर्वी रेलवे के लिये एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृत दी है;

(ख) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षायें मिडिल स्कूल के भवन में लगती हैं;

(ग) क्या कक्षाओं के लिये कमरों के अभाव के कारण कई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो झाझा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये भवन कब बनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

रेलवे की भूमि पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन

1258. श्री केदार पास्वान :

श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के झाझा और जमालपुर नगरों में पूर्व अनुमति लिये बिना रेलवे भूमि पर सार्वजनिक सभायें आयोजित करने पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या कर्मचारी संघों/कर्मचारियों ने यह प्रार्थना की है कि ऐसा कठिन प्रतिबन्ध हटा दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन का विचार रेलवे की भूमि तथा सार्वजनिक स्थानों पर शान्तिपूर्वक होने वाली सभाओं तथा प्रदर्शनों के आयोजन पर से सभी प्रतिबन्ध हटाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

जन सम्पर्क अधिकारी (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का कार्यालय

1259. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के जन-सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी हैं और 1966 में उस कार्यालय पर कितनी राशि खर्च की गई तथा 1967 के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) अन्य ज़ोनल रेलों में जन-सम्पर्क अधिकारियों के कार्यालयों पर कितनी राशि खर्च हुई है और वहां कितने कर्मचारी हैं तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के जन-सम्पर्क कार्यालय के साथ इनकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) राजपत्रित : 3

अराजपत्रित :	85
1966-67 में किया गया खर्च :	3,79,575 रुपये
अप्रैल, 1967 से जुलाई, 67 के लिए स्वीकृत रकम	1,35,900 रुपये

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इटारसी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे)

1260. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर तीसरे दर्जे के यात्रियों का प्रतीक्षा-कक्ष तथा टिकट घर स्टेशन की मुख्य इमारत से अलग हैं और वे पुल से सीधे मिले हुए नहीं हैं जिसके कारण पुल तक पहुंचने के लिये यात्रियों को धूप अथवा वर्षा में से होकर जाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि पार्सल रखने के लिये कोई अलग शैड नहीं है ;

(ग) क्या प्लेटफार्म नम्बर 4 और 5 तथा उन को मिलाने वाले पुल पर कोई शैड नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्टेशन पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । इटारसी स्टेशन पर तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और टिकट घर स्टेशन की मुख्य इमारत से विच्छिन्न हैं और ये दोनों ही एक छतदार रास्ते द्वारा ऊपरी पैदल पुल से सीधे जुड़े हुए हैं ।

(ख) जी नहीं। पार्सल रखने के लिए एक अलग शैड है।

(ग) जी हां।

(घ) द्वीप प्लेटफार्मों (न० 4 और 5) पर 300 फुट लम्बी छत लगाने का काम जारी है। ऊपरी पैदल पुल तथा तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय और ऊपरी पैदल पुल के बीच के रास्ते पर छत डालने के काम को, जो अपेक्षाकृत निम्नतर प्राथमिकता का काम है, आगामी वर्षों में शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

Issue of Industrial Licences in Bihar

1261. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Bihar State who have applied for industrial licences during the period from April, 1966 to March, 1967; and

(b) the number of applications considered and the nature of the decisions taken thereon so far ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) ;

(a) Thirtyeight applications for grant of industrial licences in Bihar State were received during the period from April, 1966 to March, 1967. This number excludes one application in which the value of fixed assets, i.e. cost of land, buildings and machinery, was stated to be less than Rs. 25 lakhs and for which an industrial licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 is not required.

(b) Five applications have been approved, three rejected and thirty applications are at various stages of consideration.

Trade with South Africa and other Asian Countries

1262. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether India is having trade relations with South Africa and other Asian countries ;

(b) if so, the name of the Asian countries with which India is doing trade on a comparatively larger scale; and

(c) the commodity in which the trade is done ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) India has no trade relations with South Africa, but has trade relations with many Asian countries.

(b) The Asian countries with which India is doing trade on a fairly large scale are Afghanistan, Burma, Ceylon, Malaysia incl. Singapore, Iran, Japan, Pakistan, Saudi Arabia, and Nepal.

(c) A statement of the commodities in which the trade is done is given below.

Statement

Asian countries with which India has two-way trade (imports plus exports) exceeding Rs. 10 crores per annum, alongwith names of important commodities.

1. **Afghanistan**

Imports. Fruits and Vegetables (almonds and rasins are important components).

Exports. Tea, Cotton Piecegoods & Jute manufactures.

2. **Burma.**

Imports. Rice and lead.

Exports. Coir yarn & manufactures, jute manufactures, fish & fish preparation base metals & manufactures thereof.

3. **Ceylon.**

Imports. Copra, Natural rubber.

Exports. Spieces, chilly is the main item, cotton twist & yarn, Cotton piecegoods, fruits & Vegetables, fish & fish preparations. Metals & metal manufactures, Machinery and transport equipment and Cinematographic films exposed.

4. **Malaysia.** (incl. Singapore which has since seceded)

Imports. Natural rubber and gums, copra, Tin, Palm oil.

Exports. Cotton piecegoods, Sugar, Onions, Jute bags, Machinery and Trans port equipment.

5. **Iran.**

Imports. Fruit and Vegetables (almonds is the main item) petroleum and petroleum products.

Exports. Tea, Jute cloth, Machinery and Transport Equipment, Base metals and manufactures.

6. **Japan.**

Imports. Chemical elements and compounds, Fertilizer manufactures, Iron and Steel, Metal manufactures, Machinery of which machinery other than electric is the main item. Transport equipment, Professional scientific and controlling instruments etc.

Exports. Animal Casing, Oil cakes, Cotton raw, Mica, Iron, Iron and Steel Scrap, Manganese Ore, Leather.

7. **Pakistan.**

Exports. Coal and Coke, Base metals and manufactures, Machinery and transport equipment.

Imports. Jute raw.

8. **Saudi Arabia.**

Imports. Petroleum Crude and partially refined.

Exports. Spices, Cotton Pieces goods.

9. Nepal.

Imports. Jute raw, jute manufactures, oil cakes, Ghee, Rice.

Exports. Sugar and preparations. Tea, Tobacco, Petroleum products, Cotton fabrics, Machinery other than electric.

State Trading Corporation

1263. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of commodities which have been brought within the purview of the State Trading Corporation since its inception; and

(b) the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) Two statements showing the items handled by the State Trading Corporation for export/import since its inception are placed on the Table of the House. **(Placed in Library, see No. LT-507/67)**

नेपा अखबारी कागज बनाने का कारखाना

1264. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में नेपा अखबारी कागज बनाने के कारखाने में उत्पादन को दुगुना करने के लिये कोई रूप रेखा तैयार की है :

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है तथा सरकार का किस प्रकार इसको कार्यरूप देने का विचार है।

(ग) क्या वहां बनने वाले अखबारी कागज की किस्म को सुधारने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय काय मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) : नेपा अखबारी कागज बनाने के कारखाने का विस्तार कार्यक्रम नक्शे की अवस्था को पार कर गया है और उसे वास्तव में अमल में लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति से पहले प्रति वर्ष 30,000 से 75,000 मीट्रिक टन तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार है। इस पर कुल 11.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा जिसमें 4.03 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है। "कागज विभाग" और "रिकवरी विभाग" की मशीनों के लिए आदेश दिये जा चुके हैं और 'कागज विभाग' के लिये मशीनों का आना प्रारम्भ भी हो गया है, लुगदी तैयार करने वाले विभाग की मशीनों के लिए आर्डर शीघ्र ही दिए जायेंगे आशा है कि कागज विभाग मई, 1968 तक चालू हो जायेगा।

(ख) से (घ) : नेपा मिल्स द्वारा बनाये जाने वाले अखबारी कागज की किस्म में सुधार हुआ है और इस संबंध में हाल के पिछले कुछ समय में उपभोक्ताओं ने कोई भी शिकायत नहीं की है।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिल

1265. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में रुई न मिलने के कारण अनेक कपड़ा मिलों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अथवा इन मिलों के प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है;

(ग) क्या कुछ मिलों को धन की कमी के कारण भी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग को इस कठिनाई से उबारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) कुछ मिलों के आर्थिक कठिनाइयों में होने की सूचना मिली है।

(घ) जी हां।

(ङ) जब भी किसी सूती कपड़ा मिल को आर्थिक सहायता देने के लिये प्रार्थना आती है तो प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और ऐसा करते समय यह देखा जाता है कि मिल आर्थिक दृष्टि से चलने योग्य है या नहीं और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है।

तिरुनेलवेली और त्रिवेन्द्रम के बीच रेलवे लाइन

1266. डा० संतोषम् : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरास्ता नागेरकोइल और कन्याकुमारी तिरुनेलवेली से त्रिवेन्द्रम तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन का कार्य इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) क्या यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। इस लाइन का इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है।

लौह अयस्क का निर्यात

1267. श्री डी० एन० देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की बिक्री बढ़ाने के सिलसिले में किसी दल को पूर्वी यूरोप में भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो दल को कितने ठेके मिले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मन जनवादी गणराज्य तथा हंगरी, जिनका दल ने दौरा किया, के साथ दल ने 15 लाख मैं० टन लौह अयस्क के निर्यात के लिये बिक्रय करार किये । यह रुमानिया तथा युगोस्लाविया से 8 लाख मे० टन लोह अयस्क के लिये पहले ही किये गये करारों को अलावा है ।

जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

1268. (श्री काशीनाथ पाँडे) : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता पर नियंत्रण बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थिति में ऐसा किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के आधीन जैसप एण्ड कम्पनी, लि., कलकत्ता के प्रबन्ध पर नियन्त्रण की अवधि 15 मई, 1967 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है ।

(ख) नियन्त्रण में यह वृद्धि लोक हित की दृष्टि से आवश्यक समझी गई थी ।

फरीदाबाद की फर्म के लिए अमरीकी ऋण

1269. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने 16 मई, 1967 को फरीदाबाद की एक फर्म को 1.64 करोड़ रुपये का ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किस उद्देश्य से तथा किस फर्म को दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अमरीकी सरकार ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से सरकार से "आपत्ति नहीं" का पत्र प्राप्त करने के पश्चात् नई दिल्ली की मैसर्स ग्लोब यूनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाऊण्ड्री कम्पनी लिमिटेड को उनके फरीदाबाद में रोल्स परियोजना के लिए देश में ही उपलब्ध मशीनों इत्यादि के खरीदने के लिए 164 लाख रुपये का कुल ऋण देना स्वीकार कर लिया है । यह समझौता 15 मई, 1967 को हुआ था ।

Manufacture of Paper and Pulp

1270. Shri Valmiki Choudhary :
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to **state :**

(a) whether Government are considering any proposal, submitted by a British firm, for manufacturing paper and pulp in India, and

(b) if so, the details of the programme submitted by the said firm ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There is no such proposal from any British firm. However, the attention of Government has been drawn to a new process for making pulp and paper developed by a company in Mexico, and arrangements have been made by Government for the preparation of a Project Report for the establishment of a paper newsprint Mill in the U. P. Bihar area with a British firm, who have been appointed engineers by the Mexican company.

(b) The Report referred to above is still awaited.

अमरीका तथा रूस के साथ व्यापार

1271. श्री शि० चं० झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका और रूस को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तथा वहां से आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 508/67]**

ठेकेदार के नियन्त्रणाधीन हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाना

1272. श्री शि० चं० झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदार के नियन्त्रणाधीन हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाने के लिये कुछ विशेष शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(ग) कोई हाल्ट स्टेशन बनाने के लिये क्या-क्या बातें आवश्यक होती हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) हाल्ट स्टेशन को झंडी स्टेशन में बदलने के बारे में विचार करते समय बदलाव पर आने वाली अतिरिक्त लागत, परिचालन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय और प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के आधार पर इस काम के वित्तीय भविताओं का पता लगाना अपेक्षित होता है । जहां हाल्ट स्टेशन को झंडी स्टेशन में बदलना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण न हो, लेकिन यात्री सुविधा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो, वहां उस मामले में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की सलाह से विचार किया जाता है ।

रेल-प्रशासनों को यह हिदायत है कि जहां किसी हाल्ट स्टेशन को बने 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो और जहां पर्याप्त यात्री यातायात होता हो, वहां हाल्ट स्टेशन को झंडी स्टेशन में बदलने की वांछनीयता पर विचार किया जाय ।

(ग) जहां विभाग द्वारा परिचालित रेलवे स्टेशन खोलने का औचित्य न हो, वहां उस क्षेत्र की जनता को यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से विकल्प रूप में ठेकेदारों द्वारा परिचालित हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में विचार किया जाता है । हाल्ट स्टेशन खोलते समय सुझाव के

वित्तीय भविताओं, क्षेत्र में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, साथ के स्टेशनों से प्रस्तावित हाल्ट की दूरी आदि बातों का ध्यान रखा जाता है।

उड़ीसा में रेलवे लाइनें

1273. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्रमानुसार रेलवे निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित की जाने के लिये किन किन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य की सिफारिश की है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में कौन कौन सी रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) क्या पुरी से कोणार्क तक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनें बनाने की सिफारिश की है :—

1. नयागढ़ होकर बांसपानी से पारादीप ।
2. तालचेर–विमलगढ़ ।
3. तालचेर–सम्बलपुर ।
4. बाराबिल–कोरिया वैली–किरीबुरु ।
5. रायगढ़ा–नवरंगपुर–जायपुर–कोरापुट ।
6. गोपालपुर–बरहामपुर ।
7. बालीमेला होकर दांतेवाड़ा से सुकमा या गुप्तेश्वर होकर जायपुर से बालीमेला ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में जो नयी लाइनें बनायी जानी हैं उनके बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के कारखाने

1275. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के कारखानों की स्थापना के लिए स्थान चुनने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) इन दोनों सरकारों ने इन कारखानों के लिये किन किन स्थानों का सुझाव दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय कारखानों के स्थान के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ का ज्ञापन

1276. श्री प्र० कु० घोष : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ, रांची ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य के विभिन्न पहलू और कर्मचारियों की मांगें दर्शाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) इस अवस्था में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है क्योंकि ये मामले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसी स्वायत्त निगमों के सीमान्तर्गत हैं। स्थापित केन्द्रिय श्रम प्रबन्ध की सहायता से निगम इस मामले में कर्मचारियों के संघ से रांची में बात चीत कर रही है।

Asian Institute of Economic Development and Planning

1277. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan objected to the proposal of extending the term of the Asian Institute of Economic Development and planning in the meeting of ECAFE held recently at Tokyo;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the decision taken in the matter ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) ; (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A Resolution adopted unanimously at the 23rd Annual Session of ECAFE at Tokyo noted the continuing need of the Asian countries for the types of training provided by the Institute, and recommended that the cash contribution to be pledged by the Governments for the next five-year period (1969-1973) for running the Institute should be greater than, and in no case less than, the total amounts pledged by them during the first five years period (1964-1968) so as to allow for a normal increase in costs, and decided that the performance and achievements of the Institute be continued to be reviewed periodically and annual reports placed before the Annual ECAFE Sessions to enable the Commission to consider at its 28th Session in 1972 the question of giving the Institute a permanent status.

आयात लाइसेंसों का दिया जाना

1278. श्री अब्दुलगनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना बैंक स्वीकृति प्रमाण पत्र आयात लाइसेंस दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1962 से 31 मार्च, 1967 तक इन प्रमाणपत्रों के बिना कितने आयात लाइसेंस दिये गये; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया है और यदि हां, तो किन को उत्तरदायी समझा गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भूतपूर्व निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत आयात लाइसेंस ऐसे बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिए जाते थे जिनमें विदेशी मुद्रा की वसूली का उल्लेख हो। चूंकि आयात लाइसेंस इसी शर्त पर दिए जाते थे कि विदेशी मुद्रा वसूल कर ली गई हो, जिसमें स्वभावतः कुछ समय लगता था, अतः निर्यात प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। इसलिये 1962 में एक निर्णय किया गया कि पंजीकृत निर्यातक निम्मलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत करने पर आयात लाइसेंस के हकदार हो सकते हैं :—

(1) निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि सौदे उनकी पालिसी के अन्तर्गत हुए हैं और माल खरीददार को सुपुर्द हो चुका है और स्वीकृत हो चुका है।

अथवा

(2) 6 महीने के अन्दर इस आशय का एक बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का वचन कि उन निर्यातों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की वसूली हो चुकी है जिनके आधार पर आयात लाइसेंस मांगा गया है।

6 महीने के अन्दर बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के वचन पर लाइसेंस की हकदारी की सुविधा बाद में 1 जुलाई 1965 से समाप्त कर दी गई।

6 जून 1966 को रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात संवर्द्धन योजनाएं समाप्त कर दी गईं। 6 जून, 1966 को या उसके बाद किए गए निर्यातों पर पुनः भरण लाइसेंस देने की एक नई नीति प्रारम्भ की गई। इस नीति के अन्तर्गत बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को आयात लाइसेंस देने के साथ परस्पर सम्बद्ध नहीं रखा गया है क्योंकि पुनःभरण लाइसेंस ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दिए जाते हैं जिसमें वास्तविक निर्यात का उल्लेख हो।

(ख) जहां तक 1 अप्रैल, 1962 से 31 मार्च, 1967 तक बैंक प्रमाण पत्रों के बिना दिए गए वर्षवार आयात लाइसेंसों की संख्या का प्रश्न है, निर्यातकों के विभिन्न वर्गों के आधार पर, जिन्हें बैंकर के प्रमाण पत्र या किसी अन्य आधार पर लाइसेंस दिए हैं, आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) चूंकि बैंक प्रमाण पत्र के बिना आयात लाइसेंस सरकारी नीति के अनुसार ही दिए गए हैं अतः उनके जारी करने के उत्तरदायित्व को नियत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन निर्यातकों के विरुद्ध, जो अपनी वचनवद्धता में उल्लिखित अवधि के अन्तर्गत निर्यात आय दिखाने में असफल रहे, दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।

महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना

1279. **श्री मधु लिमये :** **डा० राममनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि, महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना लगाने के बारे में पश्चिम जर्मनी के सलाहकारों के विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) जैसा कि 7 अप्रैल, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर में बताया गया था, पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाता मैसर्स वैरीनिगटे एल्यूमिनियम वर्के द्वारा तैयार किए हुए लागत के अनुमान ऊंचे स्तर के प्रतीत हुये और तदनुसार उनको लागत घटाने की सम्भावनाओं को खोजने के लिए और प्लांट की क्षमता के बारे में कुछ निर्धारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। लागत के अनुमानों को नीचे लाने के उद्देश्य से परामर्शदाताओं द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों की रोशनी में परियोजना रिपोर्ट का अब और आगे परीक्षण किया जा रहा है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

1280. श्री मणीभाई जे०पटेल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामसिंह श्रायरवाल :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **श्रौद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 31 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत में ट्रैक्टर बनाने की परियोजना के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन पर इस बीच विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रौद्योगिक विकास तथा समवास कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्रों में ट्रैक्टरों तथा खेती के औजारों का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित सयंत्र के बारे में चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रथम भाग 22 मई, 1967 को प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में बेकार पड़ी वस्तुएं

1281. श्री प्र० कु० घोष : क्या **श्रौद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची के स्टोर में कुल कितने मूल्य की वस्तुएं बेकार पड़ी हुई हैं;

(ख) ये वस्तुएं कितने समय से बेकार पड़ी हुई हैं;

(ग) इन वस्तुओं का किस कार्य के लिये प्रयोग किया जाना अपेक्षित था; और

(घ) ऐसी वस्तुओं पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1-4-67 को 94.66 लाख रुपये।

(ख) एक वर्ष से अधिक	27.91 लाख रु०
दो वर्ष से अधिक	39.75 लाख रु०
तीन वर्ष से अधिक	27.00 लाख रु०

(ग) कुछ की आवश्यकता निर्माण कार्यों के लिए तथा कुछ उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए थी।

(घ) 4.35 लाख रु०।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड को मशीनों की सप्लाई

1282. श्री प्र० कु० घोष : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची ने, बोकारो स्टील लि० को कुछ मशीनें तथा ढांचे सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है तथा ठेका कुल कितने मूल्य का है; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन इन क्रयादेशों के अनुसार कब माल सप्लाई करेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन 80,000 मी० टन मशीनी उपकरणों की विभिन्न वस्तुओं तथा 30,000 मी० टन ढांचों का सभरण करेगा। फिर भी सम्पूर्ण परिमाण के लिए औपचारिक आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं। इस अवस्था में इनका कुल मूल्य बता सकना सम्भव नहीं है।

(ग) 1967-68 से 1970-71 तक।

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, राँची द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने को माल की सप्लाई

1283. श्री प्र० कु० घोष : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची ने भिलाई इस्पात कारखाने को इंजीनियरी का कुछ माल सप्लाई किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य का माल सप्लाई किया गया है; और

(ग) क्या भिलाई इस्पात कारखाने ने यह माल स्वीकार कर लिया है और क्या वह हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को माल के लिये और क्रयादेश दे रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-स्नातक राजपत्रित रेलवे अधिकारी

1284. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ गैर-स्नातक राजपत्रित अधिकारियों का सेवा-काल 58 वर्ष की आयु से आगे बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति ली जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :-(क) सेवा-काल में वृद्धि सार्वजनिक हित में की जाती है । इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता । लेकिन इस समय ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

(ख) अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं है ।

वियतनाम (लोकतन्त्रीय गणराज्य) के साथ व्यापार

1285. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :-क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम (लोकतन्त्रीय गणराज्य) के साथ इस समय भारत के कोई व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 22 सितम्बर, 1956 को दोनों सरकारों के मध्य हुए पत्र-विनिमय के अनुसार भारत तथा वियतनाम के लोकतन्त्रीय गणराज्य के बीच एक व्यापार करार विद्यमान है, जिसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती है एवं यह 22 सितम्बर, 1968 तक चालू रहेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रक चालकों तथा रेलवे में प्रतियोगिता

1286. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या गैर-सरकारी ट्रक चालकों तथा रेलवे के बीच माल लाने ले जाने के लिए प्रतियोगिता कम करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबन्धित निगम स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चावल की भूसी से तेल निकालना

1287. **श्री ग्र० क० गोपालन :**
श्री राममूर्ति :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि चावल की भूसी में लगभग 15 प्रतिशत तेल होता है;

(ख) यदि हां, तो चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1966–67 में देश में चावल की भूसी अनुमानतः कितनी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) 1. भारत सरकार ने विलायक निस्सारण (सालवेंट एक्सट्रेक्शन) उद्योग को लाइसेंस देने के उपबन्धों से मुक्त कर दिया है जिसमें चावल की भूसी से तेल निकालना भी सम्मिलित है। इसलिए उद्यमी चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए विलायक निस्सारण संयत्र स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है और इसके लिए इन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसैंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

2. बैच किस्म तथा आधुनिक निरन्तर विलायक निस्सारण दोनों ही प्रकार के संयंत्रों का देश में ही निर्माण का प्रबन्ध कर लिया गया है।

3. चावल की भूसी के तेल पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है।

4. यद्यपि 6–6–1966 से मूंगफली के तेल से निकली खली पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया है किन्तु चावल की तेल निकली भूसी को इससे छूट दे दी गई है। यह चावल की भूसी से तेल निकालने के उद्योग के विकास के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन है।

(ग) लगभग 5 लाख मीट्रिक टन भूसी तेल निकालने के लिए उपलब्ध होगी जिसमें 75000 मी० टन प्रति वर्ष के लगभग तेल निकल सकता है।

आयातित मशीनी औजार

1288. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) उद्योग ने उन आयातित पुर्जों पर कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है, जिनके आयात पर विदेशी मुद्रा भी खर्च हुई है और जो इस समय बेकार पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ये पुर्जे क्यों बेकार पड़े हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है; देश में आयात किये गए मशीनी औजारों में से कितने औजारों का उपयोग नहीं हो रहा है, इसका उपयुक्त समय के अन्दर पता लगा सकना व्यावहारिक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के लिये जूते बनाना

1289. श्री० दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या आगरा के जूता निर्माताओं ने राज्य व्यापार निगम के लिये, जिसने रूस से क्रयादेश प्राप्त किया था, जूते बनाने से इन्कार कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Manufacture of Compressors

1290. Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri S. M. Joshi :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that there are some factories in private sector in India for the manufacture of large compressors of 1,000 to 2,000 c. f. m. and these factories have been manufacturing the compressors;

(b) whether Government had banned the manufacture of large compressors eight or nine years ago, and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) One Unit in the private Sector is producing Compressors of 1000 c, f. m. in limited quantities.

(b) The licensing of fresh capacity for the manufacture of compressors of sizes larger than 700 c. f. m. in the private sector has been banned since January, 1964.

(c) The programme of the public sector unit proposed to be put up at Allahabad contemplated manufacture of compressors of large sizes. In view of this, it was considered that there was no scope for creation of further capacity for large sizes of compressors above 700 c. f. m.

रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के कर्मचारी

1291. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय उन लोगों पर लागू किया जायेगा जिन्होंने छः महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है; और

(ग) क्या उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रम तथा भत्ते दिये जायेंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

नारियल जटा पर निर्यात शुल्क

1292. श्री विश्वम्भरम् :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में नारियल जटा तथा इससे बनीं हुई वस्तुओं पर लिए गये निर्यात शुल्क से केन्द्रीय सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) 1967–68 में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी राशि रखी गई है।

(घ) 1966–67 में नारियल जटा उद्योग पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ङ) 1967–68 के आय-व्यय में इसके लिए कितनी राशि रखी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 153.79 लाख रु०

(ख) 175.00 लाख रु०।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में कुल 4 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(घ) 1966-67 में निम्न अनुदान तथा ऋण स्वीकृत किये गये थे :

	अनुदान	ऋण
कायर बोर्ड	10,40,600 रु०	3,00,000 रु०
राज्य सरकार	3,29,000 रु०	6,17,000 रु०

(ङ) 1967–68 के लिये आय-व्ययक में नियत राशियां निम्न प्रकार है ?

	अनुदान	ऋण
कायर बोर्ड	8,20,900 रु०	3,00,000 रु०
राज्य सरकार	4,50,000 रु०	10,00,000 रु०

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर

1293. श्री विरेन्द्रकुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, लिमिटेड, दुर्गापुर का शास्त्री नगर में झरिया धनबाद रोड पर एक प्रदर्शन कक्ष है;

(ख) इस प्रदर्शन कक्ष के रख रखाव तथा किराये पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है;

(ग) क्या यह सच है कि यह प्रदर्शन कक्ष जनता के लिये बन्द रहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रदर्शन कक्ष से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री **(श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) 5,700 रु० प्रतिवर्ष ।

(ग) और (घ) : धनबाद में उसके इर्द-गिर्द कोयले की पट्टी में माईनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रदर्शन कक्ष स्थापित किया गया है । यह कार्य दिवसों को कार्यालय के सामान्य घण्टों में खुला रहता है ।

बिड़ला समवाय समूह को लाइसेंसों का दिया जाना

1294. श्री अदिचन : क्या **औद्योगिक** विकास **तथा समवाय कार्य** मन्त्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या केरल में एक बड़ा उद्योग समूह स्थापित करने के लिये, जो टाइटेनियम स्लांग और टाइटेनियम डयोपिडेक्स के निर्माण के लिए चावरा में पाया जाने वाले इल्मेनाइट के क्षेप पर आधारित होगा, बिड़ला समवाय समूह को कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Aluminium Plant at Koyana

1295. **Shri Mohan Swarup** :
Shri George Fernandes :
Shri Madhu Limaye :
Shri J. H. Patel :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken three years ago **to transfer the** aluminium plant at Koyana run by a private Company to the Bharat Aluminium Company in the public sector;

(b) whether it is also a fact that a target was also fixed for the **production** of 50,000 tons of aluminium by the said plant;

(c) if so, whether the target was achieved; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) A licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, was granted to M/s. Tendulkar Industries (P) Ltd., Bombay, in March, 1960, for the establishment of a new aluminium smelter in the Koyna region of Maharashtra State. Due to financial and other difficulties the licensee could not start work on the project. In view of the failure of the licensee, the Govt. decided in 1964 to take up the project for implementation in the publlic sector. After ensuring that M/s. Vereinigte Aluminium Werke of West Germany would provide the necessary assistance for the project in the public sector, the licence was finally revoked on the 13th Oct., 1965 and in November, 1965 a Government Company, the Bharat Aluminium Company, was formed to execute the project.

(b) It has been decided to have a capacity of 50,000 tonnes per annum of aluminium metal for the proposed plant.

(c) and (d) The cost estimates of the project furnished by the consultants are under examination to determine the economics of the project. A final decision regarding the implementation of the project will be taken shortly by Government in the light of the result of this examination.

Fire in Diesel Store at Katni

1296. Shri Mohan Swarup : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a devastating fire had broken out in a diesel store at Katni (Central Railway) on the 19th April, 1967 resulting in loss of property worth lakhs of rupees;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the cause of the fire ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes. The loss has been estimated at Rs. 12 lakhs approximately.

(b) On 19-4-67, at about 21-50 hours a fire was noticed in the boxes containing heavy spares of diesel locomotives, lying on the platform of New Katni Diesel Loco Stores. These boxes being very heavy and bulky in size, could not be accommodated inside the godown which was already full. The fire was brought under control with the help of the Fire Fighting staff posted at diesel locoshed assisted by diesel loco staff. The Fire Brigade of Ordnance Factory Katni also came to assistance and the fire was fully extinguished by 00-30 hours on 20-4-1967.

(c) The administrative Officers Committee of Enquiry appointed in this connection could not arrive at a definite conclusion and the matter has been referred to the Police authorities for further enquiry.

ऊनी धागे का उत्पादन

1297. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ऊनी वर्स्टेड धागों तथा कपड़े के उत्पादन के लिये चौथी योजना के लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करना चाहती है;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कच्चे माल का आयात करने हेतु कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ऊनी उद्योग अपनी दो शिफ्टों की क्षमता के अनुसार काम करने लगें; और

(घ) क्या सरकार ने इंडियन मेरीनो किस्म की भेड़ों की नस्ल का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) स्वदेशी ऊन के उत्पादन की मात्रा और किस्म में सुधार करने के लिये कृषि विभाग द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनसे आशा है कि अच्छी भारतीय ऊन का संभरण बढ़ जाएगा; और जहां तक आयातित कच्ची ऊन की मांग का सवाल है, देश की विदेशी मुद्रा–सम्बन्धी कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जायगा ।

(ख) स्वदेशी मानव निर्मित रेशों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए, दो पाली कार्य चालन के आधार पर ऊन के लिये प्रति वर्ष लगभग 22 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

(ग) उद्योग में कार्य की पालियों की संख्या कच्चे माल की उपलब्धि पर निर्भर है जो स्वयं विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है । उद्योग के लिये यह भी तरीका है कि वे अपनी कच्चे माल की आवश्यकता में से कुछ के लिये भारतीय ऊन का प्रयोग कर सकें ।

(घ) बढ़िया ऊन देने वाली उत्तम भेड़ों की नस्ल तैयार करने के लिये विदेशी भेड़ों की सहायता से नस्ल सुधारने के प्रयास लगभग कुछ वर्षों से जारी है ।

आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग

1298. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा आस्ट्रेलिया के अधिकारियों द्वारा किये गये तीन दिवसीय संयुक्त सर्वेक्षण में भारतीय दल ने कुछ सहयोग कार्यक्रमों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आस्ट्रेलिया की सरकार ने किन-किन कार्यक्रमों पर विचार करना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : भारत तथा आस्ट्रेलिया के अधिकारियों द्वारा कोई संयुक्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है । सम्भवतः आशय

भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच हुए परामर्शों से है जोकि नई दिल्ली में विदेश मन्त्रालय में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हुए थे। भारत की ओर से भेड़-पालन तथा ऊन उत्पादन इत्यादि कुछ योजनाओं का सुझाव दिया गया था। यह निश्चित किया गया कि ऐसे विषयों पर विशेष योजनाओं के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।

चाय परिषदें

1299. श्री अनिरुद्धन : श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम : श्री एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की मांग बढ़ाने के लिये सरकार ने विभिन्न देशों में कुल कितनी चाय परिषदें स्थापित की हैं;

(ख) वे किन किन देशों में स्थापित की गई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन परिषदों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : सरकार ने कोई चाय परिषद स्थापित नहीं की है। निम्नलिखित देशों में स्थानीय चाय व्यापार ने चाय परिषदें स्थापित की हैं जिनमें भारत तथा श्रीलंका की सरकारों ने भाग लिया है:–

(1) ब्रिटेन
(2) पश्चिमी जर्मनी
(3) स० रा० अमेरिका
(4) कनाडा
(5) आस्ट्रेलिया
(6) न्यूजीलैंड
(7) फ्रांस

आयरलैंड में स्थानीय चाय व्यापार ने एक चाय परिषद स्थापित की है, इसमें केवल भारत सरकार ने भाग लिया है।

(ग)	वर्ष	रुपयों में राशि
	1964-65	13,27,108.76
	1965–66	40,17,077.03
	1966–67	58,19,765.75
		योग 1,11,63,1951.54

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा

1300 श्री दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई तथा अन्य उद्योगों को दी गई विदेशी मुद्रा की तुलना में यह राशि कितनी कम व अधिक है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को 6 जून, 1966 से विदेशी मुद्रा का आवन्टन 353 करोड़ रुपये था इसमें दिनांक 22 दिसम्बर की सार्वजनिक सूचना संख्या 156-आई०टी०सी० (पी० एन०) 66 के अन्तर्गत औद्योगिक एककों द्वारा उपयोग किया गया पूरक आवन्टन भी सम्मिलित है। बड़े पैमाने में उत्पादन करने वाले गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा का 1966–67 में आवन्टन, जिसकी व्यवस्था तकनीकी विकास का महा-निदेशालय करता है, का मूल्य 50 करोड़ रुपये (अवमूल्यन के पश्चात्) था। 1965-66 में आवन्टन 20 करोड़ रुपये था और 1964–65 में (39 करोड़ रुपये अवमूल्यन से पूर्व) था। वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के आवन्टन के हकदार होंगे यदि वे पहले के लाइसेंस के 90 प्रतिशत का साख–पत्र खोल दें या उसके 60 प्रतिशत के मूल्य का माल सीमा-शुल्क से छुड़वा ले।

निरीक्षण निदेशालय

1301 श्री दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय का संगठन किस प्रकार का है, तथा यह क्या कार्य करता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हां श्रीमान। निरीक्षण निदेशालय में कई टोलियां निर्मित की गई हैं, जो दिल्ली. कलकत्ता, बम्बई, कानपुर तथा मद्रास में अवस्थित हैं। मुख्यालय में, निरीक्षण एवं जांच के निदेशक, सम्पूर्ण टोलियों के समस्त प्रभारक हैं। निदेशालय का कार्य, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (4) के अधीन, भारतीय कंपनियों के लेखाओं की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों व कागजों का निरीक्षण करना है।

मुख्य प्रत्यय यह देखना है, कि क्या अधिनियम के अधीन जिन पुस्तकों तथा कागजों का संधारण करना आवश्यक है, उनका संधारण किया जाता है, तथा यदि किया जाता है, तो क्या वह नवीनतम हैं, व कम्पनी के कार्यों की सही व उचित दृष्टि प्रतिबिंबित करते हैं। इन निरीक्षणों से यह प्रकट होता है कि क्या व्यापार का प्रबन्ध तथा कम्पनी का कार्य कम्पनी की संस्था के ज्ञापन एवं अन्तर्नियम और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाता है, तथा क्या कम्पनी के अभिलेख, प्रलेख व वाउचर इस प्रकार निर्मित किये जाते हैं कि वह कम्पनी की परिसम्पति व देयता तथा व्यापार पर सत्य तथा उचित दृष्टि प्रदान करते हैं ।

विभिन्न टोलियों की वर्तमान स्थिति तथा सस्वीकृत संख्या निम्न प्रकार है

निरीक्षण तथा जांच निदेशक (1600-2000 रुपये) **(नई दिल्ली मुख्यालय में)**

नई दिल्ली में		कलकत्ता में		बम्बई में		कानपुर में		मद्रास में	
निरीक्षण के संयुक्त निदेशक (1300–1600 रुपये)	—1	निरीक्षण के संयुक्त निदेशक	— 1	निरीक्षक के संयुक्त निदेशक	-- 1	निरीक्षण के उप-निदेशक	1	निरीक्षण के उप-निदेशक	— 1
निरीक्षण के उप-निदेशक (1100–1400 रुपये)	—2	निरीक्षण के उप-निदेशक	— 2	निरीक्षण के उप-निदेशक	-- 2	निरीक्षण अधिकारी	1	निरीक्षण अधिकारी	— 1
निरीक्षण अधिकारी (700–1250 रुपये)	-- 1	सहायक निरीक्षण अधिकारी	— 3	निरीक्षण अधिकारी	— 1	सहायक निरीक्षण अधिकारी	1	सहायक निरीक्षण अधिकारी	— 2
सहायक निरीक्षण अधिकारी (400–950 रुपये)	-- 1	आशुलिपिक	— 4	सहायक निरीक्षण अधिकारी	— 3	आशुलिपिक	2	आशुलिपिक	— 2
आशुलिपिक (210–425 रुपये)	— 2	आशु टाइप कर्त्ता	— 3	आशु लिपिक	— 4	आशु टाईप कर्त्ता	2	आशु टाईप कर्त्ता	— 2
चपड़ासी	— 2	चपड़ासी	— 2	आशु टाईप कर्त्ता	-- 3	चपड़ासी	1	चपड़ासी	1
				चपड़ासी	-- 2				

M/s. Golcha Properties (P) Ltd. Delhi

1302. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 255 on the 31st March, 1967 and state :

(a) Whether any judgment has been delivered by the High Court of Rajasthan in the matter pending before them regarding the creditors of M/S. Golcha Properties (P) Ltd. Delhi, and which was to be heard by them on the 4th April, 1967; and

(b) If so, the nature thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)) : (a) and (b) The hearing fixed on April 4, 1967 was adjourned to April 17 and again to April 27. The company filed a revised scheme under section 391 of the Companies Act. After hearing the parties, the Hon'ble High Court allowed time till May 3, for filing objections. On the 3rd May, 1967, the Court passed an order for convening a meeting of the creditors of the company on 28th June, 1967 at its registered office at Jaipur to consider and approve the revised scheme.

Running Staff Attached to Dining Cars

1303. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to **state** :

(a) whether it is a fact that running staff such as Bearers, Shunters, Checkers, Managers of the dining cars in the UP and Down express trains on the Western and Central Railways have to be on duty for 25 to 30 hours continuously;

(b) whether it is also a fact that these employees are not given any relief or rest during their duty hours.

(c) if so, the strength of the running staff put on duty in such trains; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Supply of Minerals to Centre by Bihar Government

1304. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Minister of Bihar has stated that the State would suspend the supply of minerals to the Centre if the Central Government did not allow them to import foodgrains from other States (as reported in the Nav Bharat Times, dated 1st April, 1967); and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Steel, Mines and Metals, (Dr. Channa Reddy) : (a) Central Government has no information on this subject.

(b) Does not arise.

हरियाना में कच्चे लोहे का कारखाना

1305. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाना में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक चालू हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : इन्टेंट पत्र की अवधि 31 अक्तूबर 1967 तक बढ़ा दी गई है। सरकार की सामान्य नीति के अनुसार प्रायोजना अधिकारियों से कहा गया है कि वे देश में बनने वाले उपकरणों का ही प्रयोग करें। अभी तक उनके प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं।

हरियाणा में खनिज सर्वेक्षण

1306. श्री राम किशन गुप्त : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना राज्य में खनिज सर्वेक्षण करने सम्बन्धी कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) राज्य में सामान्य भौमिक सर्वेक्षण तथा खनिज पदार्थों के प्रारम्भिक अनुमान का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और इससे कुछ खनिज पदार्थ प्रकट हुए हैं जिनमें लौह अयस्क और चूना पत्थर आर्थिक महत्व के हैं। कैलसाइट, तांबा अयस्क, फैल्सपार, मिट्टी, स्लेट, स्फटिक और कांच वाले रेत रक्त-मणि और साल्टपीटर भी इस राज्य में पाए गये हैं। लोह अयस्क के लिए महिन्द्रगढ़ में व्यधन द्वारा और आगे विस्त्रित अन्वेषण प्रगति पर है।

इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड, कलकत्ता

1307. डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारी संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस उद्योग के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मेसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के लिये अखिल भारतीय इन्डियन आक्सीजन ऐण्ड एसिटिलीन कर्मचारी संघ का एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की क्षमता को प्रयोग में लाना

1308. श्री वीरेश्वर कालिता :
डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की क्षमता का प्रयोग पिछले तीन वर्षों में अधिक हुआ है अथवा कम;

(ख) प्रत्येक कारखाने में पिछले पाँच वर्षों में कितने प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया गया; और

(ग) क्षमता का कम प्रयोग होने के कारण देश में इस्पात की उत्पादन लागत पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अनुसार 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में विक्रेय इस्पात की क्षमता का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ा है। इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अनुसार वहां पर इस अवधि में उपयोग कम हुआ है।

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अनुसार पिछले पांच वर्षों में प्रतिशत क्षमता का उपयोग निम्नलिखित है—

	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
टाटा	88.00	93.75	104.51	104.52	104.52
इंडियन आयरन	99.39	101.23	93.33	90.40	88.65

(ग) इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में इस्पात की प्रतिटन उत्पादन लागत में क्रमशः 8.77 रुपये, 16.72 रुपये और 20.36 रुपये की वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में फरो-क्रोम कारखाना

1309. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फैरो-क्रोम कारखाना चालू हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1969 में।

Import of Sport Goods

1310. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 251 on the 31st March, 1967 and state :

(a) whether Government have since taken any decision in regard to the applications received for the import of sport goods under the present import policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons to allow such imports in view of the shortage of foreign exchange ?

The Minister of commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) to (c) : Import of sport goods is not permissible under the import policy. An exception is made in respect of a few items not manufactured indigenously, and their import is allowed in small quantities to recognised sports institutions.

रेलवे के लेखा कार्यालयों में राजपत्रित पद

1312. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीनों से काम करवाने की व्यवस्था आरम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे के प्रत्येक लेखा कार्यालय में कितने राजपत्रित पद बनाये गये हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिये मशीन आपरेटरों के कितने नये पद बनाये गये हैं ।

(ग) मशीनों से काम करवाने की व्यवस्था आरम्भ की जाने के परिणामस्वरूप कितने पद (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) समाप्त कर दिये गये हैं; और

(घ) इस व्यवस्था पर कुल कितनी राशि खर्च आयेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे विभाग में मशीनों से हिसाब लगाने की पद्धति

1313. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों से हिसाब किताब लगाने की पद्धति का प्रयोग 1926 में किया गया था ;

(ख) क्या यह पद्धति 1930 में त्याग दी गई थी, क्योंकि यह पद्धति जटिल, त्रुटिपूर्ण तथा बहुत मंहगी थी;

(ग) क्या यह सच है कि इस पद्धति के निदेशक ने अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया था कि पश्चिम देशों, अर्थात् जर्मनी, इंगलैंड और कनाडा ने रेलवे में इस पद्धति के बाहरी आधार (आउटवर्ड बेसिस), को नहीं अपनाया था; और

(घ) यदि हां, तो अब मशीनों से हिसाब लगाने की पद्धति आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 1938 में मशीनों का प्रयोग बन्द कर दिया गया था, लेकिन पुराने काग़ज़ात न होने के कारण इसके ठीक ठीक कारण नहीं बताये जा सकते ।

(ग) जी हां, इंगलैण्ड और कनाडा की रेलों के बारे में यह सच है । निदेशक को जर्मनी की रेलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने का मौका नहीं मिला था ।

(घ) इंगलैण्ड और कनाडा की रेलों में हिसाब किताब रखने की पद्धति भारतीय रेलों की पद्धति से सर्वथा भिन्न है । सभी सम्बन्धित बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और 'अग्रेषित आधार' पर हिसाब-किताब रखने की पद्धति लागू की गयी ताकि जारी किये गये सभी इंवायसों के हिसाब किताब विशेष रूप से 'भाड़ा देय' यातायात के हिसाब-किताब की तुरन्त और पूरी पूरी जांच की जा सके । ऐसा इसलिये भी किया गया है क्योंकि गन्तव्य स्टेशनों से मिलने वाली रिपोर्टों के आधार पर 'भाड़ा दत्त यातायात' का जो हिसाब किताब

रखा जाता था, उससे प्रारम्भिक स्टेशनों द्वारा वसूल की गयी रकम और उसके हिसाब-किताब में सीधा और तुरन्त मेल नहीं बैठता था।

हिसाब करने वाली मशीनों का किराया

1314. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1964 से लेकर आज तक अमरीकी आई० बी० एम० कम्पनी को हिसाब करने वाली मशीनों के किराये के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ख) 1964 से लेकर मार्च, 1967 तक इन मशीनों के रख रखाव तथा मरम्मत के लिये विदेशी मेकैनिकों तथा अधिकारियों को कितनी राशि दी गई;

(ग) हिसाब करने वाली इन मशीनों के लिये अपेक्षित विशेष पेपर कार्ड, कार्बन पेपर रोल्स तथा अन्य महत्वपूर्ण लेखन सामग्री खरीदने पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उपरोक्त भागों (क), (ख) और (ग) के सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 74.80 लाख रुपये।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) 29.81 लाख रुपये।

(घ) कुछ नहीं, क्योंकि अदायगी रुपयों में की जाती है।

रेलवे विभाग में मशीनों से हिसाब कराने की प्रणाली आरम्भ करने के परिणामस्वरूप रेलवे की आय में कमी

1315. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 1964 से रेलवे के यातायात लेखा कार्यालयों में मशीनों से हिसाब कराने की प्रणाली आरम्भ करने के बाद रेलवे की आय में लगातार कमी होती जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं।

औद्योगिक उत्पादन

1316. श्री मधु लिमये : श्री एस्थोस :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री उमानाथ :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री विश्वनाथ मेनन :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री अब्राहम : श्री अनिरुधन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवमूल्यन के पश्चात् औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं;

(ख) क्या आयात के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनाने पर भी उत्पादन मन्द रहा है;

(ग) उत्पादन मन्द रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात की उत्पादन लागत और कीमत

1317. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में निर्मित भारतीय इस्पात की ऊंची उत्पादन-लागत ऊंची कीमत की ओर दिलाया गया है;

(ख) भारतीय इंजीनियरी उद्योगों द्वारा तैयार माल के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और

ग) इस्पात की उत्पादन लागत कीमत को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने र है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख) : अगस्त, 1965 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री हरि कृष्ण मेहताब थे । समिति के निर्देश-पद-इस्पात की उत्पादन लागत का विस्तृत रूप से अध्ययन करना, लागत के सभी पहलुओं का विश्लेषण करना, मूल्यों में वृद्धि के कारणों का

पता लगाना तथा लागत में कमी करने के बारे में आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देना था। समिति के विचार में भारत में निर्मित इस्पात के निर्माणों वाह्य मूल्य दूसरे देशों में निर्मित इस्पात के मूल्यों की तुलना में बहुत बुरे नहीं हैं।

इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:—

(1) संचालन–प्रक्रियाओं में सुधार करना।

(2) अधिकाधिक उत्पादन करना,

(3) कच्चे माल, सेवाओं आदि के लिए मान निर्धारित करना तथा इस बात की व्यवस्था करना कि कच्चे माल और सेवाओं का पहले से अच्छा उपयोग हो सके।

(4) उपलब्ध रोलिंग समय के उपयोग में सुधार करना।

(5) स्क्रेप की प्राप्ति में सुधार करना जिससे इस्पात पिघलाने वाले कारखाने के लिए स्क्रेप के क्रय में कमी हो सके।

(6) कोक भट्टियों में कोक के चूरे का कम मात्रा में प्रयोग तथा सारे नट कोक का धमन भट्टियों में प्रयोग

(7) धमन भट्टियों में कोक के उपयोग को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न।

(8) खुले मुंह की भट्टियों में आक्सीजन इन्जैक्शन और

(9) कोक भट्टियों और दूसरी भट्टियों से निकलने वाली गैस का पूर्ण उपयोग।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

1318. श्री मधुलिमये **डा० राम मनोहर लोहिया**
श्री स० मो० बनर्जी **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड की स्थापना में लेकर अब तक उसके मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है; और

(ग) इसके असाधारणतः अधिक प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में आविष्कार करने की प्रतिभा रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने, उनमें आविष्कार की भावना उत्पन्न करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए 1960 में जो आविष्कार

संवर्धन बोर्ड स्थापित किया गया था उसने 1966–67 तक 248 आविष्कारों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 4,10,629 रुपये मंजूर किये हैं और 134 आविष्कारों के लिए पुरष्कारों के रूप में 1,17,950 रुपये वितरित किये हैं। आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड द्वारा बढ़ावा दिये गये कई आविष्कारों का वाणिज्यिक आधार पर लाभ उठाया गया है।

बोर्ड ने हाल ही में पुरष्कार देने के लिए प्रतियोगिताएं प्रारम्भ की हैं जो वर्ष में दो बार अर्थात् 26 जनवरी और 15 अगस्त को की जाती है।

बोर्ड ने इंवेशन इन्टेलीजेस नामक जो पत्रिका अगस्त 1965 से निकालना प्रारम्भ की थी उसके इस समय तक 500 सदस्य हो चुके हैं और यह पत्रिका तकनीशनों, शोध कर्त्ताओं और विद्यार्थियों में बड़ी लोकप्रिय हो गई है।

बोर्ड ने आविष्कर्त्ता और उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से एक औद्योगिक पुस्तकालय में साहित्य को क्रमानुसार लगाने का एक अनुपम तरीका भी निकाला है जिसे औद्योगिक दशमिक वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। बोर्ड की एक ऐसी भी योजना है जिससे आविष्कारों के संवर्द्धन में औद्योगिक कारखाने भाग ले सकें।

(ख) अभी हाल ही में आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड को नये स्थापित किये गये 'आयात स्थानापन्न बोर्ड' के कार्य के साथ सम्बद्ध किया गया है। इस बोर्ड ने आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन की दिशा में कोई विशेष रूप से काम करना प्रारम्भ नहीं किया है, यद्यपि बोर्ड द्वारा बढ़ावा दिये गये कई आविष्कारों से विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। तथापि, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इन आविष्कारों से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी।

(ग) कुल व्यय में प्रशासन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत 1964-65 में 51.6 प्रतिशत से घटकर 1965–66 में 39 प्रतिशत रह गया है। ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित नई योजनाओं को प्रारम्भ करने से 'आविष्कारों के संवर्द्धन' पर होने वाले व्यय की तुलना प्रशासन पर होने वाले व्यय के और कम हो जाने की आशा है।

इस्पात का मूल्य

1319. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय इस्पात के नियंत्रित मूल्यों तथा पिछले छः महीनों में लन्दन मैटल बुलेटिन में प्रकाशित औसत मूल्य में कितना अन्तर है,

(ख) इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस सस्ते इस्पात का उपयोग आन्तरिक मांग को पूरा करने वाली वस्तुओं या उत्पादन के लिये न किया जाये और

(ग) निर्यात उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय इस्पात के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि 1–5--1967 से सभी प्रकार के इस्पात पर से नियंत्रण हटा दिया गया है । इस्पात की किस्म के अनुसार वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भारतीय मूल मूल्य का अंतर 30 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति टन तक है ।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार भारतीय मूल मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अंतर की प्रतिपूर्ति निर्यात करने तथा संबंधित निर्यात के कागजात की जांच कर लेने के पश्चात ही की जायेगी ।

(ग) निर्यात किये जाने वाले माल में काम आने वाली कच्ची सामग्री पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की वापसी के साथ साथ, जहां कहीं उचित समझा जाता है–भिन्न भिन्न माल के लिये नकदी सहायता भी दी जाती है । सरकार ऐसे निर्यातकों को चयन के आधार पर बाहर से कच्चा माल, पुर्जे और अन्य पूंजीगत माल प्राप्त करने में भी सहायता करती है ।

दिल्ली–मद्रास जनता और सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ लगाये जाने वाले डिब्बे

1320. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य शहरों से विजयवाड़ा के उत्तर भारत के अन्य शहरों से विजयवाड़ा के उत्तर में आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती नगरों को जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार दिल्ली-मद्रास जनता तथा सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियों में विशाखापतनम् तक सीधे जाने वाले डिब्बे, जो उपयुक्त जंकशनों पर मद्रास-हावड़ा मेल तथा/अथवा हैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस गाड़ी में जोड़ दिये जायें, लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) यातायात सम्बन्धी औचित्य की कमी और गाड़ियों में स्थान का न होना ।

जी० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1321. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट पर विजयवाड़ा के उत्तर में स्थित नगरों के लिए दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की बड़ी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुये सरकार विजयवाड़ा में जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी के पहुंचने के समय को बढ़ाने की वांछनीयता का

विचार कर रही है, ताकि मद्रास-हावड़ा मेल अथवा हैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस गाड़ियों के समय से उसका मेल हो सके, जैसाकि इस समय दिल्ली-मद्रास जनता और सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : 18 अप दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस और 22 अप नयी दिल्ली-मद्रास वातानुकूल/सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियां 4 डाउन मद्रास-हवड़ा डाक और 16 डाउनहैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस गाड़ियों से विजयवाड़ा में मेल लेती हैं और सीधे यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं। 16 अप नयी दिल्ली-मद्रास जी०टी०एक्सप्रेस और 4 डाउन मद्रास-हवड़ा डाक या 46 हैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस गाड़ियों के मेल लेने की व्यवस्था करने पर उनके निर्धारित समय में भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे जो यातायात और परिचालन तथा कर्षण के स्वरूप की दृष्टि से इस समय व्यावहारिक ही हैं।

कपड़े के मूल्य

1322. श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री नि० रं० लास्कर

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों में काम करने के दिनों की संख्या कम करने से सम्बन्धित विधेयक के पारित हो जाने के बाद हाल ही में कपड़े के मूल्यों में आम तौर पर वृद्धि हुई है और

(ख) यदि हां, तो कपड़े के मूल्य घटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : कपास के उपलब्ध सम्भरण में कमी के परिणामस्वरूप मशीनों के चलाने में अनिवार्यत: कमी करनी पड़ी और कपास तथा मजदूरी की लागत बढ़ने के कारण कपड़े के दामों में कुछ वृद्धि हुई है। कपास तथा मजदूरी की लागत में वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल, 1967 से मिल के बने कपड़े (अर्थात धोती, साड़ी, कमीज का कपड़ा, लट्ठा तथा ड्रिल) की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में 4–1/2 प्रतिशत की वृद्धि की गई। मिल के बने अन्य कपड़ों की किस्मों के मूल्य नियंत्रित नहीं हैं। इन किस्मों के सम्बन्ध में भी यद्यपि मूल्य बढ़े हैं तो भी यह देखा गया है कि नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात से बहुत ज्यादा इसके मूल्य नहीं बढ़े हैं।

चूंकि कपास के मूल्य का प्रभाव कपड़े के मूल्य पर सीधा पड़ता है, सरकार ने मूल्यों को यथासंभव नियत मूल्यों के इर्दगिर्द रखने के लिये, लाने लेजाने पर नियन्त्रण, स्टाक पर नियंत्रण, उधार पर नियंत्रण और कपास के अधिग्रहण जैसे कई उपाय किये हैं। आयातों को बढ़ा कर कपास के सम्भरण में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रेलवे सैलून

1325. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे, रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये कितने और किस प्रकार के सैलून उपलब्ध हैं; और

(ख) इन सैलूनों के संधारण पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे अधिकारी वास्तव में सैलून का प्रयोग नहीं करते। वे काम के कुशल परिचालन के लिए केवल निरीक्षण डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। सैलून केवल भारत सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे मन्त्री-मण्डल स्तर के मन्त्री, राज्य मन्त्री, थल-सेना अध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य मुख्य न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय, विदेश सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, रेलवे बोर्ड के सदस्य जो भारत सरकार के पदेन सचिव हैं, आदि। निरीक्षण डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है।

बड़ी लाइन पर लगभग 121 अठपहिये, 18 छः पहिये और 412 चौपहिये निरीक्षण डिब्बे मीटर लाइन पर 167 अठपहिये 45 छः पहिये और 242 चौपहिये निरीक्षण डिब्बे; और छोटी लाइन पर 23 अठपहिये और 3 चौपहिये निरीक्षण डिब्बे।

(ख) निरीक्षण डिब्बों के अनुरक्षण की लागत का अलग हिसाब नहीं रखा जाता। फिर भी, 1965-66 में कोचिंग वाहन (चौपहियों के हिसाब से) की मरम्मत और अनुरक्षण की औसत लागत इस प्रकार थी:-

बड़ी लाइन : लगभग 3,380 रुपये।
मीटर लाइन : लगभग 2,117 रुपये।

खुरदा रोड स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

1326. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरदा रोड़ स्टेशन पर तथा खुरदा डिवीजनल मुख्यालय में नियुक्ति रेलवे कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है;

(ग) इस समय प्रत्येक श्रेणी के लिये कितने कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं;

(घ) क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिये नये क्वार्टर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस कार्य के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जिन कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है उसमें से श्रेणी तीन के 56.5 प्रतिशत और श्रेणी चार के 60 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए खुरदा रोड में रेलवे क्वार्टरों की व्यवस्था कर दी गई है । इनमें मण्डल प्रधान कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल हैं ।

(ख) इस स्टेशन पर सभी सारभूत कर्मचारियों को आवास देने के लिए श्रेणी तीन के कर्मचारियों के लिए 459 अतिरिक्त क्वार्टर और श्रेणी चार के लिए 635 अतिरिक्त क्वार्टरों की जरूरत है ।

(ग) इस समय खुर्दा रोड पर श्रेणी तीन के कर्मचारियों के लिए 597 और श्रेणी चार के लिए 955 क्वार्टर उपलब्ध हैं ।

(घ) प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध होने वाली राशि को देखते हुए क्वार्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों का उत्तरोत्तर निर्माण किया जायेगा । 1967–68 में श्रेणी तीन के कर्मचारियों के लिए टाइप II के 20 यूनिट और श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिए टाइप I के 24 यूनिट क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया गया है ।

(ङ) 1967–68 में 1.58 लाख रुपये ।

कपड़े के मूल्य

1327. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० न० तिवारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों के कपड़े का मूल्य 4–1/2 प्रतिशत बढ़ा दिये जाने के बावजूद भी मिल मालिक सन्तुष्ट नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अहमदाबाद मिल संघ के अध्यक्ष ने 15 अप्रैल, 1967 को यह कहा था कि सरकार को मिल के काड़े के मूल्य नियत करने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाने चाहियें अन्यथा कपड़ा उद्योग समाप्त हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उद्योग से इस आशय के आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अहमदाबाद मिल मालिक संघ के अध्यक्ष के नाम से एक वक्तव्य पत्रों में भी आया था जिसका आशय यह था कि वृद्धि पर्याप्त नहीं है ।

(ग) सरकार का विचार है कि कपड़े की नियन्त्रित किस्मों के माल से निकलते समय के मूल्यों में 4–1/2 प्रतिशत की वृद्धि से एक ओर तो ऐसे कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि तथा दूसरी ओर यथासंभव न्यूनतम मूल्यों पर उपभोक्ता को वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कपड़ों की पूर्ति सुनिश्चित करने की मुख्य आवश्यकता के मध्य न्यायपूर्ण संतुलन होता है ।

Collision at Brajarajnagar Railway Station

1328. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 771 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether any action has been taken against the defaulting driver in connection with the enquiry into the collision of two railway trains at Brajarajnagar station; and

(b) if not, the additional time likely to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The driver held responsible for the accident has been removed from service.

उप्पल (केरल) में डाक गाड़ियों का रुकना

1329. श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उप्पल (केरल) तथा उसके आसपास के गांवों के लोगों की ओर से कोई सामूहिक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कान्नानूर जिले में उप्पल में डाक गाड़ियां रुकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले मे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उप्पल स्टेशन पर इस समय जितना यातायात होता है वह अधिकांश कम दूरी का होता है और उसकी आवश्यकता इस स्टेशन पर ठहरने वाली छः जोड़ी गाड़ियों से जिनमें नं० 29/30 मालावार एक्सप्रेस भी शामिल है, पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है। उप्पल स्टेशन पर इस समय लम्बी दूरी का यातायात इतना कम है कि उसके लिए यहां नं० 1/2 मद्रास-मंगलूर डाक गाड़ियों के ठहराने का औचित्य नहीं है ।

Theft in Bhopal—Ahmedabad Train

1330. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person has been arrested on a charge of stealing goods by breaking through a wagon in Bhopal—Ahmedabad train as reported in the Hindustan dated the 3rd April, 1967;

(b) whether it is also a fact that a gang is operating in running trains on the Ratlam Ujjain section of the Western Railway for the purpose; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, a theft was committed on the Ujjain-Bhopal Sector between Tarana Road and Maski stations in Ahmedabad-Bhopal train on the night of 21/22-3-1967, involving four cases of tea valued at Rs. 460/- One Ismail Khan S/o Mehtab Khan of Ujjain was arrested and the entire stolen property was recovered. The case is under trial in the court of the Railway Magistrate, Indore. The case is sub-judice.

(b) No.

(c) Does not arise.

अल्वाये रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बे

1331. **श्री एस्थोस** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैराम्बूर की केरल आरा मशीन मालिक संस्था की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अल्वाये रेलवे स्टेशन पर इमारती लकड़ी ले जाने के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) उच्च प्राथमिकता वाले यातायात, जैसे अनाज, उर्वरकसीमेंट आदि जिसके लिए मांग बहुत अधिक है, कि निकासी के लिये दिये गये वचन के अनुरूप इमारती लकड़ी और लकड़ी के सामान जैसे गैर प्राथमिकता वाले यातायात के परिवहन के लिए माल डिब्बों की यथासंभव सप्लाई को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी से 25 मई, 1967 तक की अवधि में अल्वाये स्टेशन पर इमारती लकड़ी और लकड़ी के सामान से 343 माल डिब्बे लादे गये थे।

काली मिर्च के व्यापार में सट्टे बाजी

1332. **श्री एस्थोस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से काली मिर्च के व्यापार में सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार काली मिर्च का राज्य व्यापार आरम्भ करने का भी है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) पिछले दो वर्ष की अवधि की मूल्य प्रवृतियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने से पता लगता है कि काली मिर्च के व्यापार में वायदे के सौदों से काली मिर्च के उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाएं

1333. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सागर, नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा; और सियोनी जिलों में वन, खनिज तथा इस्पात पर आधारित उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त सम्भावना है, जिससे ग्रामीणों तथा आदिम जाति के लोगों और पूर्वी पाकिस्तान तथा बाहर से आये अन्य भारतीयों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है; क्या सागर, नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा और सियोनी जिलों में से होकर गुजरने वाली ललितपुर सागर, नरसिंहपुर-सियोनी-गोंडिया रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो इसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई

1334. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन, केन्द्रीय रेलवे, को सिंगरी नदी से पानी सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या रेल विभाग ने वर्ष 1966 और 1967 में इस नदी पर बांध बनाया था जिससे रेलवेस्टेशन पर पानी सप्लाई किया जा सके;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा बनाये गये बांध के कारण उस नदी का पानी नीचे नहीं जा सकता और इसके फलस्वरूप अप्रैल, 1966 तथा फरवरी, 1967 में यह नदी सूख गई जिसके कारण नदी के निचले भाग पर रहने वाली जनता तथा पशुओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा;

(घ) क्या यह भी सच है कि बांध बनाने के कारण नदी का पानी रुक गया और गंदा हो गया, जिसके फलस्वरूप वह पीने के योग्य भी नहीं रहा; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । 1966 और 1967 में इस नदी पर एक अस्थायी बांध बनाया गया था ।

(ग) जी नहीं । पिछले दो मानसून के समय वर्षा न होने के कारण, न कि बांध बनाने से नदी सूख गयी यद्यपि पानी के बहाव के लिए नरसिंहपुर के कलक्टर की सलाह से निकास की व्यवस्था की गई थी ।

(घ) जी नहीं । पानी गंदा नहीं है और यह रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में नारियल जटा बनाने वाले उद्योग

1335. श्री अब्राहम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के तटीय क्षेत्रों में नारियल जटा बनाने के उद्योग आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : कायर बोर्ड, जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, कालावूर, जिला ऐलेप्पी (केरल) में कायर की चटाइयों के उत्पादन के लिए एक शक्तिचालित करघा कारखाना स्थापित कर रहा है। केरल की राज्य सरकार का भी तटवर्ती क्षेत्रों में कायर उत्पादन कारखाने प्रारम्भ करने का विचार है परन्तु इन कारखानों के लिए अभी तक स्थान निश्चित नहीं किये गये हैं ।

Export of Electric and Diesel Locomotives

1336. Shri S. C. Samanta : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of electric and diesel locomotives manufactured in India which are being exported to foreign countries alongwith the names of those countries;

(b) whether the demand of export is fully met; if not, the percentage of demand not being met and the steps being taken to meet the full demand of export;

(c) whether only the surplus locomotives left after meeting the demands of the country are being exported; and

(d) whether a statement showing the details of the wagons and coaches exported from our country will be placed on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Manufacture of electric and diesel locomotives in India is still in a developmental stage with a fairly high import content. Due to foreign exchange difficulties, the production has to some extent been controlled and at this stage the entire production has been ear-marked for Indian Railways. With greater expected availability of indigenous components, the production is likely to be stepped up in the near future when the question of tendering against foreign tender enquiries, not made so far, could be considered.

(d) The following exports have been effected so far.

Coaching Stock :

2 passenger bogies to Thailand valued at Rs. 47,130/-.

Wagon Stock :

2 prototype wagons to Hungary (under despatch).

480 wagons to East Africa valued at Rs. 1.57 Crores.

The following orders have also been secured and are under execution.

33 coaches to Burma valued at Rs. 59.33 lakhs.

500 wagons to Hungary valued at Rs. 1.62 Crores.

40 Tank wagons to Ceylon valued at Rs. 31 lakhs.

Rail Link Between Hajipur and Balmiki Nagar

1337. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have ever considered linking Hajipur with Balmiki Nagar Railway station by direct rail link;

(b) if so, whether any preliminary work has been undertaken in this connection; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no station called 'Balmiki Nagar'. It is, therefore, not clear as to which rail link has been asked for by the Hon'ble Member. However, there is no proposal at present to construct any new line taking off from Hajipur station of the North Eastern Railway.

(b) and (c) Do not arise.

Transfer of Railway Guards on Western Railway

1338. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Guards of Western Railway have been experiencing a lot of difficulties in regard to their residences etc. due to their periodical transfer;

(b) whether it is also a fact that due to their transfer, the education of their children is dislocated and they have to lose one year on account of their shifting to another school; and

(c) if so, the action taken to remove their difficulties ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Guards have been representing their difficulties due to periodical transfers.

(b) No Periodical transfers are ordered at the close of the school session to avoid dislocation of education of children.

(c) Transfers are kept down to the minimum.

मैसूर राज्य में इंगलदल में खानों की खोज

1339. **श्री मुहम्मद इमाम : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इंगलदल चितुर दुर्ग में कब से नीला थोथा (कौपर सल्फेट) और सोना मक्खी (पाइरेट) की खानों की खोज की जा रही है;

(ख) अब तक इस कार्य पर कितना धन व्यय हो चुका है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में उपलब्ध अयस्क की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) सन् 1939 और 1949 के मध्य में मैसूर राज्य के भूवैज्ञानिक विभाग ने पहली बार इंगलदहालु के पाइराइट और

नीला थोथा के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया। इसके बाद सन् 1951 में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने भूभौतिक सर्वेक्षण किये। अन्वेषण का यह कार्य मैसूर के भूवैज्ञानिक विभाग द्वारा विस्तृत व्यधन करके फिर आगे ले जाया गया।

सन् 1957–58 में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उस क्षेत्र में आधुनिक तरीकों से विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने अन्वेषण के रूप में व्यधन कार्य किया। सन् 1966–67 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने इंगलद हालू क्षेत्र के साथ लगने वाले क्षेत्र में कुछ प्रारम्भिक कार्य भी किया है।

(ख) ऐसे अन्वेषणों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा खर्चे का कोई अलग लेखा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) तांबा अयस्क के संचयों का अनुमान एक मिलियन मीट्रिक टन और पाइराइट के भंडार का अनुमान तीन मिलियन मीट्रीक टन है।

झज्झर तथा जींद के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

1340. **श्री रणधीर सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करने वाली जनता की सुविधा के लिये, जिस रेलवे फाटकों के बन्द हो जाने पर घण्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, (1) हरियाणा राज्य में दिल्ली सोनीपत रोड के पारपथ पर (2) जींद नगर के रेलवे पारपथ तथा (3) झज्झर रोड़, रोहतक के पारपथ पर ऊपरी पुलों के निर्माण अथवा कोई अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रोहतक, जींद और सोनीपत में वर्तमान समपारों की जगह ऊपरी/नीचले सड़क पुल बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार रेल प्रशासन किसी भी वर्तमान व्यस्त समपार की जगह। ऊपरी निचला सड़क पुल तभी बनाते हैं जब उसे बनाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की गयी हो और साथ ही राज्य सरकार सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए तैयार हों। सम्बन्धित राज्य सरकार से अभी तक इन समपारों में से किसी भी समपार की जगह सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं मिला है।

रेलवे के कुली

1341. **श्री बलराज मधोक :**

श्री हरदयाल देवगुण : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कुलियों के कल्याण और सुरक्षा के लिये स्वतन्त्रता के बाद क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) लाइसेंस शुल्कों के रूप में प्रति वर्ष रेलवे कुलियों से इकट्ठे किये जाने वाले लाखों रुपयों को किस काम में खर्च किया जा रहा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लाइसेंसदार भारिक, जो 1947 से पहले आमतौर पर ठेकेदारों की मार्फत नियुक्त किये जाते थे, अब सीधे रेलवे द्वारा लाइसेंस देकर नियुक्त किये जाते हैं ताकि उन्हें इस बात का विश्वास रहे कि जब तक उनका काम और सामान्य आचरण संतोषजनक रहेगा तब तक वे अपना काम करते रहेंगे।

उनके कल्याण के लिए जो और काम किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

(i) लाइसेंसदार भारिकों को, केवल स्वयं के लिए, बहिरंग रोगी के रूप में निःशुल्क डाक्टरी चिकित्सा दी जाती है; और

(ii) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर द्विदलीय समितियां बनायी जाती हैं।

हाल ही में रेलों द्वारा भारिक प्रभारों पर पुनर्विचार किया गया है और जहां कहीं आवश्यक था दरें बढ़ा दी गयी हैं।

(ख) लाइसेंस फीस की जो रकम इकट्ठी की जाती है वह पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर आने वाले खर्च और जहाँ कहीं रेलों द्वारा वर्दियां दी जाती हैं वहां उनको सप्लाई पर खर्च की जाती है। लाइसेंस फीस "न लाभ न हानि" के आधार पर केवल उपर्युक्त खर्च को पूरा करने के लिए निश्चित की जाती है।

चितरंजन लौकोमोटिव वर्कशाप के रेलवे कर्मचारी

1342. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के किन-किन कर्मचारियों को राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत 1960 से बरखास्त किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त आदेश में संशोधन करने का है जिससे बरखास्त शुदा व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर जा सकें ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) किसी को बर्खास्त नहीं किया गया, लेकिन श्री शम्भू नाथ डे नामक केवल एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया।

(ख) जी नहीं।

रेलवे के कुशल श्रमिकों के वेतन मान

1343. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में कुशल श्रमिकों की दो श्रेणियां हैं, एक वह जिसमें

खलासियों (अकुशल श्रमिकों) में से भरती की जाती है तथा दूसरी वह जिसमें व्यवसाय के प्रशिक्षुओं में से (5 से 3½ वर्ष तक के प्रशिक्षण के बाद) सीधे नियुक्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों श्रेणियों के श्रमिकों का वेतनमान समान है;

(ग) क्या कई वर्षों के प्रशिक्षण तथा किये गये अतिरिक्त खर्चे को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार व्यवसाय के प्रशिक्षुओं में से नियुक्त किये जाने वाले कुशल कर्मचारियों को बड़ा वेतनमान देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) रेलवे में दक्ष श्रमिकों की केवल एक ही श्रेणी है, अर्थात्, 110 रु०–3–131–4–143–दक्षता रोध–4–171–दक्षता रोध–4–175–5–180 और इस श्रेणी के पद उन दस्तकार शिक्षकों द्वारा भरे जाते हैं जो सीधे भर्ती किये जाते हैं और "बेसिक ट्रेड्समेन"। अर्धदक्ष श्रमिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। दस्तकार शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने बाद उन्हें दक्ष कर्मचारियों के रूप में भेज दिया जाता है। दक्ष श्रमिकों के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले "बेसिक (ट्रेड्समेन")। अर्वदक्ष श्रमिकों को विहित दक्ष दस्तकार की परीक्षा पास करनी पड़ती है। दक्ष कर्मचारियों दो वेतनक्रम, एक सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिये और दूसरा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के लिये, देने का कोई औचित्य नहीं है जबकि दक्ष दस्तकारी में कार्य और जिम्मेदारियों में कोई अन्तर नहीं है।

पटसन की कमी

1344. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हमारा पटसन उद्योग पटसन की कमी के कारण भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी हो रही है; और

(घ) निर्यात। नियति से आय में कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) देश में जूट की लगातार तीन फसलें खराब हो जाने के कारण उद्योग को अपनी रेशे की आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई रही है।

(ख) देश में जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किये गये कई उपायों के अतिरिक्त, स्थानीय पूर्ति तथा मांग के मध्य अन्तर को पूरा करने के लिये कच्चे जूट के आयात के लिये उदारतापूर्वक अनुमति दी जा रही है।

(ग) 1966-67 (अप्रैल-जनवरी) में जूट के माल का निर्यात 619,500 मे० टन हुआ जो 1965-66 की उसी अवधि में हुए 768,400 मे० टन के निर्यात से 148,900 मे० टन कम था।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जूट के माल के निर्यात। निर्यात उपार्जन को बढ़ाने के लिये जो कतिपय महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(1) कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाने और खेती के सुधरे हुए तरीके अपना कर उसकी किस्म में सुधार करने के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) जूट के माल के नये तथा विविध प्रयोगों का पता लगाने के लिये एक गहन गवेषणा कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिससे जूट की खपत में वृद्धि हो। इस समय भारतीय जूट मिल संघ अमेरिका में औद्योगिक सलाहकारों की एक फर्म (फैब्रिक रिसर्च लेबोरेट्रीज) के साथ एक गवेषणा कार्यक्रम चला रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य जूट के माल के नए प्रयोगों का विकास करना है।

(3) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1965 से अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण को लागू किया गया है।

(4) सोवियत रूस और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ दीर्घावधि व्यापार करार किये गये हैं जिनमें जूट के माल के निर्यात के लिये विशेष व्यवस्था है।

(5) जूट के माल पर लगने वाले निर्यात शुल्कों के सम्बन्ध में समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप जूट के माल की सभी किस्मों पर शुल्क घटा दिया गया है जैसा नीचे दिया गया है :—

(1) कालीनों का अस्तर (2) विशेष माल	900 रु० से 700 रु० प्रति मे० टन
(3) अन्य हेसियन	900 रु० से 750 रु० प्रति मे० टन
(4) बोरियों का टाट	600 रु० से 450 रु० प्रति मे० टन
(5) सूती थैलों का कपड़ा	11 फरवरी, 1967 से 600 रु० से 200 रु० प्रति मे० टन।

मैंगनीज का निर्यात

1345. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में मैंगनीज के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) नये बाजारों का पता लगाने तथा पुराने बाजारों को पुनः प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये गयें हैं ; और

(ङ) इस अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात में गिरावट के कारण मुख्यतः ये हैं :—

(1) उपभोक्ता देशों के निकट संभरण के नये स्रोतों का उद्‌भव ।

(2) उपभोक्ताओं की ग्रहीत खानों के उत्पादन में वृद्धि ।

(3) प्रोद्योगिकीय प्रगतियों के कारण इस्पात उत्पादन में मैंगनीज अयस्क पर कम निर्भरता ।

(4) लौह–मैंगनीज तथा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत में मैंगनीज अयस्क की आंतरिक आवश्यकताएं बढ़ रही हैं ।

(ग) नये बाजारों का पता लगाने तथा पुरानों को पुनः प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क उपभोक्ता देशों में अभिकरणों की व्यवस्था की गई है । अच्छे व्यापार सम्बन्ध कायम रखने के लिए भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमण्डल बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा बिक्री करने के लिए मैंगनीज अयस्क के मुख्य उपभोक्ता देशों का समय समय पर दौरा करते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) विदेशी मुद्रा अर्जन की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चालू मूल्यों तथा दूसरी बातों पर निर्भर होगी । फिर भी 1966–67 की अवधि में निर्यात से 14,14,60,000 रुपये प्राप्त हुए ।

रेलवे के शिकायत रजिस्टर

1346. श्री निहाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारी कई बार जब वे गलती पर होते हैं प्रामाणिक यात्रियों को भी शिकायत रजिस्टर नहीं देते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि कुछ लोग रेलवे कर्मचारियों का अनुचित लाभ उठाने के लिये झूठी शिकायत करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक या दो रुपये की जमानत की राशि जमा कराने की पद्धति आरम्भ करने का है ताकि केवल सच्ची शिकायतें ही की जा सकें और ईमानदार रेलवे कर्मचारियों को परेशान न किया जा सके ?

रेलवे मन्त्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) हिदायत यह है कि शिकायत पुस्तिकाओं को किसी ऐसे स्थान पर दीवाल या डेस्क से बांध कर रखना चाहिए जहां से साफ दीख पड़े। शिकायत पुस्तिका का न दिया जाना गम्भीर बात समझी जाती है और जिम्मेदार पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध निवारक कार्यवाई की जाती है।

(ग) जी हां, कुछ मामलों में।

(घ) जी नहीं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

1347. **श्री निहाल सिंह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्य में पुन: वृद्धि करने का है ;

(ख) गत छः वर्षों में मूल्य में कुल कितनी वृद्धि करने की मंजूरी दी गई ;

(ग) क्या लागत को कम करने और मूल्यों को घटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या भारतीय कोयले का निर्यात करने के लिये कुछ नये बाजारों का पता लगाया गया है ; और

(ङ) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में कोयले का निर्यात करने के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले के मूल्यों से संबन्धित सारा प्रश्न प्रशुल्क आयोग को निर्देशित है। उत्पादन की लागतों के अध्ययन के आधार पर कोयले के मूल्यों में जो सामान्य वृद्धि होती है उसका किसी विशेष कारक से सम्बन्ध नहीं है। इस वृद्धि के अतिरिक्त, समय समय पर कुछ और मूल्य वृद्धियां भी मन्जूर की जाती हैं। ये वृद्धियां लेबर अपैलट ट्रिब्यूनल जैसी निकायों के फैसलों को कार्यान्वित करने के लिये होती हैं और इन के प्रभाव से उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

(ख) कोकिंग कोयले के श्रेणि करण तथा मूल्य सम्बन्धित संशोधित ढांचे को फरवरी 1962 में लागू किया गया। कुछ श्रेणियों के कोयलों के बारे में जून 1962 और मार्च 1964 में तदर्थ वृद्धियां की गई। इसके अतिरिक्त, पिछले 6 सालों में कुल मिलाकर कोयले के मूल्यों में निम्न वृद्धियों की मंजूरी दी गई है :-

बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र

श्रेणि II और III	-6.02 रुपये प्रति मीट्रिक टन
अन्य श्रेणियां	-6.22 रुपये प्रति मीट्रिक टन

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दूरस्थ-क्षेत्र

सब श्रेणियों का कोयला	-5.42 रुपये प्रति मीट्रिक टन

(ग) सरकार की मूल्य नीति इस प्रकार बनाई जाती है जिससे कि कोयला उत्पादन करने वाली इकाईयों की अदक्षता निरूत्साहित हो।

(घ) यद्यपि कोई नए बाजार नहीं खोजे गए हैं पर कुछ परम्परागत बाजारों को पुन: अपनाया गया है और निर्यात के लिए नए रास्तों को खोजने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(ङ) यह आशा की जाती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 215 करोड़ मीट्रिक टन कोयला निर्यात किया जावेगा।

झाझा के माल गोदाम को अन्य स्थान पर लेजाना

1348. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झाझा पर माल गोदाम को उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर (रेलवे के पानी के टैंक के निकट) हटाने और उसी स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म शैड बनाने के लिये स्थान का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सरकार को झाझा (उत्तर रेलवे) की जनता से कोई नया अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) झाझा के माल गोदाम को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा ले जाने पर बहुत अधिक खर्च होगा, जिसका, इस स्टेशन के वर्तमान माल यातायात और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए औचित्य नहीं है। जहां तक अतिरिक्त प्लेटफार्म शेड के लिए प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यात्री यातायात की वर्तमान मात्रा को देखते हुए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

झाझा में रेलवे भूमि का रेलवे कर्मचारियों को अलाटमेंट

1349. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, दानापुर ने झाझा (पूर्व रेलवे) में कुछ वर्ष पहले अधिग्रहीत की गई रेलवे भूमि अनाज उगाने के लिये अस्थायी आधार पर कुछ रेलवे कर्मचारियों को दी थी ;

(ख) क्या मूल मालिकों (कर्मचारियों) ने जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी रेलवे अधिकारियों से यह प्रार्थना की है कि इस भूमि के अस्थायी आधार पर अलाटमेंट के मामले में उन्हें वरीयता दी जानी चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो इस के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस वर्ष की खरीफ की फसल के लिये भूमि देने की नीति क्या है ; और

(घ) यदि अन्य कर्मचारियों की तुलना में मूल स्वामियों कर्मचारियों को वरीयता न देने की नीति है तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, रेल कर्मचारियों सहित कुछ व्यक्तियों ने भूमि का मूल स्वामी होने का दावा करते हुए भूमि में नियतन में तरजीह देने का प्रतिवेदन दिया है। लेकिन रेलें यह सत्यापन करने की स्थिति में नहीं हैं कि वे मूल स्वामी हैं या नहीं क्योंकि यह भूमि सीधे राज्य सरकार से अधिगृहीत की गयी थी।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार स्टेशन यार्डों की खेती योग्य भूमि केवल रेल-कर्मचारियों को दी जाती है ताकि रेलवे को जब कभी अपने काम के लिए उसकी आवश्यकता पड़े वह अल्प-सूचना देकर ही उसे प्राप्त कर ले। इस तरह के अस्थायी नियतन में मूल स्वामियों को तरजीह देने का कोई नियम नहीं है।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, मूल-स्वामित्व वाले कर्मचारियों को तरजीह देने के सुझाव का पालन करने के लिए इस बारे में राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करनी होगी और चूंकि इसमें समय लगेगा, इसलिए इस क्रियाविधि को अपनाना प्रसाशकीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

Lignite Coal Mines in Palana, Rajasthan

1350. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the time by which the scheme drawn for prospecting the lignite coal mines in village Palana in Bikaner district of Rajasthan would be implemented;

(b) the quantity of coal expected to be dug out from this mine and the purpose for which it will be used;

(c) whether this variety of coal is also being mined in village Khari in district Bikaner of Rajasthan; and

(d) if so, the result there of

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : The Government of Rajasthan are reported to have completed prospecting work relating to the lignite deposits in Palana in Bikaner District. According to the State Government, about 13 million tonnes of lignite can be mined by open cast mining method and used in a thermal power station near the pit mouth. The actual exploitation of the deposit and its utilisation is the concern of the State Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Damage Caused to Railway Lines by Floods in Ghaggar River

1351, Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether his Ministry has formulated any scheme to avoid damage caused to railway lines by floods in the Ghaggar river every year which results in disruption of the traffic;

(b) the loss of revenue from goods traffic since the date on which the railway line was closed upto 1st September, 1964;

(c) the total amount of loss of revenue under railway passenger fares etc. on this account;

(d) the cost of repairs of the damaged railway line etc., and

(e) the amount of expenditure required to be incurred in case a railway line is built of four feet higher than the level of the present railway line and proper culverts are built for free flow of water ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No separate scheme has been formulated by the Railway as the problem involves flooding of not only the railway track but also vast areas of land including the Suratgarh Farms in Rajasthan State. The State Government have, however, constructed a diversion channel to carry the flood waters through the syphon under the Rajasthan Canal to the natural reservoir formed by the sand dunes to the west of Suratgarh thereby reducing the flood in the Ghaggar bed.

(b) Approximately Rs. 10.32 lakhs from 1960 to 1964.

(c) Approximately Rs. 5.54 lakhs from 1960 to 1964.

(d) About Rs. 10 lakhs for 1961-62 to 1965-66.

(e) The alignment is situated in the bed of the River Ghaggar and therefore raising the Railway line by 4 ft. will not solve the problem. As such, the cost of such proposal has not been worked out. However, as mentioned against para (a), the State Government is constructing a diversion channel which is expected to carry away most of the discharge from the river bed, leaving only about 4,000 cusecs, during the monsoons, for which the existing culverts and bridges are quite adequate.

गुरा-मक्सी रेलवे परियोजना

1352. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरा-मक्सी रेलवे परियोजना को पूरा करने के लिए कौन सी नई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक संशोधित लक्ष्य तिथि निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस विषय पर शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

Maheshi Railway Station

1353. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Maheshi station of the Eastern Railway has been made a 'B' Class Railway station;

(b) whether all the facilities provided at 'B' Class railway station are available there.;

(c) if so, the nature thereof;

(d) if the said station has been included in 'B' class the reasons for stoppage of the trains there for only three minutes now while previously the trains had been stopping there for ten minutes;

(e) whether Government propose to construct a shed over the platform of the said station; and

(f) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

(d) There has been no curtailment in duration of stoppages of trains.

(e) No.

(f) Does not arise.

खुरदा रोड में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

1354. **श्री अ० दीपा** :
श्री प्र० के देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० प्रभात :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लोगों ने यह आरोप लगाते हुए एक अभ्यावेदन दिया है कि खुरदा रोड स्थित रेलवे के विभिन्न विभागों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Price of Cement

1355. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that cement is in short supply for the past few months and its price has also gone up considerably;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the steps being taken to improve the situation ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) No, Sir. The supply position in recent months all over the country has been satisfactory. In May 1967, the Governments of Haryana and Punjab have, however, reported shortage of cement in certain districts and towns. Price of cement has not gone up. The last price increase given from 1.4.1967 was to the extent of Rs. 1.20 per tonne on account of enhanced freight charges.

(c) The cement industry's Central Organisation viz. Cement Allocation and Coordination Organisation, which is looking after the distribution of cement, has been asked to be vigilant and to ensure that supplies to all parts of the country are maintained at past levels, if not improved upon. Specific complaints, when received from any State Governments, are referred to this Organisation for taking immediate remedial measures.

नारियल जटा के धागे के लिये रेल के माल डिब्बों का न मिलना

1356. **श्री श्रीधरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के बड़ागरा के नारियल-जटा धागा व्यापारियों की ओर से नारियल-जटा के धागे की गांठों की ढुलाई के लिये रेल के माल डिब्बों के न मिलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) लदान बढ़ा दिया गया है । 1 अप्रैल, से 20 मई, 1967 तक की अवधि में बडागरा से नारियल-जटा के 39 माल डिब्बे लादे गये । इसके अलावा इस अवधि में इस स्टेशन से 368 क्विंटल नारियल-जटा 'फुटकर' के रूप में भी भेजी गयी।

मुद्रण सम्बन्धी मशीनों का आयात

1357. **श्री श्रीधरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 से 1966 के दौरान मुद्रण संबंधी मशीनों का आयात करने के लिये गैर-सरकारी मुद्रकों को लायसेंस जारी किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं जिनको लायसेंस दिये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में मुद्रण सम्बन्धी मशीनों के लिए एक बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा ऐसे सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में प्राप्य हैं।

केरल में सूक्ष्म औजार उद्योग

1358. श्री श्रीधरण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सूक्ष्म औजार उद्योग स्थापित करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखाने में कब कार्य आरम्भ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पालघाट में स्थापित सिविल इंजीनियरी कार्यालय कारखाने के स्थान पर भूमि और प्रारम्भिक निर्माण कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण कर रहा है। केरल सरकार ने मलमपुझा बांध से कारखाने के स्थान तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। कारखाने की इमारत के निर्माण के लिए टेण्डर संबंधी कागजों को पूरा कराने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। 17 इंजीनियरों के पहले दल की भर्ती की जा चुकी है और एक परियोजना प्रशासक नियुक्त कर लिया गया है।

(ख) वर्ष 1968 के अन्त तक।

मैसूर और उत्तर केरल के बीच रेल सम्पर्क

1359. श्री श्रीधरण : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर और उत्तर केरल के बीच रेल द्वारा संबंध स्थापित करने की संभावना के विषय में छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा विस्तार से क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) कुर्ग के रास्ते तेल्लिच्चेरी और मैसूर के बीच एक मीटर लाइन बनाने के लिए 1957-58 में अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किया गया था। यह प्रस्ताव अलाभप्रद पाया गया।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

1360. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के संबंध में कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितनी राशि निर्धारित करने का विचार है और उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य सरकार ने चौथी योजना की अवधि में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित कर ली हैं (वर्ष 1967-68 की योजनाएं अलग से नहीं दिखाई गई हैं) :

1. उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण,
2. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को अंश पूंजी संबंधी ऋण,
3. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को कार्यकारी पूंजी संबंधी ऋण,
4. पंचायत उद्योगों की सामान्य पूंजी में हिस्सा,
5. पंचायत उद्योगों की स्थापना के लिए चुनी हुई ग्राम पंचायतों को अनुदान,
6. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को प्रबन्ध संबंधी कर्मचारियों के मामले में आर्थिक सहायता,
7. केन्द्रीय वित्त समिकरणों को औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा देय ब्याज के संबंध में आर्थिक सहायता,
8. कारखाने की बिजली संबंधी प्रशुल्क को समान करने के लिए आर्थिक सहायता,
9. प्रदर्शनियां एवं मेले ।

ग्रामीण लघु उद्योग संबंधी कार्यकारी दल ने लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए 130 लाख रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है ।

इस्पात का आयात

1361. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :

क्या इस्पात, खान और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य को 1966–67 में इस्पात का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी ?

इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : लोहे और इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस नीति में ढील देने से अगस्त, 1966 में किसी भी राज्य को लोहे और इस्पात का आयात करने के लिए अलग से विदेशी मुद्रा नहीं दी गई । राज्यों के लघु उद्योग और दूसरे कारखाने इस नीति में बताये गये तरीके के अनुसार कच्चे माल, संघटक और फालतू पुर्जे आयात कर सकते हैं ।

उड़ीसा में भारी उद्योग

1362. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में कोई भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण

1363. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में उड़ीसा से कितने लोग छोटे पैमाने के उद्योगों का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेशों में भेजे गए हैं; और

(ख) जिन देशों में उन्हें भेजा गया है, उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा को सीमेंट की आवश्यकता

1364. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को इस समय कितने सीमेंट की आवश्यकता है; और

(ख) 1966-67 में उड़ीसा राज्य को वस्तुतः कितना सीमेंट दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : चूंकि सीमेंट के मूल्य तथा वितरण से नियन्त्रण हटा लिया गया है, अतः अब राज्य सरकारों को नियतन के लिए सीमेंट की अपनी आवश्यकता केन्द्रीय सरकार को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके बदले उनकी आवश्यकताएं अब स्वयं

उद्योग द्वारा ही सामान्य व्यापारिक साधनों द्वारा पूरी की जाती हैं। 1966-67 में उड़ीसा को 3,83,000 मी० टन सीमेंट का वास्तविक सम्भरण किया गया। चूंकि सीमेंट की अत्यधिक कमी की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए समझा यह जाता है कि उक्त राज्य की आवश्यकता इतनी ही थी। यदि और अधिक परिमाण की आवश्यकता पड़ती भी हैं तो उद्योग उसे पूरी कर सकता है।

1366. श्री मोहसिन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य खादी बोर्डों द्वारा किये गये कुप्रबन्ध तथा धन के गबन के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें आई हैं ;

(ख) क्या इन खादी बोर्डों के काम के बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या निकला है; और

(घ) ये बोर्ड ठीक प्रकार काम करें, इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब के राज्य बोर्डों द्वारा आयोग को भेजे गये कपट और निधियों के दुर्विनियोग के मामलों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और राजस्थान के चार राज्य बोर्डों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ देखी गई अनियमितताएं इस प्रकार हैं :—

(एक) वित्तीय विवरणों और सन्तुलन पत्रों तैयार किये जाने में विलम्ब (प्राप्ति और भुगतान लेखों के अतिरिक्त)।

(दो) दृष्टिबन्धक पत्र प्राप्त करने में विलम्ब।

(तीन) उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त करने और देने में विलम्ब।

(चार) जिन प्रयोजन के लिए निधियां दी गईं उन्हें उनमें न लगाकर अन्य प्रयोजनों में लगाना।

(पांच) अनुमोदित लेखा प्रकिया के न होने के परिणामस्वरूप लेखों का अव्यवस्थित ढंग से रखा जाना।

(छः) राज्य सरकार विभाग द्वारा सहकारी समितियों के लेखों की जांच में विलम्ब।

(सात) राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और विनियमों का तैयार न किया जाना तथा अनुमोदन न किया जाना।

(आठ) उधार विक्रय के अन्तर्गत बड़ी राशियां बकाया।

(नौ) प्रदर्शियों के लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

(दस) संस्थाओं/सहकारी समितियों से उपयोग न की गई निधियों की वसूली में विलम्ब।

(ग्यारह) सावधि विक्षेपों में निधियों का विनियोजन।

[घ](एक) राज्य बोर्डों की बैठकों में प्राप्ति तथा व्यय के लेखों पर भी चर्चा की जाती है।

(दो) उनके द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं और सहकारी समितियों से संतुलन पत्रों की पुष्टि प्राप्त करने की एक पद्धति।

(तीन) राज्य बोर्डों द्वारा जिन संस्थाओं को सहायता दी गई है उन संस्थाओं से उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त करने में प्रगति देखने के लिये उपयुक्त रजिस्टरों का रखा जाना।

(चार) उपयुक्त रजिस्टरों के द्वारा संस्थाओं/सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋणों के भुगतान समय पर लौटाये जाने की प्रगति को देखने के लिए नई पद्धति का लागू किया जाना।

(पांच) बजट तैयार करने और बजट आवंटनों के अनुसार निदित शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय देखने के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारित किया जाना।

(छः) अधिकांश राज्य बोर्डों में आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति का लागू किया जाना जिससे वे समय समय पर संस्थाओं/सहकारी समितियों के कार्य का पुर्नविलोकन कर सकें।

(सात) आयोग के वरिष्ठ अधिकारी राज्य बोर्डों का अध्ययन करते हैं और राज्य बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी समस्याओं और आपत्तियों पर चर्चा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा की जाती है।

(आठ) जब राज्य बोर्डों के वार्षिक उत्पादन कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है तो अन्य बातों के साथ साथ बकाया राशियों की वसूली सम्बन्धी समस्याओं, त्रुटियों का घटाया जाना, शेष राशियों की संपुष्टी, पेशगी दी रकमों सम्बन्धी खातों का ठीक किया जाना, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता, महालेखापाल के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन और आवश्यक उपचारीय उपायों,अब तक के लेखों का तैयार किया जाना और आन्तरिक लेखा परीक्षण पर भी चर्चा की जाती है।

अलाभप्रद कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

1367: श्री सु० कु० तापड़िया श्री त्रिदिब कुमार चौधरी

श्री देवकीनन्दन पटोदिया : श्री स० चं० सामन्त :

श्री मुहम्मद इमाम : श्री काशीनाथ पाण्डेय :

श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलाभप्रद कपड़ा मिलों के प्रबंध के लिये एक निगम की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सरकार एक वस्त्र निगम की स्थापना के प्रश्न पर सक्रिय रूप में विचार कर रही है, जो उसे सौंपे गये कुछ अन्य कार्यों को करने के अलावा ऐसी कमजोर तथा समाप्तप्राय वस्त्र मिलों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें चलायेगा जो आर्थिक रूप में चलने योग्य तो हों पर कतिपय कारणों से बंद हो गई हों या जिनके शीघ्र ही बंद होने का खतरा हो ।

राजस्थान में औद्योगिक विस्तार सेवा

1368. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में राजस्थान में औद्योगिक विस्तार सेवा से छोटे पैमाने के कितने कारखानों को लाभ हुआ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में उस राज्य में इन कारखानों को कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :
(क) तकनीकी सहायता :

1. पार्टियों की संख्या जिनसे उनके कारखाने में ही सम्पर्क स्थापित किया गया ।	2208
2. पार्टियों की संख्या जिसे सम्पर्क स्थापित किया गया ।	7996
3. पार्टियों की संख्या जिन्हें केवल तकनीकी सलाह दी गई ।	3157
4. पार्टियों की संख्या जिन्हें नए उद्योग स्थापित करने के लिए जानकारी दी गई	1000
5. किए गए प्रदर्शनों की संख्या (चलती फिरती वर्कशापों के अतिरिक्त)	226
6. ऐसी पार्टियों की संख्या जिनको अन्य सहायता प्रदान की गई	3384

2. **चलती फिरती वर्कशापें**

1. केन्द्रों की संख्या जिनका निरीक्षण किया गया	81
2. किए गए प्रदर्शनों की संख्या	87
3. प्रशिक्षित किए गए कारीगरों की संख्या	262

3. **वर्कशापों की गतिविधियां**

2. पार्टियों की संख्या जिन्होंने उजरत पर काम करवाने के लिए विस्तार केन्द्र वर्कशाप को देखा 1157

2. पार्टियों की संख्या जिन्हें वास्तविक सहायता दी गई 1062

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को इकट्ठा ऋण दिया जाता है ताकि वे उसे अपनी योजनाओं के लिए उपयोग में ला सकें, जिनमें उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत लघु एककों औद्योगिक सहकारी समितियों सामान्य सेवा सुविधा केन्द्रों, वर्कशापों, उत्पादन केन्द्रों को ऋण देना शामिल है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के वार्षिक विवरण, जिनमें पहली तीन तिमाहियों का वास्तविक व्यय तथा चौथी तिमाही के सम्भावित व्यय के आधार पर दी जाती है और राज्य सरकारें अपने खर्च को वित्त मन्त्रालय द्वारा नियत "अर्थोपाय अग्रिम राशि" से पूरा करती हैं। 1966-67 में राजस्थान सरकार को लघु उद्योगों का विकास करने के लिए 2.10 लाख रुपये के ऋण का अस्थायी भुगतान किया गया है।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

1369. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के सम्बन्ध में कोई योजनायें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कितना धन नियत करने का विचार है तथा योजनायें किस प्रकार की हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ग) : राजस्थान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निम्नलिखित योजनाएें शामिल की हैं (1967–68 की योजनाओं को प्रथक नहीं दिखाया गया है):—

1. लघु उद्योगों के लिए ऋण
2. लेदर वर्क्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का विकास
3. किस्म चिन्हांकन तथा निर्यात संवर्धन
4. औद्योगिक तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास
5. राजस्थान वित्त निगम और दूसरी बैंकिंग संस्थाओं के ब्याज पर राज्य सहायता
6. औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला का विस्तार
7. किस्म चिन्हांकन
8. खण्डों में सामान्य सुविधा के केन्द्र
9. सामाजिक कल्याण योजना

राज्य सरकार ने लघु उद्योग तथा औद्योगिक विकास बस्तियों के विकास के लिए बजट में 7.75 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

राजस्थान में भारी उद्योग

1370 श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार 1967-68 में राजस्थान में कोई भारी उद्योग स्थापित करने के लिये कोई विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में औद्योगिक कारखाने

1371. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में राजस्थान में सरकार का कौन कौन से औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : निम्नलिखित केन्द्रीय परियोजना जिनका राजस्थान में निर्माण कार्य चल रहा है, 1967-68 तक पूर्ण हो जायेंगी ।

1. उदयपुर में जिंक स्मेल्टर
2. कोटा में सूक्ष्म यन्त्रों का कारखाना

इसके अतिरिक्त अजमेर में एक मशीनी औजारों का कारखाना स्थापित किया जायगा ।

राज्य सरकार के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं :-

1. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
2. ऊनी कपड़े की मिल
3. चमड़ा रंगने की फैक्टरी
4. सोडियम सल्फेट संयंत्र का विस्तार
5. हाई-टेक ग्लास फैक्टरी

इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकार पर है ।

निर्माताओं को स्टेनलेस स्टील की सप्लाई

1372. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री निर्माताओं को स्टेनलेस स्टील की सप्लाई के बारे में 31 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :(क) जी, हां।

(ख) 1967-68 के लिये लोहे और इस्पात की आयात नीति में जिसकी घोषणा लोहा और इस्पात नियन्त्रक ने अपने 16 मई, 1967 के सरकारी नोटिस में की थी, बर्तनों तथा अन्य घरेलू सामान बनाने वालों के लिए स्टेनलेस स्टील शीट्स, सर्कल्स, और प्लेटों के आयात के लिए भी व्यवस्था की गई है। विस्तृत कार्यप्रणाली पर विचार किया जा रहा है और इसकी घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

मद्रास में पुल निरीक्षक अनुभाग

1373, **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मद्रास में पुल निरीक्षकों के अनुभाग के 31 अस्थायी कर्मचारियों को जो पांच वर्ष से लेकर पन्द्रह साल तक की नौकरी पूरी कर चुके हैं, नौकरी से निकालने के नोटिस हाल में दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी लगातार लम्बी अवधि तक की नौकरी पर विचार करते हुए उनको वैकल्पिक नौकरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इन व्यक्तियों को नैमित्तिक मजदूर के रूप में नैमित्तिक किस्म के एक विशिष्ट काम पर लगाया गया था इसलिए पर्याप्त काम न होने तथा अनुदान में आम कटौती के कारण उन्हें 21-5-67 से काम पर न आने का नोटिस दिया गया था।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है और पुनरीक्षण के दौरान 20-6-67 तक उनकी नौकरी बरकरार रखना सम्भव हो सका है।

Class III and IV Staff of N. E. Railway.

1374. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about twenty thousand Class III and Class IV employees of North Eastern Railway have not been confirmed even after putting in three to seven years of service; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. The number of such staff in the initial recruitment grades is about 3000.

(b) Non-availability of permanent vacancies and in some cases, fitness for confirmation not yet established.

रेलवे वर्कशाप, समस्तीपुर का मैकेनिकल विभाग

1375. भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर स्थित रेलवे वर्कशाप के मैकेनिकल विभाग में वर्कशाप के 1200 कर्मचारियों को टिफिन कैरियर बांटने के लिए 1966 में 40,000 रुपये मंजूर किये गये थे ;

(ख) क्या यह राशि कर्मचारियों में अभी तक नहीं बांटी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

1376 श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सात वर्ष पहले दरभंगा जिले में रामेश्वर नगर में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड नाम से कागज तैयार करने का एक बड़ा उद्योग आरम्भ किया गया था और उसमें 7 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगाई जा चुकी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन आरम्भ करने के लिए अभी 3 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है और यह धन न होने के कारण काम बिल्कुल रुका पड़ा था;

(ग) क्या अकाल की स्थिति के कारण बिहार सरकार अपेक्षित धन देने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस कारखाने को बिहार सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिये जाने के लिए उसे अपेक्षित राशि देने अथवा इस कारखाने को केन्द्रीय नियन्त्रण में लेने का है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 1956 में दरभंगा जिले में कागज और लुगदी का निर्माण करने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अशोक पेपर मिल्स लि० को एक लाइसेंस दिया गया था। संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए 12 अगस्त, 1959 को अनुमति दे दी गई थी। लाइसेंस प्राप्त कर्त्ता के वित्तीय कठिनाइयों के कारण गत ढ़ाई वर्षों से संयंत्र को पूरा करने का काम रोक दिया गया है। परियोजना पर व्यय की गई ठीक-ठीक राशि ज्ञात नहीं है किन्तु पिछले वर्षों में आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें देखते हुये परियोजना पूरी और कार्यान्वित करने पर 6.50 करोड़ रुपये से लेकर 15.75 करोड़ रुपये तक व्यय होने का अनुमान

है और बिहार राज्य सरकार ने उस कारखाने को पुनः स्थापित करने एवं उसका विस्तार करने तथा उसे बचतपूर्ण ढंग से चलाने का उत्तरदायित्व लेने का निश्चय किया है ।

(ग) हमें बिहार सरकार से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1966–67 में उड़ीसा में खानों का पट्टे पर दिया जाना

1377. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही: क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1966 और 1967 में उड़ीसा की विभिन्न खानें खनन-कार्य तथा उनसे माल निकालने के लिए पट्टे पर दी गई थीं; और

(ख) प्रत्येक पट्टाधारी को कितनी कितनी खान पट्टे पर दी गई थीं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रखी जायेगी ।

तलचर औद्योगिक केन्द्र

1378. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव : **श्री डी० एन० देव :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में तलचर में तलचर औद्योगिक केन्द्र की स्थापना के बारे में मंत्रिमंडल की उप-समिति ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का स्वरूप क्या है;

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी;

(घ) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में इस समूह के लिये अपने हिस्से की धनराशि वहन करने में अपनी असहमति प्रकट की है; और

(ङ) इस समय इस परियोजना की स्थिति क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क), (ख) और (ङ) तलचर में एक औद्योगिक कौम्पैलक्ष स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर दिसम्बर 1966 में मंत्री मंडल की औद्योगिक समिति ने विचार किया था । समिति ने कुछ अत्यन्त महत्व की बातों के सम्बन्ध में और सूचना लेनी चाही थी । यह सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों आदि के साथ विचार विमर्श करके संकलित की जा रही है ।

(ग) चौथी योजना के मसौदे की रूप रेखा में यह योजना राज्य की सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में शामिल की गई है। योजना आयोग ने संकेत दिया है कि उड़ीसा के राजकीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता इस परियोजना की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर दी जायेगी।

(घ) नहीं, महोदय।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

1379. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1967 को पूर्वोत्तार सीमा रेलवे के सिलीगुड़ी-अलीपुर द्वार सैक्सन पर बीना गुन्डी तथा दलगांव स्टेशनों के बीच सीधी जाने वाली अप माल गाड़ी पटरी से उतर गई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उससे रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि माल डिब्बे के एक्सिल के बियरिंग स्प्रिंग बकल में खराबी आ गयी थी।

(ग) रेल सम्पत्ति को अनुमानतः लगभग 60,076 रुपये का नुकसान हुआ।

कलकत्ता के निकट इस्पात का कारखाना

1380. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह के सहयोग से इस्पात निर्माताओं की एक ब्रिटिश कम्पनी का विचार कलकत्ता के निकट इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) कलकत्ता के निकट ब्रिटिश फर्म द्वारा इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य मिश्रित इस्पात के कारखाने के बारे में पूछना चाहते हैं। बिड़ला की एक फर्म हाई क्वालिटी स्टील्स लिमिटेड को कलकत्ता के निकट औजारों और मिश्रित इस्पात के उत्पादन के लिए एक कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इन्होंने यू० के० की एक फर्म के साथ तकनीकी सहायता तथा जानकारी के लिए एक करार किया है। यू० के० की यह फर्म 'हाई क्वालिटी स्टील्स' को क्विटी कैपीटल में भी धन लगायेंगी। सरकार ने यू० के० की फर्म द्वारा तकनीकी सहयोग देने तथा ईक्विटी कैपीटल में धन लगाने की अनुमति दे दी है। ऐसी आशा है कि यह कारखाना 1970-71 तक उत्पादन करना शुरू कर देगा।

मिलिट्री स्पेशल रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1381. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि 28 मार्च, 1967 को गया से लगभग 30 मील की दूरी पर गुरपा और पहाड़पुर रेलवे स्टेशनों के बीच एक मिलिट्री स्पेशल मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप कुछ सैनिक बुरी तरह घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) दुर्घटना होने के क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के गुरपा स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास सैनिक स्पेशल मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण सेना के चार कार्मिकों को हल्की चोटें आयीं।

(ग) दुर्घटना का कारण यह था कि गाड़ी के ब्रेकवान से सातवें नम्बर पर लगे एक डिब्बे की दाहिनी ओर की अगली बोगी का इलिप्टिकल स्प्रिंग रिटेनर टूट गया। साथ ही इसी डिब्बे में लदे हुए मोटर वाहन अच्छी तरह बंधे न होने के कारण खिसक गये। इन कारणों से इस डिब्बे के पहियों पर असंतुलित भार पड़ा और डिब्बा पटरी से उतर गया।

Railway Line from Daurala to Hastinapur

1382. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether the scheme for constructing a railway line from Daurala to Hastinapur was drawn up by the Central Government with a view to develop Hastinapur, of District Meerut, Uttar Pradesh and the Daurala Sugar Works handed over their narrow gauge railway line from Daurala to Bhavana to Government free of cost;

(b) whether it is also a fact that the land for the railway line from Bhavana to Hastinapur was spared by the farmers during the consolidation of land and it is still lying vacant;

(c) whether it is also a fact that the construction of the said railway line was stopped owing to Indo-Pak conflict; and

(d) if so, the time by which the said line is likely to be constructed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) So far as the first portion of this question is concerned it may be stated that the scheme was examined by conducting a survey for the proposed line. Regarding the second portion, it may be added that it was understood that the management of this NG line (Daurala-Mawana Tramway) were prepared to offer the land of this tramway to the Railways for constructing the proposed BG line from Daurala to Hastinapur via Mawana but due to technical and other difficulties, construction of a BG line over the NG line alignment was not found feasible. Hence the Railway surveyed a separate alignment and as such the question of taking over the tramway's land did not arise.

(b) This Ministry is not aware of this,

(c) No. The project was not approved as it was unremunerative, particularly in view of the existence of well developed roads in the area.

(d) Does not arise.

Heavy Engines at Meerut City Junction.

1383. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangements for turning the directions of heavy engines have not been started so far at Meerut City Junction;

(b) whether the existing arrangements for movement of shuttle trains between Meerut and Delhi are still such that the direction of engine is not changed; and

(c) whether it is a fact that all the material necessary for the arrangements is lying there for the last few months but the same has not been installed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) No. The links have been so arranged that no passenger train runs tender foremost.

(c) No. Only part materials have been received so far for the installation of the turn table.

Manufacture of Passenger Cars

1384. Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 761 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether the proposal regarding the manufacture of passenger cars has since been finalised ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the places at which and the firms by whom these cars would be manufactured ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) No (b) and (c) : Do not arise.

सेलम इस्पात संयंत्र

1385. **श्री कन्डप्पन :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाड में सेलमानीवेली क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो कारखाना स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस्पात की आवश्यकता और साधनों की उपलब्धि पर पुन: विचार करने के पश्चात ही लोहे और इस्पात के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

कुलियों के लाइसेंसों का उनके लड़कों के नाम किया जाना

1386. श्री कंडप्पन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रेलवे स्टेशनों में कोई ऐसी प्रथा है कि जब कुली काम करना छोड़ देते हैं तो वे अपने लाइसेंसों को अपने लड़कों के नाम करा देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) लाइसेंस प्राप्त भारिकों के बिल्ले हस्तान्तरणीय नहीं होते। लेकिन कुछ वर्ष पहले कुछ रेलों पर मृत अथवा डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य भारिकों के पुत्रों को करुणा मूलक आधार पर लाइसेंस दिये गये थे। वर्तमान स्थिति यह है कि लाइसेंस प्राप्त भारिकों का चुनाव एक विधिवत गठित चुनाव बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसमें एक गैर सरकारी सदस्य भी रहता है। अन्य प्रार्थियों के साथ लाइसेंस प्राप्त भारिकों के पुत्रों के मामलों पर गुण-दोष के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

कपास की वसूली

1387. श्री याज्ञिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री च० चु० देसाई :
श्री आर० के० अमीन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कपास विक्रय सहकारी समितियां तथा अन्य स्टाकिस्टों ने वस्त्रायुक्त द्वारा कपास के स्टाक के सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य पर जो कि बाजार के मूल्य से बहुत कम है, मनमाने ढंग से अधिग्रहण के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या अन्य सभी राज्यों की तुलना में उपलब्ध कपास के भण्डारों का बहुत अधिक अनुपात में अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या स्थिति पर पुनर्विचार के परिणामस्वरूप सरकार ने कोई नये आदेश जारी किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग): संविधिक तौर पर नियत किये गये उचित अधिकतम मूल्य पर उद्योग को कपास की उपलब्धि को सुनिश्चित करने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुसरण में, वस्त्र आयुक्त ने जो देश भर में अधिग्रहण शुरु किया था, उसके विरुद्ध गुजरात के कपास उगाने वालों और सहकारी समितियों से अभ्यावेदन मिले थे। प्रत्येक क्षेत्र से कपास का अधिग्रहण उन मिलों द्वारा मांगी गई कपास की किस्म पर निर्भर रहेगा जिनके लिये अधिग्रहण किया गया है।

कपास के विनियमित बाजारों के संबंध में सरकार की नीति की आवश्यकता, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कपास का अधिग्रहण भी करना पड़ता है, इसलिए हुई थी कि

उद्योग को कपास के उपलब्ध सम्भरण का सम्यक वितरण हो। पुनरीक्षण करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि :

(1) कपास उगाने वाले तथा उनकी सहकारी समितियां कपास की बिना बिकी मात्रा को, सर्वेक्षण हो जाने की अवस्था में, उचित अधिकतम भाव पर बेचें और वस्त्र आयुक्त, बम्बई, भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ से कहेगा कि वे ऐसे कपास के उठान को सुकर करें।

(2) ऐसी कपास को जो बिक तो गई हो परन्तु उसकी सुपुर्दगी न हुई हो, खरीददार मिलों को वस्त्र आयुक्त द्वारा दिये गये लाने ले जाने के परमिटों पर, यथासंभव संजित किया जाता है।

(3) भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा खरीदी गयी कपास की कुल मात्रा के लाने ले जाने के परमिट जारी किये जाएंगे जिसे मिलों में यथावश्यक वितरण के लिए रखा जायेगा।

चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार

1388. श्री य० श्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री गेदव्रत बरुग्रा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के साथ हाल में एक व्यापार करार हुआ है। और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 19 अप्रैल, 1967 को प्रेग चेकोस्लोवाकिया में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल तथा चेकोस्लोवाकिया के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के मध्य एक व्यापार संधि प्रारुप पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यह उल्लेख था कि 1967 की अवधि में भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच माल का आदान-प्रदान 7 नवम्बर, 1963 के व्यापार तथा भुगतान करार, जो 1968 के अन्त तक वैध है, के साथ संलग्न वस्तु-सूचियों 'क' तथा 'ख' के आधार पर किया जायेगा। इस करार की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

2. दो प्रतिनिधि मण्डलों के मध्य 1967 के वर्ष में व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। यह आशा की जाती है कि 1967 की अवधि में दोनों देशों के मध्य दोनों ओर से 72 करोड़ रुपये तक का व्यापार होगा। वर्ष 1967 की अवधि में सहयोग योजना इत्यादि के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया भारत को मशीनी औजार, ट्रैक्टर सी० के० डी० तथा फालतू पुर्जे एवं संघटक, पूंजीगत माल, बिले हुए इस्पात उत्पाद, मिश्रित धातु एवं विशेष इस्पात के औजार, रासायनिक पदार्थ, अखबारी कागज, प्रयोगशालाओं के तथा वैज्ञानिक उपकरण मोटर साइकिल, स्कूटर, मेज घड़ियां, घरों में प्रयोग किये जाने वाले बिजली के मीटर, ईंधन डालने के उपकरण आदि के लिए पुर्जे तथा कच्चे माल का संभरण करेगा। चेकोस्लोवाकिया

को निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में लौह अयस्क, जूट उत्पादन, कमाई तथा अर्ध-कमाई चर्म एवं खालें, तेल रहित खलियां, चाय, काफी, तम्बाकू, काली मिर्च, मेंगनीज अयस्क तथा अभ्रक आदि परम्परागत मदों के अतिरिक्त इंजीनियरी तथा अनेक औद्योगिक उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, भेषज और जड़ी-बूटी, सिले-सिलाये वस्त्र, टायर तथा ट्यूब, टीन बन्द फल इत्यादि हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का ठेके देना

1389. श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का ठेके दिये जाने के मामले की जांच करने के लिये जांच समिति नियुक्त की गई है जिसका सुझाव लोक लेखा समिति (तृतीय लोक-सभा) ने दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) रेलवे बोर्ड ने इस मामले की कार्यविधिक त्रुटियों की जांच करने के लिए अक्टूबर 1966 में निर्माण, यांत्रिक तथा वित्त के अपर सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति के विचारार्थ कोई विशिष्ट विषय निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि समिति को निदेश दिया गया था कि वह मामले का अध्ययन करे और विचारार्थ विषय का विनिश्चय स्वयं करे। लेखा समिति की 72 वीं रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि समिति में लेखा परीक्षा विभाग का भी एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए, भारत के अपर उप महालेखा परीक्षक (रेलवे) को इस समिति में शामिल कर लिया गया है। लोक लेखा समिति के निदेशानुसार इस समिति को लोक लेखा समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए, लेन-देन के इस विशेष मामले की विस्तृत जांच करनी है।

वाराणसी-भटनी यात्री गाड़ी की दुर्घटना

1390. श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि 13 मई, 1967 को आंधी आ जाने के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी और पियोकोल स्टेशनों के बीच 7 डाउन वाराणसी–भटनी यात्री गाड़ी की भयानक दुर्घटना हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) रेलवे की कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 13.5. 1967 को 72 डाउन वाराणसी-भटनी सवारी गाड़ी जब पविकोल और भटनी स्टेशनों के बीच से गुजररही थी तब यह एक भयंकर आंधी में पड़ गई जिसके कारण गाड़ी के सभी 11 डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये ।

(ख) इस दुर्घटना में 27 व्यक्तियों को चोटें पहुंची जिनमें से 23 को डाक्टरी सहायता के बाद फौरन छुट्टी दे दी गयी, 3 को रेलवे अस्पताल में रखने के बाद छुट्टी दे दी गयी और एक ने अस्पताल में भर्ती होने से इन्कार कर दिया ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 3,31,600 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

भिलाई इस्पात कारखाने को उपकरणों की सप्लाई

1391. श्री कार्तिक ओरावों : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रयादेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा उपकरण तथा ढांचे सप्लाई न किये जाने के कारण भिलाई इस्पात कारखाने की छः धमन भट्टियों के समूह के निर्माण में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो (1) माल देने के कार्यक्रम के अनुसार क्रयादेशों के आधार पर सप्लाई किये गये उपकरणों तथा ढांचों का ब्यौरा क्या है, (2) वचन पूरे करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और (3) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को भिलाई इस्पात कारखाने की निर्धारित क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची में ढलाई तथा गड़ाई का कार्य

1392. श्री कार्तिक ओरावों : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची का ढलाई तथा गढ़ाई का कार्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) ढलाई व गड़ाई परियोजना में कितने टन माल की ढलाई तथा गड़ाई होती है;

(दो) भारी मशीन निर्माण कारखाने की ढलाई की कुल आवश्यकता कितनी है; और

(तीन) भारत मशीनी कारखाने की ढलाई की कुल आवश्यकता कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, जब ढलाई व गढ़ाई परियोजना में पूरा उत्पादन होने लगेगा ।

(ख) (1) 1,23,820 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ।

(2) और (3) यह आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ठीक ठीक कितने आर्डर पूरे किये जाते हैं किन्तु स्थापित उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग पर आधारित अनुमानों के अनुसार जब भारी मशीनें बनाने वाला कारखाना और भारी मशीनी औजार कारखाना पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगेगा तो उन्हें इस्पात तथा भूरे लोहे के ढले हुए क्रमशः लगभग 51000 मिट्रिक टन और 11000 मीट्रिक टन पुर्जों की आवश्यकता होगी ।

भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची

1393. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची के भारी मशीनी औजार कारखाने का उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) इसे ग्राहकों से कितनी राशि के माल के क्रयादेश मिले हैं;

(ग) उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये भारी मशीनी औजार कारखाना कितना उत्पादन करेगा; और

(घ) इस कारखाने में पूरी क्षमता पर उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :(क) भारी मशीनी औजार कारखानों की अन्ततोगत्वा निर्धारित क्षमता 10,000 मी० टन प्रति-वर्ष है ।

(ख) 1967-68 में 37 मशीनों का निर्माण करने का कार्यक्रम है। चार मशीनों के लिए पक्के आर्डर प्राप्त हो चुके हैं तथा 27 और मशीनों के आर्डरों के लिए बातचीत चल रही है ।

(ग) 1966-67 की अवधि में 6 रेडियल ड्रिलिंग मशीनों और एक डबल कालम प्लेनिंग मशीन का निर्माण पूरे आयातित पुर्जों को जोड़कर किया गया था ।

(घ) पूरा उत्पादन 1971-72 तक होने लगने की संभावना है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची का चेयरमैन

1394. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के चेयरमैन को भर्ती करने। बर्खास्त करने तथा पदोन्नति करने के मामले में क्या शक्तियाँ दे रखी है; और

ये शक्तियां अन्य सरकारी उपक्रमों के प्रधानों को दी गई ऐसी ही शक्तियों से कहां तक भिन्न हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भर्ती, बर्खास्तगी तथा पदोन्नति के मामलों में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष संस्था की अन्तर्नियमावली के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इन मामलों में सरकार द्वारा अध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Land Utilised by Diesel Locomotive Works, Varanasi

1395. Shri Nihai Singh :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether certain parts of the land acquired from farmers in District Varanasi for the purpose of setting up a diesel railway locomotive factory is being utilised by the Diesel locomotive Works for cultivation ;

(b) if so, the total acreage of the land under cultivation ; and

(c) whether Government have decided to set up some other factory on the said land ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. Certain pieces of land have been temporarily allotted to groups of Diesel Locomotive Works employees for cultivation till such time as these lands are developed and utilised for future construction of quarters and service buildings in pursuance of the 'Grow More Food' policy of the Government.

(b) 80 acres (Approximately).

(c) No.

पंजाब मेल से सेना के जवान का गिरना

1396. श्री अगाड़ी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मई, 1967 को मथुरा और कोसीकलां स्टेशनों के बीच सेना का एक जवान पंजाब मेल से नीचे गिर पड़ा था ;

(ख) क्या इसके कारणों की जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) सही स्थिति यह है कि 5.5.67 को अंझाई और छाता स्टेशनों के बीच खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण 5 डाउन पंजाब डाक 39 मिनट रुकी रही। रिपोर्ट के अनुसार सेना का एक जवान जो दरवाजे के पास अपने बक्स पर बैठा हुआ था, गाड़ी से गिर पड़ा। गाड़ी को अंझाई स्टेशन के बाहरी सिगनल तक वापस ले जाया गया, लेकिन जवान का कोई पता नहीं चला। मथुरा और कोसीकलां की सरकारी रेलवे पुलिस तथा छाता की जिला पुलिस ने भी यह सूचित किया है कि इस तरह की घटना की उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली मुआफ किया जाना

1397. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम व पते क्या है जिनसे निर्धारित क्षतिपूर्ति के कारण ली जाने वाली 75 लाख रुपये की राशि की वसूली लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन द्वारा मुआफ कर दी गई है;

(ख) क्या इन फर्मों को आयात लाइसेंस देने से पहिले इनकी पूंजी वित्तीय स्थिति, उनके मालिकों के नाम और उनकी निर्माण क्षमता उनके कारखानों के उत्पाद तथा कारखानों के पते तथा आयकर की राशि व इनके द्वारा किया गया भुगतान आदि मूलभूत तथ्यों के बारे में कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी रकम की वसूली मुआफ की गई है;

(घ) इस धनराशि की वसूली करने में क्या बाधा पेश आ रही है और क्या इसके लिये कोई अधिकारी अथवा लाइसेंस देने की प्रक्रिया जिम्मेदार है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में इस प्रकार की बातें न होने पायें क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) आयातकर्त्ताओं से अधिभार की वसूली करने के क्या नियम है तथा इस बात का क्या ब्यौरा है कि उनसे अभी तक 40 लाख रुपये की राशि वसूल करना बकाया है, हालांकि उन्हें माल मिल चुका है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न में जो बातें पूछी गई हैं उन सब का प्रकरण आडिट रिपोर्ट (सिविल) 1967 में आता है। यह रिपोर्ट 7 अप्रैल, 1967 को सभा पटल पर रखी गई थी। लोक लेखा समिति इन सभी बातों को भली प्रकार जांच करेगा। अतः समिति द्वारा इन बातों की जांच पूरी कर लेने से पूर्व सरकार के लिए इन मामलों पर कुछ कहना उचित न होगा।

फर्मों से राशि की वसूली

1398. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15,000 टन टिन का आयात करने में हुई 1 लाख 46 हजार रुपये की हानि को, क्रयादेश देने वाली फर्मों से वसूल करने की बजाये स्वयं वहन करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसकी मंजूरी सरकार से ली गई है और क्या इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं०सेठी) : (क) से (ग) : प्रश्न में जो बातें पूछी गई है उन सब का प्रकरण आडिट रिपोर्ट (सिविल) 1967 में आता है। यह रिपोर्ट 7 अप्रैल 1967 को सभा पटल पर रखी गई थी। लोक लेखा समिति इन सभी बातों की भली प्रकार जांच करेगी। अतः समिति द्वारा इन बातों की जांच पूरी कर लेने से पूर्व सरकार के लिए इन मामलों पर कुछ कहना उचित न होगा।

Transporation of Motor Cars

1399. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether maximum cost of road transporation of motor cars from factory to marketing place is determined by Government while fixing the sale price of motor cars at various places and if so, the procedure followed ;

(b) whether the cost of transportation is determined in proportion to distance and if not, whether the dealers have been authorised to add to the ex-factory price as much transportation charges as they consider proper;

(c) the prices fixed for the sale of fiat, Ambassador and Standard cars at Patna, Calcutta, Bombay, Madras and Delhi ; and

(d) whether the tools given alongwith these motor cars are examined as to their quality and usefulness and whether the price fixed for these tools is refundable if a customer does not want to purchase them ?

The Minister of Industrial Development and company affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : Government of India only approve of the ex-factory retail prices of motor cars. The manufacturers are permitted to add to the ex-factory price the actual cost of transportation. This naturally varies from place to place and is not fixed by Government.

(c) As stated earlier, the prices approved by Govcrement are ex-factory and not ex show-room at the various centres in the country.

(d) Government do not go into the quality and usefulness of the tools supplied along with the motor cars. No separate price is approved by Government for these tools. Government understand that neither the manufacturers nor the dealers of cars have fixed a separate price for the tools; go with the car and no refund is given to any customer who does not desire to take the tools with the car.

मोटर गाड़ियों का निर्माण

1400. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्माण की जारही छोटी और बड़ी मोटरकारों, ट्रकों, बसों के ढाचों (बसी) यात्री बसों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमायें निर्धारित की गई है और यदि हां तो निर्माताओं के नाम तथा पिछले तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक निर्माता को एक वर्ष में कितनी मोटरगाड़ियों का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी तथा प्रत्येक निर्माता ने वास्तव में कितनी मोथ मोटरगाड़ियों का निर्माण किया, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ मोटरकार निर्माताओं ने सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक मोटरकारें तैयार करने की अनुमति मांगी थी ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में किन किन निर्माताओं ने किस किस तारीख को यह अनुमति मांगी थी और प्रत्येक मामले में क्या क्या निर्णय किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मोटरगाड़ी निर्माताओं को दिये जाने वाले औद्योगिक लाइसेंसों में यह दिखाया जाता है कि कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है सरकार के तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय समय पर वास्तव में स्थापित क्षमता का भी अनुमान लगाया जाता है और जांच पड़ताल के बाद इस स्थापित क्षमता के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। यदि निर्माता उनके लिए नियत की गई विदेशी मुद्रा में से ही कई पालियों में काम करके और अतिरिक्त मशीनों को लगाये। प्राप्त किये बिना लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर सके इसके लिए उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त तथा स्थापित क्षमता और गत तीन वर्षों में उनके द्वारा किए गए उत्पादन के आंकड़े दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 509/67)**

(ख) और (ग) : दिसम्बर, 1966 में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता ने प्रतिवर्ष 30,000 एम्बैसेडर कारों के उत्पादन के लिए आवश्यक पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात विदेशी मुद्रा के नियतन करने के लिए आवेदन किया था और उन्होंने यह दावा किया था कि वे इतनी कारों का उत्पादन अतिरिक्त उपकरणों के बिना ही कर सकेंगे। विदेशी मुद्रा सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई थी।

जनवरी, 1967 में मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० बम्बई ने प्रति वर्ष 30,000 फिएट कारों का उत्पादन करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता में काफी विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर में सेवा नियोजन

1401. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर का कोयला खान तथा संबंधित मशीनरी कारखाने के प्रबन्धक सेवा नियोजन के मामले में स्थानीय लोगों को वरीयता देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 को वहाँ के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा उनमें स्थानीय लोग (जिस जिले में परियोजना है तथा आसपास के जिलों के) कितने लोग थे ; और

(ग) जिस राज्य में परियोजना है वहां के लोगों की संख्या तथा अन्य राज्यों के लोगों की कुल संख्या तथा स्थानीय लोगों की कुल संख्या कितनी है, जिनका मासिक वेतन 1600 रुपये तथा उससे अधिक है और जिनका मासिक वेतन 1000 रुपये तथा उससे अधिक किन्तु 1600 रुपये से कम है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भर्ती के मामले में खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने इसको स्वीकार कर लिया है कि निम्न वेतन पाने वाले स्थानों पर यदि संयंत्र के आस पास के स्थानीय व्यक्ति मिल जायें तो अधिक लाभदायक रहेगा ।

(ख) 31 मार्च, 1967 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 6,340 थी । जिस जिले में संयंत्र स्थापित है और उसके अड़ोस-पड़ोस के जिलों में रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 1967 को 3000 थी ।

(ग) यह परियोजना पश्चिमी बंगाल में स्थित है और उस राज्य के कर्मचारियों की कुल संख्या 5,041 है । अन्य राज्यों के कर्मचारियों की कुल संख्या 1,299 है । ऐसा कोई भी स्थानीय कर्मचारी नहीं है जिसका मासिक वेतन 1,600 रुपये प्रतिमास से अधिक हो और ऐसे स्थानीय कर्मचारियों की संख्या 4 है जिनका वेतन 1000 और 1,600 रुपये के बीच है ।

ट्रैक्टरों तथा छोटी कारों का निर्माण

1402. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने छोटी कारों के निर्माण के लिये संसाधनों के नियतन का विचार करते समय छोटी कारों के निर्माण की तुलना में देश में छोटे तथा सस्ते ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये दी जाने वाली पारस्पारिक प्राथमिकता का विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : पुर्जों, कच्चे माल आदि का उदारतापूर्वक आयात करने के लिए आयात लाइसेंस स्वीकार करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त 59 उद्योगों की जो सूची तैयार की गई थी उसमें कृषि ट्रैक्टर उद्योग सम्मिलित हैं । यात्री कार उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त 59 उद्योगों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

हिन्दुस्तान प्लान्टेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

1403. श्री गणेश : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हिन्दुस्तान प्लान्टेशन (प्राइवेट) लिमिटेड को कितना ऋण दिया है तथा क्या इस फर्म को ऋण मंजूर करने से पहले इस फर्म तथा इसके निदेशकों के पूर्व इतिहास तथा शोध क्षमता की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई थी;

(ख) क्या इस फर्म को 'ईष्ट वे कचाल' में भूमि खुले टेंडरों द्वारा दी गई थी या समझौते द्वारा दी गई थी; और

(ग) इस फर्म से ऋण वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या ऋण अदा न करने वाली इस फर्म के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फिएट कारों को नियतन

1404. श्री गणेश : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिये नियत किया गया फिएट कार का कोटा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित है;

(ख) 1960 में अब तक कितने अधिकारियों को फिएट कार दी गई है तथा इनमें से कितने अधिकारी प्रतिनियुक्त पर है;

(ग) 1960 से अब तक क्रमशः कुल कितने ऐसे अधिकारियों को जो एक वर्ष छः महीने, तीन महीने और एक महीने में उन द्वीप समूहों से चले गये हैं, फिएट कारें दी गई; और

(घ) अन्दमान के कोटे से कार लेने वाले कितने अधिकारियों ने द्वीप समूह से बाहर किसी स्थान पर कारें ली ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Jute factory in Bihar

1404. Shri Cananand Thakur : Will the Ministr of Commeree be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Saharsa and Purnia Districts of North Bihar and principal jute producing centres;

(b) whether it is a fact that the production of jute has gradually declined during the last two or three years for want of a jute factory in Shaharsa district and because farmers are not paid reasonable prices;

(c) whether it is a fact that inter alia other things raw material is not in short supply for the setting up of a jute factory in Shaharsa district; and

(d) if so, when Government propose to set up a jute industry in this backward border area ?

The Deputy Minister in the Ministry of commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (d) (A statement is attached).

Statement

Saharsa and purnea constitute the largest jute-production districts in Bihar. The production of jute in these districts during the last few years has been of the following order:—

Year	Lakh Bales
1961–62	11·0
1962–63	8·7
1963–64	10·0
1964–65	7·8
1965–66	7·9

2. The production of jute (and mesta) has declined in all the jute growing areas in India including Bihar, owing mainly to adverse weather conditions during the last three years. The quality of the jute grown in Saharsa and Purnea is comparatively inferior and as a result, this jute fetches a lower price. It is not correct to say that the production of jute has declined for want of a jute-factory or because farmers are not paid reasonable prices. Due to acute shortage of raw jute in the country during the preceding seasons, prices of jute all over the country (including Purnea and Saharsa) were ruling at high lavels both at Calcutta and in the mufossil markets. While it is a fact that there is no jute mill in Saharsa District, there are already three jute mills in Bihar and the bulk of their requirement of fibre is met from jute grown in Purnea and Saharsa Districts. The country as a whole has more jute-manufacturing capacity than can be fed fully by the raw jute currently available, with the result that the requirements of the existing mills are met by allowing import of raw jute from time to time. The only way to ensure better price for Saharsa jute is to improve the quality and yield of the fibre.

3. There is no proposal to set up a jute mill in the jute-producing area of the District.

अधिक भाड़े वाला माल

1406. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अधिक माल-भाड़े वाले कुछ वर्गों के बारे में अध्ययन करने का निर्णय किया है ताकि सड़क परिवहन से होने वाली प्रतियोगिता का सामना किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन का निष्कर्ष कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे में ऊंची भाड़ा दर वाले माल यातायात को कायम रखने के प्रश्न पर रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेल प्रशासन लगातार ध्यान देते रहे हैं। जब कभी आवश्यक होता है, भाड़ा दरों में समंजन करने और रेल सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए समय-समय पर उपाय किये जाते हैं।

(ख) चूंकि ये अध्ययन लगातार चलते रहते हैं और समय-समय पर जो सूचना मिलती है उनके अनुसार कारवाई की जाती है, इसलिए इस तरह के अध्ययनों के परिणाम बताना न सम्भव है और न वांछनीय।

रेलवे एवं सरकारी उपक्रमों में चार्जमैन तथा फोरमैन

1407. **श्री स० च० बेसरा :** क्या रेलवे मन्त्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे की वर्कशापों तथा शेडों में और हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार तथा नेशनल स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड में चार्जमैनों तथा फोरमैनों के कर्त्तव्यों, योग्यताओं, भरती के तरीकों, पदोन्नति के अवसरों कार्य स्वरूप, जिम्मेदारियों तथा वर्कशाप की सुविधाओं के मामले में वर्ग-वार मूल-भूत अन्तर क्या क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में चार्जमैनों के लिए प्रोत्साहन बोनस

1408. **श्री स० च० बेसरा :** क्या रेलवे मन्त्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों में कार्य करने वाले चार्जमैनों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन बोनस की दरों को न बढ़ाने के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन बोनस की जो दरें पहले से मंजूर हैं, वे पर्याप्त समझी जाती है और इन दरों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण

1409. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग से छोटे ट्रैक्टरों, जिनका छोटे खेतों तथा चावल के खेतों में आसानी के साथ प्रयोग किया जा सके के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जापानी फर्मों के सहयोग से पावर टिलर्स (छोटे ट्रैक्टरों) के निर्माण के लिए कई योजनाओं को लाईसेंस, आशय पत्र अथवा सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :-

क्रम सं०	निर्माता का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	स्थान	क्षमता स० प्रतिवर्ष	टिप्पणी
1.	कृषि इन्जनस् प्रा० लि० हैदराबाद	मेसर्स अकीतु आफ़ जापान	सन्तनगर हैदराबाद	6,000	फर्म में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।
2.	मेसर्स वी. एस. टी. मोटर्स लि.,बंगलौर	मेसर्स मित्या बीथी हेवी इन्डस्ट्रीज़ लि., जापान	बंगलौर	5,000	6-4-66 को लाइसेंस दिया गया।
3.	मेसर्स जे.के. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स् लि.,कानपुर	मेसर्स सातोह एग्रीकल्चरल मशीन मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, टोक्यो	कानपुर	6,000	29-4-67 को लाइसेंस दिया गया।
4.	मेसर्स हैदराबाद आलविन मेटल वर्क्स लि, हैदराबाद	मेसर्स इसकी एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० टोक्यो	हैदराबाद	12,000	13-3-67 को लाइसेंस दिया गया।
5.	मेसर्स प्रवारा टूल्ज एण्ड इम्प्लीमेन्टस कोआपरेटिव सोसाइटी, प्रवरनगर	मन्मार डीज़ल इन्जन कम्पनी लि०	प्रवरनगर	—	केवल आशय पत्र जारी किया गया है और औद्योगिक लाइसेंस विदेशी सहयोग से उपबन्धों की स्वीकृति तथा आयातित मशीनों की आवश्यकता की स्वीकृति के बाद जारी किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त दो और योजनाऐं, एक पंजाब सरकार की और एक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की कमशः 12,000 तथा 15,000 पावर टिलर्ज प्रतिवर्ष को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इन योजनाओं में भी जापानी सहयोग की व्यवस्था है। इसको विस्तृत योजनाऐं प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाकर 1967 के अन्त तक कर दिया गया है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा कच्चे माल की खरीद

1410. श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्चे माल को खरीदने के अपने तरीके के कारण सरकारी उपक्रमों को होने वाले घाटे को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकारी उपक्रमों द्वारा कच्चा माल खरीदने के लिये अपनाई गई पद्धति से हुए घाटे के बारे में कोई भी सूचना अथवा शिकायत न होने के कारण किसी प्रकार का सुधार करने की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

वायदा बाजार आयोग

1411. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांतवाला समिति ने वायदा बाजार आयोग के ढांचे तथा कार्य प्रणाली को नया रूप देने और उस प्रयोजन के लिए वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, 1952 का नये सिरे से प्रारूप तैयार करने के लिये सिफारिश की है ;

(ख) क्या सिफारिश पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रबन्ध अभिकरण

1412. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने समवाय ऐसे हैं, जिनकी प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है ; और

(ख) इन समवायों का नियन्त्रण करने वाले प्रबन्ध अभिकरणों की संख्या कितनी है, तथा प्रत्येक प्रबन्ध अभिकरण द्वारा कितने कितने समवायों का नियन्त्रण किया जाता है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की समस्त कम्पनियां, जिनकी प्राधिकृत पूंजी, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है, 938 हैं, जिनमें से 228 कम्पनियों का 179 प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा, प्रबन्ध होता है । इन प्रबन्ध अभिकरणों में से प्रत्येक के प्रबन्ध में, ऐसी कम्पनियों की संख्या निम्नलिखित है :—

प्रबन्ध अभिकरणों की संख्या	प्रत्येक प्रबन्ध अभिकरण के प्रबन्ध में कम्पनियों की संख्या
1	9
1	6
1	5
1	4
6	3
17	2
152	1

कागज तथा गत्ते का आयात

1413. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों में निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत कागज तथा गत्ते के आयात के लिये कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये;

(ख) देश में कागज तथा गत्ते के बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत इन वस्तुओं के आयात में कटौती करने अथवा आयात को बन्द करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक निर्णय न किये जाने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दिये गये लाइसेंसों के मूल्य के आंकड़े वस्तुवार नहीं रखे गये हैं। इसलिये कागज तथा गत्ते जैसी अलग अलग वस्तुओं के संबंध में निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य नहीं बताया जा सकता।

(ख) और (ग) : नई आयात नीति के अंतर्गत केवल पूंजीकृत निर्यातकों को उतने ही कागज तथा गत्ते के आयात की अनुमति दी जाती है जितने आयातित कच्चे माल की उन्हें निर्यात उत्पादों के निर्माण में वास्तव में आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कागज और गत्ते के आयात की अनुमति देते समय स्वदेशी उत्पादन का उचित ध्यान रखा जाता है।

आयात तथा निर्यात

1414. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों में आयात और निर्यात व्यापार में अधिक राशि के बीजक तथा कम राशि के बीजक लाने के कितने मामले पकड़े गये हैं और कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ;

(ख) पिछले बारह महीनों में आयात और निर्यात के नियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं, और

(ग) कितने अफसरों तथा सार्वजनिक नेताओं के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 83 मामले।

(ख) 374 मामले।

(ग) 66 मामलों में मुकदमे चलाये गये और 7 में दण्ड दिया गया। उनमें कोई अफसर नहीं है।

Water Supply at Jhajha and Gomoh Stations

1415. Shri R. Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the water supplied to the workers in Jhajha and Gomoh stations on the Eastern Railway is injurious to health;

(b) whether Railway doctors, after examining the water have also supported this fact; and

(c) if so, the arrangements proposed to be made by Government to provide pure water to the workers and when these arrangements would be made ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Water is supplied at both Gomoh & Jhajha after filteration and chlorination. The water at Gomoh has been found to be statisfactory and potable on analysis by the Railway doctors.

At Jhajha, however, the filteration plant, which was installed in 1953, is not working efficiently. On isolated occasions, the water has been found unsatisfactory, particularly during and immediately after rains. Samples are tested every day by the doctors and on those days when the sample is found to be unsuitable, the staff are warned to draw water from the open wells provided in the colony. In the meantime, overhauling of the filteration plant has been taken in hand. This is expected to be completed by 3 -9-67 and after its completion, it is expected that there would be no grounds for such complaint.

सी रामपुर कोयला खान का बन्द किया जाना

1416. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गिरिडीह में सीरामपुर कोयला खान को बन्द करने और उसके 1500 कर्मचारियों की छटनी करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं और इसे होने से बचाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ; और

(ग) क्या बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के सरकारी उपक्रमों को गिरिडीह का ऊंची किस्म का कोयला बेचने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बिहार की सीरामपुर और कुरहुरवाड़ी कोयला खानों में,जो गिरिडीह खान समूह के नाम से जानी जाती है,लगभग एक शताब्दी से कार्य हो रहा है। अच्छी किस्म के कोयले के संचयों के समाप्त होने के कारण सीरामपुर की कोयला खान का केन्द्रीय गढ़ा जुलाई 1967 में बन्द किया जाना प्रस्तावित है। सीरामपुर के केन्द्रीय गढ़े के बन्द हो जाने से 1148 मज़दूरों और 201 एवजी के रूप में काम करने वालों की छंटनी की संभावना है। इसी मध्य में इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है तथा संचयों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) गिरिडीह के ऊंची श्रेणी के कोयले के लिए बाजार ढूंढने में कोई भी कठिनाई नहीं है।

मनुष्य के बालों का निर्यात

1417. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनको मनुष्य के बालों का निर्यात किया जा रहा है तथा इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, हांगकांग, आस्ट्रिया, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भारत से मनुष्य के बालों (बिना तैयार किये) तथा उसकी रद्दी का आयात करने वाले मुख्य देश हैं। 1964-65, 1965-66 तथा अप्रैल 66-जनवरी 67 की अवधि में किये गये निर्यात का मूल्य क्रमश : 29, 65 लाख रुपये, 44. 19 लाख रुपये तथा 90.73 लाख रुपये था।

निर्यात शुल्क

1418. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद निर्यात शुल्क में हुई कटौती से अवमूल्यन का प्रभाव समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जब कभी निर्यात शुल्क लगी हुई वस्तुओं की प्रतियोगिता स्थिति विदेशी बाजारों में कमजोर हुई, तभी निर्यात शुल्कों में कटौती की गई। निर्यात को कायम रखने तथा बढ़ाने के लिये की गई ऐसी कार्यवाही किसी भी रूप में अवमूल्यन के उद्देश्य से, जो कि निर्यात को कायम रखने तथा बढ़ाने के लिये है, प्रतिकूल नहीं है।

ढाली-राजहारा-दांतेवाड़ा रेलवे परियोजना

1419. श्रीमती अगम दास गुरू मिनिमाता :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के दक्षिणी बस्तर क्षेत्र के विकास के लिये ढाली-राजहारा-दांतेवाड़ा रेलवे परियोजना के महान् महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके मन्त्रालय का विचार कुछ अन्य परियोजनाओं की तुलना में, जो तत्काल लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इस परियोजना को सर्वाधिक वरीयता देने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : चौथी पंच वर्षीय योजना में जिन नयी लाइनों के बनाने का प्रस्ताव है उनके सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। इसलिए इस लाइन को अधिभावी प्राथमिकता देने का अभी सवाल नहीं उठता।

Sago And Sago Flour Importers Association

1420. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Rabi Ray :
Shri S.M. Joshi :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from Sago and Sago Flour Importers Association in which they have mentioned an estimated loss of rupees one hundred and fifty crores as a result of the stoppage of import of Sago and Maize for preparing starch; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Import of Sago and Sago flour has been banned for a number of years, and to the extent possible, domestic sources of starch, such as tapioca and maize, are being utilised for conversion into industrial starches. To the extent that some of imported maize is also allowed for purposes of manufacture of starches, the fact is that imported maize grains are actually cheaper than imported Sago or Sago flour and, therefore, in this process, there has been a saving rather than a loss of foreign exchange. Efforts are also being made to grow hybrid maize in adequate quantities with a view to achieving self-sufficiency in this commodity also.

गजेन्द्रगड़कर प्रतिवेदन के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER RE : GAJENDRA GADKAR REPORT

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 376 (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी ही ध्यान दिलाने वाली सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : गजेन्द्रगडकर आयोग का समस्त प्रतिवेदन आज के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हो गया है परन्तु उसको अभी सभापटल पर नहीं रखा गया है । मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि उक्त प्रतिवेदन 30 मई को प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने अभी कोई वक्तव्य नहीं दिया । पहले हमें उनका वक्तव्य सुनना चाहिये ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार का इन्कार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"निर्वाह व्यय सूचक अङ्क में औसतन दस अङ्कों की वृद्धि के बावजूद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार का इन्कार।"

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने 25 मई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में सदन को बताया था कि वर्तमान अवसर पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों की समीक्षा करने से पहले, सरकार गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों पर विचार करना चाहती है, जिसे उन सिद्धान्तों की जाँच करने के लिए कहा गया था जिनके आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भविष्य में मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट 30 मई की शाम को मिल गयी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। आयोग की सिफारिशों पर निर्णयों की घोषणा करने से पहले कुछ और समय की आवश्यकता होगी। लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को, जो 5 मई को व्यय सचिव से मिले थे, यह आश्वासन दिया गया था कि जो भी निर्णय किये जायेंगे उनको 1–2–1967 की पिछली तारीख से लागू किया जाएगा, क्योंकि तब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत, मंहगाई भत्ते की दरों में पिछली बार किये गये संशोधन के बाद से, 10 अङ्क ऊपर चला गया था। ऐसा ही एक आश्वासन 30 मई को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सम्बन्धी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी दिया गया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the report of the Gajendragadkar Commission will be placed on the Table to-day ?

श्री स० मो० बनर्जी—मैं इस बात की पुष्टि चाहता हूँ कि क्या जो कुछ समाचार-पत्रों में छपा है वह ठीक है अथवा नहीं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे केवल दो प्रतियां ही प्राप्त हुई हैं। मैं उनको सभा-पटल पर रखता हूँ। मैं इसकी प्रतियाँ यथासम्भव शीघ्र मुद्रित करा रहा हूँ। आवश्यक प्रतियाँ न होने के कारण मन्त्रिमण्डल द्वारा इस पर विचार करना सम्भव नहीं हो सका है।

Shri Madhu Limaye : May I know from what source the press got that information?

Shri Morarji Desai : What can I say about it. But whatever has appeared in the Press is not correct.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना निर्वाह व्यय सूचक अङ्क में औसतन दस अङ्कों की वृद्धि के बावजूद भी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि न करने के बारे में है। जब दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था तो स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह पंचाट के समान है।

फरवरी, 1967 में निर्वाह व्यय सूचक अंक में दस अंकों की वृद्धि हो गई थी। इस लिये 22 लाख सरकारी कर्मचारी कानूनी तौर पर अधिक मंहगाई भत्ता पाने के अधिकारी हैं। क्या मंहगाई भत्ता देने में विलम्ब करने तथा इसको न देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जब तक गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें नहीं मिल जाती तब तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती क्योंकि इस आयोग को इसी उद्देश्य हेतु नियुक्त किया गया है। हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी वचन दिया है कि कोई निर्णय करने से पूर्व उनसे भी परामर्श किया जायेगा। इसलिए निर्णय करने में कुछ समय लगेगा। परन्तु हमने यह भी कहा है कि निर्णय करने में चाहे कितना समय लगे परन्तु उसको 1 फरवरी, 1967 से ही लागू समझा जायेगा।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I would like to know whether Government is taking steps to see that prices do not rise unless there is a rise in dearness allowance.

Shri Morarji Desai : Had the Government been able to do that they would have done that.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सामान्य व्यक्ति का निर्वाह व्यय बढ़ गया है। सरकार ने पिछले आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है और वे सिफारिशें अभी तक लागू हैं। जब तक कोई अन्य स्वीकार्य सूत्र उनका स्थान नहीं ले लेता तब तक सरकारी सेवा में सामान्य व्यक्ति को उन सिफारिशों के लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार की वित्तीय नीति है। तो क्या कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता देने के लिए राज्य सरकारों को, इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, सहायता देना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्या चौथे वित्तीय आयोग ने राज्य सरकारों के इस अतिरिक्त तथा अनदेखे व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए कोई उचित प्रक्रिया बनाने की सिफारिश की है। यदि हाँ तो इस बारे में केरल सरकार की सहायता सम्बन्धी प्रार्थना को पूरा किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए केन्द्रीय सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी। मैं यह बात भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मूल्यों में वृद्धि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक तथा वित्तीय नीति के कारण हुई है।

श्री नायनार (पालघाट) : सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के वचन के बावजूद कोई सुविधा देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री नायनार : क्या यह ठीक है अथवा नहीं कि आयोग ने मंहगाई भत्ते की वृद्धि के एक बड़े भाग को अनिवार्य बचत में परिवर्तन करने का अनौपचारिक प्रस्ताव किया है ? क्या सरकार ने निर्वाह व्यय सूचक अंक में दस अंकों की वृद्धि पर अपने आप मंहगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार द्वारा कोई निर्णय कर लेने पर ही ये बातें उत्पन्न होंगी ।

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : मन्त्री महोदय के वक्तव्य को देखते हुए क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रश्न का मूल विषय से कोई सम्बन्ध नहीं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the employees will get interest on the money due to them since February, 1967 on account of increased dearness allowance which Government propose to give them :

Shri Morarji Desai : No Sir.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह इसके प्रतिवेदन को रद्द अथवा संशोधित कर सकती है तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि कर्मचारियों को 1–2–67 से पहले जो मंहगाई भत्ता मिलता था उसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य स्वप्नों के संसार में रहते हैं ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : अनाज के मूल्यों में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार को कर्मचारियों को कुछ राहत देनी चाहिए । सरकार को इस बारे में भी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को न मिलकर बाजार में न चला जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The hon. Minister has stated that he will not assist the State Governments for paying increased dearness allowance to their staff. On the other hand he says that he will consult the State Government before announcing his decision on the Gajendragadkar Commission's roport.What it means ? Does he want to delay the matter or is he awaiting a countryside agitation from the Central Government employees?

Shri Morarji Desai : We are committed to the Chief Ministers in this respect. That is why we intend to consult them before announcing any decision.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वित्त मन्त्री तथा अब उप-प्रधान मन्त्री के कथन से प्रगट होता है कि वह दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वचन-बद्ध हैं कि निर्वाह व्यय सूचक अंक में दस अंकों तक की वृद्धि के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जाये । उनके कथन से यह भी प्रगट होता है कि कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1967 से अधिक मंहगाई भत्ता दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों को तत्काल सहायता देने की घोषणा करने में सरकार को क्या बाधा हो रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने केवल यह कहा है कि सब मामलों पर विचार करने के पश्चात सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लागत लेखा रिकार्ड्स (साइकल्स) नियम

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा रिकार्ड्स (साइकल्स) नियम, 1967 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस. आर, 311 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 496/67]

सिंगारेणी कोलियरीज कम्पनी तथा कोयला बोर्ड के प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:—

(1) (एक) कम्पनी-अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सिंगारेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 497/67]

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कोयला बोर्ड, कलकत्ता, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 498/67]

कपड़ा समिति आदि के लेखे के बारे में प्रतिवेदन

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कपड़ा समिति के वर्ष 1965-66 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 499/67]

(2) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कपड़ा समिति (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 438 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 500/67]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1722 की एक प्रति जो दिनांक 15 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 501/67]

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत कपड़ा (विद्युत् करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1475 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 502/67]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 740 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 503/67]

(6) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1744 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 504/67]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं 5 जून 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ :

(1) रेलवे मन्त्री का उत्तर

(2) 1967–68 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा

(3) भ्रष्टाचार निवारण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 पर चर्चा तथा पास किया जाना।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I would like to know whether Government propose to bring some Bill in regard to ban the cow slaughter ? I would also like to know whether Government propose to bring some Bill in regard to agarbatti manufacturers ?

Dr. Ram Subhag Singh : Business to be conducted in House is decided by the Business Advisory Committee. These matters have not been raised there by the representative of the hon. Members party.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : The Government has decided to appoint a Committee to go through the whole and names have been called for from the Mahabiyan Samiti. As soon as the names are received the Committee will be appointed.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : I would like to know whether there is any difference in regard to the number of representatives of the Samiti and the Government ?

Shri Jagjiwan Ram : No Sir.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would request the hon. Minister to take up the motion regarding the situation of West Asia which stands in the name of Smt. Tarkeshwari Sinha soon after the reply given by the Railway Minister in the railway debate.

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा (आनन्द) : पिछले सत्र में हिन्दू धर्म धर्मस्व विधेयक को पुर-स्थापित किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस विधेयक को पुनः पुर-स्थापित करेंगे ?

श्री कन्डापन (मैटूर) : गैर-हिन्दी भाषी लोगों-विशेषकर मद्रास के लोगों ने यह मांग की थी कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए रखने के लिए संविधान में संशोधन किया जाये। सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह संविधान के बजाय अधिनियम में संशोधन करेगी। इस बारे में कोई संकेत नहीं मिल रहा कि सरकार कब ऐसा करेगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर इस समय संसदीय समिति में चर्चा हो रही है। समाचारपत्रों में भी इस बारे में बहुत कुछ आ चुका है। ऐसा लगता है कि शिक्षा की मांगों पर चर्चा के लिए केवल पांच घण्टे का समय दिया गया है। शिक्षा को इस बार प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि हम शिक्षा के पूरे ढांचे को ही बदलने का विचार कर रहे हैं। अतः इसे अधिक समय दिया जाना चाहिये।

दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चीन में हुये आणविक शक्ति के विकास को देखते हुए क्या भारत को अणु बम बनाना चाहिये या नहीं। परमाणु शक्ति का विभाग एक महत्त्वपूर्ण विभाग है जिसके लिये केवल दो घण्टे ही नियत किये गये हैं। उसके लिये भी अधिक समय मिलना चाहियें। संसद कार्य विभाग के लिये भी एक घण्टा दिया गया है जो बहुत थोड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इन सबके लिये समय कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया है जिसके प्रतिवेदन को सभा ने स्वीकार कर लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन और आर० के० हजारी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया है। यह अवसर उपयुक्त है क्योंकि बजट पर भी शीघ्र ही चर्चा होने जा रही है।

हम पिछले सात वर्षों से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि रूबी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी और न्यू एशियाटिक कम्पनी की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाये। परन्तु आज तक वह मांग स्वीकार नहीं की गई। अब जबकि आर० के० हजारी समिति के प्रतिवेदन के माध्यम से बिरला समूह पर चर्चा होने जा रही है तो उपरोक्त दोनों कम्पनियों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को भी सभापटल पर रखा जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It was the practice during the period, when Shri Iyyangar was the Speaker that atleast one No–Day–Yet–Named Motion would be taken up in two weeks-time. But now the No–Day–Yet–Named Motions are being ignored. On last Friday it was decided that a No–Day–Yet–Named Motion regarding the situation arising out of the resumption of arms supply by Western countries to Pakistan and the increased tension on the border. I request the Minister for Parliamentary Affairs for including in List of Business a motion regarding concentration of Pakistani Forces on the border of Akhnoor and air intrusion by Pakistan in Rajasthan. I again request that some practice should be established in respect of No–Day–Yet–Named Motion.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : It is the long established convention that all the matters of public importance are discussed in Parliament, when it is in session. Now there are two crises before the country–the economic crisis and the crisis from security point of view. Economic situation will be discussed while discussing the budget. The other matter is the latest developments in the South East Asia, which will affect Indian security to a great extent, because Pakistan is likely to launch crusade against India. This matter should be discussed in the House on priority basis.

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान का मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है और सोमवार को इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : कई सरकारी निगम बड़े ही महत्त्व के हैं, जैसे जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड आदि। इनके समय-समय पर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं, परन्तु, उन पर चर्चा करने का समय नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार भूतलिगम प्रतिवेदन जैसे अन्य प्रतिवेदनों के लिये भी समय नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये एक सप्ताह में दो घंटे नियत किये जाने चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay–South) : Since the marriage of Maharaja of Sikkim with an American girl there has been some change in the attitude of Sikkim towards India. Though we have given Calling Attention Notice on this matter but that was dis-allowed. Now I request again that this matter should be discussed in the House soon.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सिक्किम का मामला सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये, क्योंकि सिक्किम के साथ हमारे सम्बन्ध एक सन्धि पर आधारित है। इस विषय में मेरी यह राय है कि विदेश मन्त्री को वक्तव्य देकर वे सब शंकाएं दूर कर देनी चाहिये जो सिक्किम के बारे में पैदा हो गई हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : पश्चिमी एशिया की स्थिति के लिये अगले सप्ताह में समय दिया जाना चाहिये, क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। बजट पर रेलवे मन्त्री के उत्तर के बाद इस विषय पर गैर-सरकारी प्रस्ताव या मंत्री के वक्तव्य के माध्यम से चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है इसलिये मैंने सरकार से इस विषय पर चर्चा के लिये समय देने को कहा है। मेरी राय में सिक्किम के मामले पर यहां विचार नहीं किया जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : अनियत दिन वाले प्रस्तावों के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनके बारे में विचार किया जायेगा ।

सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, रंगा और मधु लिमये आदि सदस्यों ने पश्चिमी एशिया, पाकिस्तान से खतरा तथा सिक्किम मामले आदि का भी जिक्र किया है । सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान इन सभी विषयों पर चर्चा की जा सकती है । हजारी समिति के प्रतिवेदन को भी समय मिलने पर लिया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री के इस कथन से मैं सहमत नहीं हूं कि अनियत दिन वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । कार्य मंत्रणा समिति ने ऐसे पांच प्रस्तावों को चुना था जिनको लेने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा ।

जहां तक संविधान संशोधन विधेयक या हिन्दू धर्म धर्मस्व विधेयक आदि की अभी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि बजट पर वाद-विवाद समाप्त होने के बाद ही इन्हें किसी उपयुक्त समय पर लिया जा सकेगा । श्री दी० चं० शर्मा ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बातचीत की थी । अणु-शक्ति विभाग की मांगों के लिये दो घंटे नियत किये हैं । श्रीमान जी, यदि आप चाहें तो, जो एक घंटा आपकी इच्छानुसार किसी विषय पर खर्च किया जाना है, उसे आप अणु शक्ति विभाग के लिये नियत कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब रेलवे बजट पर विचार-विमर्श होना है और हमारे पास केवल दो घण्टे शेष हैं । सभी विरोधी दलों का समय लगभग समाप्त हो गया है । यह बचा हुआ समय भी माननीय सदस्यों को ही दिया जायेगा और रेलवे मन्त्री सोमवार को प्रश्न-काल के बाद उत्तर देंगे ।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म. प. पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

रेलवे आयव्ययक (1967-68) सामान्य चर्चा

(RAILWAY BUDGET (1967-68) GENERAL DISCUSSION)

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा पुनः शुरू होगी ।

श्री सी० दास (तिरूपति) : मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे रेलवे बजट पर बोलने का अवसर दिया गया है । मैं नये रेलवे मन्त्री श्री पुनाचा जी का भी स्वागत करता हूँ ।

मैं अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि हूँ, और इस नाते मुझे रेलवे के किराये और भाड़े में वृद्धि किये जाने का बड़ा दुख है, क्योंकि बढ़े हुए किराये का प्रभाव केवल गरीब यात्रियों पर ही पड़ता है अतः मेरा अनुरोध है कि तीसरे दर्जे का किराया न बढ़ाया जाये। भोजन-यान में तीसरे दर्जे के यात्रियों को तीसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जबकि रेलवे का अधिकतर राजस्व तीसरे दर्जे के किराये से प्राप्त होता है। गर्मी के दिनों में इन यात्रियों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। प्रत्येक स्टेशन पर एक से अधिक पानी की गाड़ी होनी चाहिये जो गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद तीसरे दर्जे के डिब्बों के यात्रियों को पानी सप्लाई करें। रेलवे में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। परन्तु अब इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है इसका क्या कारण है ? मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के आसपास के स्टेशनों पर विभागीय खान-पान की व्यवस्था बड़ी ही शोचनीय है। यहां अच्छे माल के स्थान पर सस्ता माल यात्रियों को दिया जाता है। आजकल रेलवे तथा सरकारी कर्मचारियों को पूरे परिवार के लिये प्रथम श्रेणी के पास दे दिये जाते हैं। ऐसे पासों की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि कुछ यात्रियों को, जो प्रथम श्रेणी में यात्रा करना चाहते हैं, स्थानाभाव के कारण निराश होना पड़ता है।

रायलसीमा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं की बहुत कमी है। इस क्षेत्र में बड़ी रेल योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले तत्काल इस बात की आवश्यकता है कि पकाला से धर्मवरम की ओर रात को जाने वाली मीटर गेज की गाड़ी के साथ कटपडी से सिकन्दराबाद तक एक सीधा डिब्बा जोड़ा जाय। बम्बई मेल या बम्बई एक्सप्रेस में, जो मद्रास से चलती है, सिकन्दराबाद के लिये एक सीधा डिब्बा जोड़ा जाये। साथ ही पकाला और धर्मवरम के बीच वाली गाड़ी को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना होगा तथा उस लाइन को मदनपल्ले हरसले हितस की ओर मोड़ना होगा। चूँकि मदनपल्ले एक सुविख्यात स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान है। अतः मैं रेलवे प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले पर वे शीघ्र ध्यान दें।

गत 3 वर्षों से हम यह आशा कर रहे है कि नन्दयाल से मदनपल्ले के बीच एक रेलवे लाइन की आशा करते आ रहे हैं। परन्तु रायलसीमा के लोगों की यह आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। दक्षिण-मध्य रेलवे जोन के बन जाने पर यह आशा की जाती थी कि आन्ध्र रेलवे कर्मचारी जो अन्य जोनों में काम करते हैं, वे सब दक्षिण-मध्य जोन में काम पर लगाये जाते हैं। मद्रास–बम्बई के बीच वाली रेलवे लाइन को पार करने वाली सड़क पर, जो तिरूपति नामक धार्मिक स्थान को जाती है, एक ऊपरी पुल और एक निचला पुल बनाया जाना चाहिये। पुत्तर के स्टेशन पर बम्बई मेल या बम्बई एक्सप्रेस में से कोई एक गाड़ी अवश्य ही रुकनी चाहिये, क्योंकि यहां तालुक मुख्यालय है और यह एक धार्मिक स्थान और श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये पकाला से तिरुपति और कालाहस्ती से तिरुपति के बीच शटल गाड़ियां चलायी जानी चाहियें।

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : I would like to draw the attention of Railway Minister to the deplorable condition of Gaya Station. Gaya is a religious centre, where lakhs of people go every year for religious purposes. There are five platforms but none of them has platform number plate or urinal or latrine. Railway lines are full of dirty soil and they give bad smell. It is the great example of inefficiency and mismanagement on the part of Railways.

A train service namely P. G. D. train has been started between district Gaya and Palaman. It runs between Patna and Dihari. A large number of people of this area are taking benefit of it. But there is one thing to be noted in this respect. This train does not stop on all the stations between Dihari and Gaya, while it is a must, because no other train is there to cater the needs of the passengers and there is great rush on bus routes between Dihari and Gaya. My other suggestion is that the railway line, which is there between Patna and Rajgraha via Bihar Sharif should be further extended to Gaya; which is pilgrimage. It will provide facility to pilgrims as well as add to the income of the Railways.

I support this Railway Budget. It is a deficit budget. The reason given by the Railway Minister for the deficit do not include the reasons like inefficiency and corruption which is rampent in railway administration. The Minister has tried to have a curtain on them, because the revealation of these things would have been the self-criticism of railways structure. Alongwith other things the Minister should pay attention to this aspect also.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : हमें आशा थी कि रेलवे आयव्ययक से जनसाधारण को कुछ राहत मिलेगी परन्तु किरायों की वृद्धि के कारण जनसाधारण पर और अधिक बोझ पड़ा है। यह तर्क दिया गया है कि क्योंकि कम दूरी वाली रेलवे लाइनें लाभप्रद नहीं हैं, इसलिये रेलवे के किरायों में वृद्धि कर दी जाये। लगभग आधी जनता कम दूरी वाली रेलवे लाइनों पर यात्रा करती है जिसमें से 90 प्रतिशत लोग निर्धन व्यक्ति हैं इस प्रकार किरायों में वृद्धि से निर्धन व्यक्तियों पर ही अधिक बोझ पड़ा है। कांग्रेस के मन्त्री लोकतंत्र और समाजवाद के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। परन्तु व्यवहार में वे सब कुछ भूल जाते हैं। 19 करोड़ रुपये के घाटे को वे खर्च में कमी कर के पूरा कर सकते थे। हम तो उस दिन को देखने की इन्तजार में हैं कि जब जनसाधारण को यह विश्वास हो जायेगा कि टिकट खरीदने के बाद उन्हें गाड़ी में स्थान अवश्य मिल जायेगा। कांग्रेस के मन्त्री नौकरशाही के गुलाम बन चुके हैं। **(व्यवधान)** लोकतंत्र में नौकरशाही प्रगति के लिये बाधक होती है। ब्रिटिश शासन के समय रेलवे को जो थोड़ा बहुत लाभ था वह ब्रिटेन के खजाने में जाता था परन्तु अन्तर इतना ही है कि अब रेलवे बोर्ड के निदेशकों के पास जाता है और भारतीय खजाने में सम्भवत: कुछ भी नहीं पहुंचता।

यदि किराये बढ़ा भी दिये गये थे तो अनिवार्य वस्तुओं पर रेल भाड़े में वृद्धि तो नहीं करनी चाहिये थी। यदि मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि अनिवार्य वस्तुओं पर रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया जायगा तो सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। इसका कारण यह है कि रेल भाड़े में वृद्धि से अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में भी एकदम वृद्धि हो जायेगी। जिसके फलस्वरूप निर्धन जनता और पिसेगी।

गाड़ियों की गति बहुत धीमी है। जापान में बिजली से चलाई जाने वाली गाड़ियों की गति 120 मील प्रति घंटा है। इससे दुर्घटनाएं भी नहीं होतीं। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी की जानी चाहिये।

आज रेलवे के खर्च में कमी करने की बहुत आवश्यकता है। अपव्यय, चोरी आदि को रोक कर और बड़े बड़े अधिकारियों वाले विशेष प्रकार के सैलून दिये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर के कुछ बचत हो सकती है। सतर्कता विभाग का पुनर्गठन करके भी कुछ धन बचाया जा सकता है। यदि सतर्कता विभाग इन्हीं अधिकारियों के अधीन काम करेगा तो भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में वह कैसे सफल हो सकता है। सतर्कता विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिये।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेलवे बोर्ड सतर्कता महानिदेशक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन काम करता है ।

श्री स० कुन्डू : हम चाहते हैं कि सतर्कता विभाग रेलवे विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के प्रभाव से परे हो । मैंने पिछली बार अपने वक्तव्य में कहा था कि विभिन्न साधनों को कुछ कम विकसित राज्यों में विकसित करने के विषय में अध्ययन करने के लिये एक जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिये । उड़ीसा की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है । रूरकेला से तलछट और तलछट से कटक तक एक लाइन बनाई जानी चाहिये और इसे पारदीप से मिला दिया जाना चाहिये । टाटा से कटक तक एक सीधी लाइन बरास्ता बारीपाडा बनाई जानी चाहिये । बोलंगीर से खुरदा तक एक लाइन और सम्बलपुर से तलछर तक एक दूसरी लाइन बनाने के बारे में जांच-पड़ताल की जानी चहिये ।

यह कहना अनुचित है कि नैरोगेज लाइनों से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है । वह सब काल्पनिक बातें हैं । इन लाइनों को समाप्त करना उचित नहीं होगा । सभा में सभी सदस्यों ने मांग की है कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना चाहिये । ऐसा करने के पश्चात ये लाइनें भी लाभप्रद सिद्ध होंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने भाषण के लिये 7 मिनट से अधिक समय न लें, जिससे यह चर्चा 3·30 तक समाप्त हो सके ।

Shri Tamaskar (Durg) : Efficiency in the Railways has gone down as Railway employees are dissatisfied with their service conditions and their grievances are not being dressed by the authorities. There should be some machinery to examine the demands and grievances of Government servants. The Government should agree to the appropriate demands so that Government servants should not feel dissatisfied. I feel very much pained when I see Government servants resorting to 'Satyagrah' and strikes.

I happened to go to Bilaspur few days back. There was a conference of Railway employees in which Ticket-Checkers and Ticket Collectors were demanding adequate arrangements for their stay at the Railway Stations. This is a genuine demand and it should be acceded to. We should not wait for agitations by the Federation of Government servants. We should be readily agree to the genuine demands.

I know the difficulties being experienced by the passengers travelling in Third Class. All of us have been travelling in III class before coming to this House. I therefore request the Government to note down the difficulties and remove them without creating any fuss. If we remove the difficulties of the people they will naturally realise that the Government is by the people and for the people.

I belong to Chhatisgarh and it takes 36 hours to reach this place. First class comparts are just like furnace. I request Shri Poonacha to make some suitable arrangements for our travel.

Shri Balgovind Verma (Kheri) : I support the budget presented by the Railway Minister. But this budget deficit should not be met by the increase in the fare of passengers travelling in 3rd class. It will increase the difficulties already experienced by the common man. The deficit budget should have been met by more vigilance, economy in expenditure and regularising the timings of trains. The thefts in goods trains should be checked and arrangements for strict vigilance on the Railway property should be made. If thefts are checked the people will have full faith in the Railways. They will send more goods through Railways and it will result in additional income.

There is competition between the Railways and road transport. The people feel that their goods are safe in the roads transport and they will reach the consignee in time.

The Railways should try to load maximum goods which are being carried by road transport at present.

You have made up your mind to root out corruption and I wish you could achieve success. In fact an honest man finds very much difficult to work in the Railways. The fact remains that corrupt employees are flourshing whereas honest employees are suffering. The facts of the corruption have been brought to the notice of Railway Board several times but in vain. No action is taken against the corrupt officials. Generally it is stated that nothing has been substantiated against the persons concerned. This is no pretex. You should not shield the corrupt officials. There are many loopholes in the system of recruitment of collies. If they are considered to be class IV employees and their service is nationalised, there will be greater security of goods.

I request the Hon'ble Minister to extend 63 UP and 64 Down train upto Lakhimpur or Sitapur.

Shri Ramji Ram (अकबरपुर) : I wish to bring to the notice of the Minister that there is no railway line counecting Tanda in U.P. which is being Centre of Cloth business. I suggest that a railway line be constructed to pass though Gosainganj. Tanda, Jalalpur and Azamgarh.

I request the hon. Minister to provide a halt of Sealdah express at Gosainganj. I would also request that an overbridge at Malipur station and an underbridge at Akbarpur which is junction station. The representation scheduled castes and Tribes in higher rank of railway administration is very small. The number of officers belonging to these castes insignificant. I demand that adequate representation should be given to these people and the post reserved for them should be filled from amongst them only.

In the Nav Bharat Times of 1st May, 1967 a news item says that Shri Malhotra, Chief Executive Councillor had said at Hardwar on 1st May, 1967 that Harijans and Muslims should not be given high posts. This statement, if true, is against the provisions of the constitution. I Condemn this.

***श्री शिंकरे (पंजिम) :** गोश्रा ने सरकार को मुक्ति के पश्चात् 45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा कर दी है। अतः रेलवे मंत्री को इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। गोआ में कच्चे लोहे और मैगनीज़ का उत्पादन देश के सभी क्षेत्रों से अधिक है। गोआ का क्षेत्रफल केवल 1234 वर्ग मील है और वहां की जनसंख्या 6 लाख है। इस क्षेत्र में खनिजों के बहुत भण्डार हैं। यदि सरकार विदेशी मुद्रा कमाना चाहती है तो सरकार को वहां की रेलवे सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सरकार को चाहिये वहां के प्राकृतिक संसाधनों से पूरा पूरा लाभ उठाये।

गोआ से 40 मील की दूरी पर गोआ में मार्मागोआ नाम का एक बहुत अच्छा बन्दरगाह है। वहां पर मीटर लाइन है। इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये। मार्मागोआ के बन्दरगाह से अधिक माल विदेशों को निर्यात किया जा सके, इस के लिये सरकार को और अधिक रेलवे सुविधाएं वहां उपलब्ध करनी चाहिये।

मेरी यह मांग केवल उसी क्षेत्र के हित में नहीं बल्कि इस मांग की पूर्ति से पूरे देश को लाभ होगा। इससे देश की सुरक्षा तथा विकास में सहायता मिलेगी।

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : आज की स्थिति को देखते हुए यह रेलवे बजट बहुत अच्छा है। मैं माननीय रेलवे मंत्री को इस बजट के लिये बधाई देता हूँ। रेलें

* मूल मराठी के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित
* English translation of Speech deliver in Marathi.

हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम हैं। इनमें लगभग 3½ लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। प्रतिदिन लगभग 57 लाख व्यक्ति रेल यात्रा करते हैं। किरायों में परिवर्तन करने से पहले सरकार को सभी पहलुग्रों पर विचार करना होता है। रेलों की प्रगति से राष्ट्र की प्रगति सम्बद्ध है। मैं आशा करता हूँ रेलें कार्यकुशलता से चलेंगी और देश को लाभ होगा।

गाड़ियों में भीड़ की समस्या एक जटिल समस्या है। माननीय मंत्री को इस ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये। बिना टिकट के यात्रा भी एक समस्या है। इसे समाप्त करने के लिये कारगर कदम उठाये जाने चाहियें। इससे एक तो आय में वृद्धि होगी और दूसरे लोगों के चरित्र में अच्छाई की भावना पनपेगी।

पिछले कुछ महीनों में आसाम तथा महाराष्ट्र में दुर्घटनाएँ हुई हैं। इनमें सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि रेल कर्मचारी इनके लिये जिम्मेदार हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी इसके लिये जिम्मे-दार हैं।

यात्रियों की सुविधाओं के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। स्टेशनों पर पानी का केवल एक ही नल होता है। इसका अधिक लाभ नहीं होता।

आसाम राज्य की रेलवे प्रशासन द्वारा उपेक्षा की जा रही है। 1962 के चीन के आक्रमण से हमारी आँखें खुल जानी चाहिये थीं। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसाम में रेलों का विस्तार नितान्त आवश्यक है।

आसाम में पुलों के बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। गौहाटी से तिनसुखिया जाने वाली लाइन किसी नगर से होकर नहीं जाती। यह अंग्रेज लोगों, जो बगान के मालिक थे के लिये बनाई गई थी। आसाम राज्य के विकास के लिये वहां और रेलवे लाइनें बनायी जानी चाहियें। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आसाम राज्य के बहुत कम लोग रेलवे में कार्य करते हैं। इस प्रकार इस राज्य से भेदभाव किया जा रहा है। आसाम के निवासियों की अधिक संख्या में रेलवे में नियुक्तियां की जानी चाहिये।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Sir, the time for this discussion should be extended,

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप की मांग अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा. रामसुभग सिंह) : हमें निर्धारित समय के अनुसार कार्य करना चाहिये।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 31 मई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 31 मई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कपड़ा उद्योग में संकट के बारे में संकल्प–जारी

RESOLUTION RE : CRISIS IN TEXTILE INDUSTRY-CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एस्थोस द्वारा 31 मार्च, 1967 को प्रस्तुत किये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :—

कपड़ा उद्योग में विद्यमान संकट को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप मिलें बराबर बन्द हैं और बुनकर भारी संख्या में बेरोजगार हो गये हैं, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी बन्द मिलों का प्रबन्ध तुरन्त अपने हाथ में ले ले ।"

श्री एस्थोस (मुवत्तुपुजा) : श्रीमान 2 महीने हो गये हैं जब मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था । इन दो महीनों में सरकार कपड़ा उद्योग में सुधार लाने में असफल हुई है । माननीय मन्त्री के 4 अप्रैल के वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है । मई से सरकार ने कपड़े की कीमतों में वृद्धि कर दी है । हथकरघा उद्योग की स्थिति भी खराब है । हथकरघा बुनकर सूत उपलब्ध न होने के कारण बेरोज़गार हो गये हैं । मिलों के पास पड़े स्टाक में कमी नहीं हुई है । यह स्थिति अप्रैल 1966 से चली आ रही है । हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है । लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है । कुछ मिलें बन्द भी कर दी गई हैं परन्तु फिर भी उद्योग में काफी स्टाक है । इस प्रकार संकट की स्थिति बराबर चली आ रही है ।

सरकार के विचार में अवमूल्यन के बाद कपड़ा के निर्यात में वृद्धि होती थी परन्तु अब अनुमान लगाया गया है कपड़े के निर्यात में 30 से 45 करोड़ रुपये की कमी होगी। भारत 60 या 70 करोड़ रुपये की रुई का आयात करता है । अवमूल्यन के बाद आयात किये जाने वाले माल के मूल्य में वृद्धि हो गई है । देश के कपड़ा उत्पादन में भी कमी होती जा रही है । उद्योग में जो कुल धन लगा हुआ है वह भी कम है । यह मांग हो रही है कि उद्योग के विस्तार के लिए और धन दिया जाये ।

हथकरघा उद्योग की हालत और भी खराब है । सूत के मूल्य में वृद्धि होने के कारण बुनकरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है । केरल के कन्नूर जिले में ही साठ हजार मजदूर तथा उनके परिवार भूखों मरने जा रहे हैं क्योंकि उनको सूत की सप्लाई बन्द हो गई है । नागपुर के दो लाख बुनकरों की हालत खराब है । आंध्र प्रदेश में भी स्थिति ऐसे ही है ।

मिल मालिक ऐसी स्थिति में सरकार से और रियायतें प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय कपड़ा मिल संघ के अध्यक्ष ने हाल में एक वक्तव्य में यह धमकी दी है ।

कि यदि उनको पर्याप्त सुविधायें अर्थात कपड़ा तथा सूत पर उत्पादन शुल्क में कमी कम्पनी करों में राहत, आयकर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता उद्योग घोषित करना तथा कपड़े के मूल्य तथा उत्पादन से नियन्त्रण हटाना आदि नहीं दी जाती तो अधिक मिलों का बन्द होना अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि क्या यह सब मांगें उचित हैं ?

कपड़ा उद्योग ने पिछले वर्षों में बहुत अधिक लाभ कमाया है परन्तु उस लाभ दुर्विनियोग किया गया है। उद्योगपतियों ने कम्पनी कानून की त्रुटियों से पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

{ श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manoharan *in the Chair* }

कपड़े के मूल्य पहले ही बहुत अधिक बढ़ गये हैं और लोगों के लिए पर्याप्त कपड़ा खरीदना कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में कपड़े के भण्डारों में वृद्धि होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में कपड़े के मूल्य में कमी की जानी चाहिए जिससे लोग पर्याप्त कपड़ा क्रय कर सके। परन्तु उद्योगपति तो कपड़े के मूल्य में वृद्धि के इच्छुक हैं चाहे कपड़े के उत्पादन में कमी क्यों न हो जाये। वे तो केवल मुनाफा कमाना चाहते हैं। उद्योगपति कपड़े के मूल्य से पूरी तरह नियन्त्रण हटाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

कपड़ा मिलों को अधिक रियायतें देने से हथकरघा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले ही उनके लिये मिल के बने कपड़े से स्पर्धा करना कठिन हो रहा है।

मिलों से स्वामी सरकार तथा मजूरी बोर्ड पर दबाव डाल रहे हैं ताकि मजूरी में वृद्धि की सिफारिश न की जाये। कपड़ा मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी उत्पादन लागत का केवल 26 प्रतिशत है।

कपड़ा उद्योग सट्टा खेलने वालों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। रुई की उपज से पूर्व ही रुई के खेतों को क्रय कर लिया जाता है और यही व्यापारी उपज को बाद में ऊंचे मूल्यों पर बेचते हैं। जब तक सूत का थोक व्यापार को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती तब तक रुई का संकट समाप्त होने वाला नहीं है।

सरकार द्वारा हाल ही में की गई कार्यवाही से रुई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिली रुई के वितरण के लिए एक एजन्सी का कार्य कर रही है। आज रूई निर्धारित मूल्य पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है और सरकार का यह आश्वासन कि वह समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी केवल कागज पर ही विद्यमान है। पी० एल० 480 पर निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिये। 50 प्रतिशत उत्पादन लागत केवल रुई पर ही होती है इसलिए इस ओर शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है।

मिलों के बन्द होने सम्बन्धी मामलों से निपटने वाली सरकारी व्यवस्था बहुत समय लेती है। रुपये के गड़बड़ के मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त करने में महीनों एवं वर्ष तक लग जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन अनियमितताओं की जांच तथा मिलों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार को स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।

कुछ मिलें वास्तव में वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुई हैं। ऐसे मामलों में सरकार को ऋण देकर सहायता करनी चाहिए।

सरकार तथाकथित रोगी मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये एक कपड़ा निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह दूसरा राजकीय क्षेत्र सिद्ध हुआ तो कपड़ा उद्योग के भाग्य का अन्दाजा लगाया जा सकता है। कपड़ा मिलों को बिना विलम्ब पुनः खोलने के लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि बड़ी-बड़ी मिलों की सहायता करने की नीति चालू रखी गई तो कपड़ा उद्योग नष्ट हो जायगा।

हथकरघा उद्योग को सरकार द्वारा तुरन्त सूत की सप्लाई की जानी चाहिए। उनको आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं प्रस्तावक के साथ इस बात में सहमत हूँ कि बेरोजगारी को और अधिक बढ़ाने से रोकना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है परन्तु उन्होंने इनके लिए जो विधियां सुझायी हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार द्वारा इन मामलों को अपने हाथ में लेने से यह समस्या हल नहीं होगी। वास्तव में स्थिति यह है कि जिस किसी मामले में सरकार ने हाथ डाला है वहां स्थिति और उलझ गई है।

मिलें कुप्रबन्ध तथा किसी अन्य प्रशासनिक कारण से बन्द नहीं हुई हैं बल्कि रूई के वितरण सम्बन्धी सरकार की गलत नीति के कारण ही स्थिति में बिगाड़ हुआ है। सरकार की वर्तमान नीति से बड़ी मिलें अधिक प्रगति कर रही हैं तथा छोटी मिलें बन्द होती जा रही हैं।

सूती कपड़ा उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला तीसरा बड़ा उद्योग है। परन्तु इसके साथ साथ यह उद्योग विदेशी मुद्रा व्यय भी बहुत करता है। प्रत्येक वर्ष रुई खरीदने के लिए 46 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इसको रोकने के लिए कुछ कार्यवही की जानी चाहिये। आयात की गई रुई का केवल 4.6 प्रतिशत भाग ही निर्यात किये जाने वाले कपड़े में लगाया जाता है शेष भारत में प्रयोग किये जाने वाले कपड़े में ही इस्तेमाल होता है। सरकार की आयात की इस नीति से मिलों में भी विभेद किया गया है। बड़ी बड़ी मिलों को रुई आयात करने की अनुमति दी जाती है जो बाजार में 40 प्रतिशत अधिक भाव पर बिकती है। छोटी मिलों को भी आयात का कोटा दिया जाना चाहिए जिससे वे मिलें भी अपने पांव पर खड़ी हो सके। दूसरा विकल्प यह है कि आयात की गई कपास को खुले बाजार में विक्रय किया जाये और इससे होने वाले लाभ से कपड़ा मिलों के लिए एक विशेष निधि स्थापित की जाये जिससे उनको अपनी स्थिति सुधारने के लिए ऋण दिया जा सकता है।

छोटी तथा नई मिलों को कुछ सहायता दी जानी चाहिए। जिससे देश की विभिन्न मिलों में असमानता दूर हो सके। रियायतों के फलस्वरूप जमा होने वाली राशि को विस्तार के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु सुरक्षित निधि बनाई जा सकती। जब तक छोटे एकको की प्रगति नहीं होती तब तक वर्तमान स्थिति में सुधार सम्भव नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : It has been the experience that mills taken over by the Government are not functioning properly. So the Government should not take over the closed mills. It will be better if these mills are handed over to the workers to give them the incentive for more production.

Shortfall in the production of cotton is responsible for the present crisis in the Textile industry. It is, therefore, requested that Government should take some steps to increase the production of raw cotton. Efforts should also be made to produce the quality cloth so that we could earn more foreign exchange.

Allegation has been made that Ram Lal Jawahar Lal Company in Madhya Pradesh set on fire their stock of cotton to get the insurance money. During the last session assurance was given to investigate the matter but nothing has been done so far in this regard. Such anti-social activites should be dealt with strong hand.

Due to the shortage of cotton the weivers in handlom industry are not getting the yaran. They are sitting idle. Something should be done in this regard also.

It is matter of great regret that Government has not taken any steps to recover the arrears of Provident Fund from a Mill in Bhopal whereas for the same purpose they took strong steps against a Mill in Indore. Such a discriminatory attitude is improper.

Excessive excise duty is responsible for the rise in the prices of cloth. This should be reduced so that people could get cloth at cheap rates.

Government should help the progressing smaller units as an incentive so that they may be able to produce quality cloth. There are many such mills in Madhya Pradesh.

Increasing use of terrylene and Nylone cloth is also causing harm to the textile industry. Government should do something to attract the people to the cotton cloth.

श्री देवव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सरकार पहले ही उन सभी प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो सभा के समक्ष रखे गये हैं। समूचे मामले की छानबीन की जा रही है। एक कपड़ा निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है।

अमरीका में एक ऐसी विचारधारा है जो हम दबाव डालकर वर्तमान कठिन स्थिति से लाभ उठाना चाहती है। वह लोग नहीं चाहते कि अधिक क्षेत्र में कपास की उपज करें। ऐसा सुझाव दिया गया है कि भारत अधिक कपास का आयात कर सकता है और कि यही हमारे लिए लाभदायक हैं। इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

इस बात पर सन्देह है कि कपड़ा उद्योग ने भारत की अच्छी सेवा की है। एक सदस्य ने कहा है कि धन को मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है परन्तु मिल वालों ने ऐसा न कर धन को सट्टा बाजार तथा अन्य क्षेत्रों में व्यय किया है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योगों से लाभ नहीं हुआ है क्योंकि पहले यह प्रचार किया जाता रहा है कि इस क्षेत्र को 'कोई लाभ नहीं' के आधार पर तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के, उद्योगों के लिये मूल उद्योग के आधार पर चलाया जाये। सरकारी क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, मूल्यों को स्थिर करने तथा बेरोजगारी कम करने में समर्थ न देने के लिए है।

श्री कन्डायन (मैंदूर) : इस संकल्प में कपड़ा उद्योग में उत्पन्न हुए संकट की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा सरकार द्वारा रोगी मिलों को अपने हाथ में ले लेने के लिए कहा गया है। इस बात में सन्देह है कि इन मिलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने से स्थिति में सुधार हो जायेगा। सरकार ने जिन आठ मिलों को अपने हाथ में लिया था उनमें से कोई भी मुनाफे में नहीं चल रही है। अब जैसा कि प्रातः कहा है कि सरकार एक कपड़ा निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है तो मेरे विचार में सरकार को इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए।

वर्तमान संकट केवल कुप्रबन्ध तथा अदक्षता के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि वास्तविक कारण यह है कि गत कुछ वर्षों से कपास के उत्पादन में कमी हुई है। इस प्रकार देश में इस समय कपास की निरन्तर कमी है। अवमूल्यन के पश्चात कपड़े के निर्यात में बढ़ोत्री के बजाय कमी हुई है। इस मामले में पूरी तरह विचार किया जाना चाहिये।

यद्यपि हम सबसे अधिक कपड़ा बनाने वाले देशों में से हैं तथापि हमने कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। गवेषण से पता चलता है कि यदि उचित पानी तथा उर्वरक उपलब्ध किया जाये तो कपास की उपज दुगनी अथवा तीन गुणा की जा सकती है।

कपास की उपज के लिए धान तथा गन्ने की तरह अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से पानी से कपास की कहीं भी उपज की जा सकती है।

सरकार ने उर्वरक के लिए दी जाने वाली राज सहायता में कमी कर दी है जो कि उचित नहीं है। तर्क यह दिया गया है कि उर्वरक की मांग बहुत है। इस प्रकार उत्पादन लागत बढ़ जायेगी और किसान निर्धारित मूल्य पर कपास नहीं दे सकेंगे। जब तक उत्पादन लागत में कमी नहीं की जाती तब तक कपड़े के मूल्यों में कमी करना मुश्किल है।

सूत के मूल्य बढ़ जाने के कारण मद्रास, आंध्र तथा अन्य स्थानों में लाखों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं। इसलिए इसके लिए किसी प्रकार की राज सहायता दी जानी चाहिए। सूत की ऐसी किस्मों पर विशेषकर जिनका प्रयोग हथकरघा उद्योग में किया जाता है। मन्त्री महोदय को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I support this resolution Inspite of three five Year Plans the food situation in the country has been deteriorated. The rich persons have become richer and the poor have become poorer. The manner in which Government has abolished Zamindari system and distributed the land among the landless persons, in the same manner Government should take over the Textile Mills and give it to the labourers. They should be provided with all the necessary facilities and given incentive to produce more so that we may earn more foreign exchange.

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*

Industry in India has been monoplished by a few industrialists viz. Birla, Tata Jain etc. Our Government gives open support to Birla. Birla family has become

controller of Indian economy. The Government may nationalise all the Mills but I may inform that it is not only Birla who can manufacture small cars or who can prepare art silk yarn. Birlas are making huge profits. If the mills will be in the hands of labourers, it will benefit a large number of people. In view of this Government should accept this resolution which is in the interest of labour.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : इस संकल्प के प्रस्तावक का आशय कपड़ा उद्योग के संकट की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक राज-रत्न मिल है जो पिछले एक वर्ष से बन्द है। इसके फलस्वरूप 1500 व्यक्ति बेकार पड़े हैं। सरकार ने इसकी जाँच करने के लिये घनश्याम लाल ओझा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसका प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है। मालिकों का कहना है कि कपड़ा उद्योग में संकट केवल कुप्रबन्ध के लिये ही नहीं अपितु इस संकट के और भी कई कारण हैं जैसे रूई की कमी, रूई का ऊँचा मूल्य, कपड़े के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण, अधिक उत्पादन कर, और वित्त तथा आधुनिकीरण सम्बन्धी कठिनाइयां। हमारे देश में कपड़े के दो प्रकार के कारखाने हैं एक तो पुराने कारखाने हैं जिनकी मशीनें बदलने वाली है तथा दूसरी ओर बम्बई और अन्य स्थानों के आधुनिक कारखाने हैं जो कर्मचारियों की संख्या को कम करके आधुनिक मशीने लगाना चाहते हैं।

वाणिज्य मन्त्री का विचार है कि सरकार संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का स्वामित्व और प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये एक निगम की स्थापना करे। मुझे यह भी पता चला है कि उद्योग विकास तथा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी मिलों की छानबीन करने के लिये जांच समितियों की स्थापना की जाने की भी सिफारिश की गई है जिनके बन्द हो जाने की सम्भावना हो। इससे सरकार को उन कारखानों का प्रबन्ध सम्भाल लेने में सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की एक स्थायी व्यवस्था की स्थापना की जाये। मुझे पता चला है कि सरकार स्थिति पर ध्यान रखे हुए है ताकि ऐसे कारखानों का पता चल सके जिनके प्रबन्ध में गड़बड़ी हो रही हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि धनवान व्यक्ति अधिक धनवान होते जा रहे हैं और निर्धन व्यक्ति और निर्धन हो रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। श्री हुकम चन्द कछवाय का सुझाव सही है कि जिन मामलों में कर्मचारी धन बचा सकते हैं और भविष्य निधि में धन लगा सकते हैं वहां वे सहकारिता के आधार पर मिल का स्वामित्व सम्भाल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि कर्मचारी वर्ग भी लाभ उठा सकें।

इसलिये में इस संकल्प को अनावश्यक समझता हूँ। अतः इसे वापिस ले लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे संक्षेप में बोलें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। हमारे नेता श्री डांगे ने मन्त्री महोदय से भेंट की थी तो उन्होंने उनको सुझाव दिया था कि इस समस्या का समाधान एक ही है और वह यह कि इन कारखानों का कार्यभार केन्द्र सरकार स्वयं

सम्भाल ले और उनके प्रबन्ध के संचालन के लिये एक कपड़ा निगम की स्थापना कर दी जाये। मुझे प्रसन्नता है कि यह सुझाव सरकार ने मान लिया है।

संकटग्रस्त वही कारखाने हैं जिनमें मध्यम कोटि का या सस्ता कपड़ा बनता है, उन कारखानों को जितनी रुई की आवश्यकता होती है उतनी रुई उन्हें नहीं मिलती है। वास्तव में बिड़ला ग्रुप का इस क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि छोटे कारखानों का चलना कठिन हो गये हैं। बिड़ला इस देश में शार्क मछली के समान है। फूलबाग़ी शरीफ़ और गया में एक एक कारखाना बन्द हो गया है जिससे 1500 कर्मचारी बेकार हो गये हैं। इसी प्रकार कानपुर में भी न्यू विक्टोरिया मिल के बन्द हो जाने का खतरा है। लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के बन्द हो जाने से 6000 व्यक्ति बेकार हो गये हैं। इस मिल के मालिक ने लगभग 6000 व्यक्तियों को पिछले बारह महीने में उनकी मजदूरी भी नहीं दी। इस मिल का कार्यभार संभालने के विषय में मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब तक कि यह विधेयक पास नहीं हो जाता तब तक सरकार किसी भी मिल का नियन्त्रण अपने हाथ में नहीं लेगी। हाँ, यदि राज्य सरकार ऐसा करना चाहे तो केन्द्र सरकार को आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम के लिए केन्द्र से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता चाहती है, मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विषय में अनुकूल रवैया अपनायें।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जब कभी सरकार किसी कारखाने का कार्यभार संभाल लेती है तो उसकी कार्यकुशलता में कमी हो जाती है। वास्तव में इन कारखानों का नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हों।

मैं सब प्रकार के दबावों के बावजूद सरकार द्वारा इन कारखानों का नियन्त्रण सम्भाल लेने का सब प्रकार से समर्थन करता हूँ। लक्ष्मीरतन काटन मिल्स में क्या हुआ? इस कारखाने के मालिक श्री राम रतन गुप्ता ने मन्त्रियों या राज्यपालों के सम्बन्धियों को नियुक्त कर लिया और साधन उसके पास इतने थे नहीं। अतः अब मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार इन कारखानों का नियन्त्रण सम्भाल ले।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I support this resolution. I welcome the announcement made by the Hon'ble Minister that Government is going to establish a corporation in other to run the Mills already taken over by Government. In this connection I would, however, like to say that when India United Mills, Bombay was taken over by the Government, the private enterprises manager in such a way that the cloth prepared by this mill could not go to the market. The result was that stock of cloth in this Mill was piled up. I want to say that this thing in the context of establishment of a corporation to run such sick Mills. If no arrangement is made to sell the goods prepared by these Mills. It may become a problem to dispose of the stocks and the Mills might have to be closed. If the Government think that they will devise some way out to lift this stock they should apply that method just now. If this thing is not done, I am afraid, the Mills will be forced to close.

I had suggested that Government should not charge that much excise duty on the cloth prepared by the Mills run by Government as it is being charged on the cloth prepared in other private Mills. In this manner owners of private mills will not continue to make profit for all times to come.

I want to make another suggestion with regard to the disposal of stocks being filed up in these Mills. The Government should purchase all its requirements of cloth from these Mills instead of Mills owned by private enterprises. Director General of Supplies and Disposals may, of course, make less profit but it will certainly help thousands of labourers working in these Mills.

Inspite of all the credit facilities provided to the private enterprisers if they continue to run their Mills at a loss and Government is to support them, then the best thing would be to nationalise the whole industry.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support this Bill whole heartedly. Ceiling of land holding was a step in the right direction. Similarly there should be some ceiling to the ownership of Mills also. It may be Tata or Birla-they should have one Mill each and rest of Mills should be taken over by the Government. There should not be any discrimination in this matter. We should think of the welfare of thousands of labourers working in these Mills and the cultivators who produce cotton. It will be in the interest of the nation as a whole to nationalise this industry. It would be alright, if the Mill owners readily agree to hand over the charge of the Textile Mills otherwise the Government should take over these Mills forcibly-because these Mills are national property.

श्री श्री० ग्र० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण) : मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्राय: यह देखा गया है कि जब सरकार मिलें लेती है तो सबसे प्रथम कार्य मजदूरों के महंगाई भत्ते में कटौती कर देती है । ऐसा नहीं होना चाहिए । इन मिलों के प्रबन्ध कार्य के साथ जब तक मजदूरों को सम्बद्ध नहीं किया जाता इनके कार्य में प्रगति नहीं हो सकती । इन मिलों की दुर्व्यवस्था का कारण वहां निदेशकों की लापरवाही है । ये लोग मिल के खातों से निजी लाभ उठाते हैं । यह एक तथ्य है और बहुत सी जांच समितियों ने इसकी पुष्टि की है । एक मिल के मामले में मैं जानता हूँ जहां 96 लाख रुपये का गबन हुआ था । उसकी जांच हुई थी परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । बाद में जब श्री मोरारजी देसाई ने हस्तक्षेप करके निदेशकों को बदल दिया तो उस मिल ने दो वर्षों तक मुनाफा दिखाया । मैं चाहता हूँ कि धोखे से धन लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये कोई संस्था होनी चाहिए । मिल मालिक इन मिलों से अनुचित लाभ उठाते हैं । वे लोग सरकार से धन के रूप में सहायता प्राप्त करते हैं । आपको इसका उदाहरण शोलापुर तथा बम्बई की मिलों से मिल सकता है । अतः मैं आशा करता हूँ कि कारपोरेशन ऐसी मिलों के निदेशकों की रक्षा नहीं करेगी ।

इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह पहले के अनुभव से लाभ उठाकर सावधान रहे । मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री सभा के सदस्यों से सलाह-मश्विरा करेंगे और कार्मिक संघों से भी सलाह की जायेगी ।

सरकार को चाहिए कि अलाभप्रद मिलों के साथ साथ कुछ लाभ देने वाली मिलों को भी अपने हाथ में ले । इससे अलाभप्रद मिलों को लाभदायक बनाने में सहायता मिलेगी । सरकार को चाहिए कि उपभोक्ता के प्रयोग की सभी अनिवार्य वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण कर दे ताकि बड़े बड़े मिल मालिकों के शोषण से बचा जा सके ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कपड़ा उद्योग हमारे देश का सबसे प्रथम उद्योग है परन्तु आज इसका सबसे पहले पतन हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ मिलों के बारे में जानता हूं जहां प्रबन्धकों ने मजदूरों को वेतन देना बन्द कर दिया है। इस कारण मजदूरों को हड़ताल करनी पड़ गई। मालिक लोग सरकार से ऋण लेते हैं परन्तु वे स्वयं लाभ उठाते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले निगम को कुछ लाभप्रद मिलों को भी अपने नियन्त्रण में लेना चाहिए।

रूई की कीमतों में वृद्धि हो गई है और मिल मालिकों स्टाक रखे हुए हैं परन्तु बेचारे मजदूरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा उद्योग के मजदूरों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। सरकार को उनकी सहायता के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। इस उद्योग में लाखों लोग काम करते हैं।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : कपड़ा उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेकर अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं। इस उद्योग में एक बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। इस उद्योग के ठीक प्रकार से चलने में हम सबकी रुचि है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने पर विचार किया है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए बड़े जोरदार शब्दों में मांग की है। मैं इस बारे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। इस समय 27 मिलें बन्द पड़ी हैं। इनके अतिरिक्त 13 मिलें काम कर रही है। इन 13 में से भी दो बन्द कर दी गई हैं। इन मिलों के बन्द किये जाने के कई कारण हैं। कुछ में आर्थिक संकट है। और कुछ में मजदूरों आदि की कठिनाई है। हमारी मुश्किल यह कि जब हम संकट ग्रस्त मिल को अपने हाथ में लेते हैं और जब वह अच्छी प्रकार से कार्य करने पर लाभदायी सिद्ध होती है तो मालिक लोग उसे वापिस लेने की मांग करने लगते हैं। मैं मानने को तैयार नहीं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यसंचालन ठीक प्रकार से नहीं होता। इन मिलों का उदाहरण हमारे समक्ष है जहाँ पर कि मालिक लोग मिलों को वापिस लेन की मांग करने लगते हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र ने गैर सरकारी क्षेत्र को पछाड़ा है।

श्री श्री० अ० डांगे : शोलापुर की मिल ऐसा ही एक उदाहरण है। जहां मालिकों ने वापिस किये जाने की मांग की थी।

श्री दिनेशसिंह : 13 मिलों में 11 मिलों में हमने लाभ प्राप्त किया है। कपड़ा उद्योग में निरन्तर नवीकरण और नई प्रकार के माल के उत्पादन की आवश्यकता रहती है। हमारे देश का रूई उत्पन्न करने वाले देशों में चौथा स्थान है परन्तु यहां का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की उपेक्षा बहुत कम है। रुई का मूल्य हमारे देश में लगभग सभी देशों के भावों से ऊँचा है। ऐसी स्थिति में कपड़ा उद्योग को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है। यह एक प्रवृत्ति सी बनती जा रही है कि नई मिलें स्थापित की जायें और पुरानी मिलों का नवीकरण न किया जाये। इस ओर हमें ध्यान देना होगा।

रूई तथा सूत की कमी के कारण हथकरघा उद्योग को भी मुश्किल हो रही है। विदेशों से रुई मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आशा है कि आगामी वर्षा ऋतु के बाद हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। हम बुनकरों की शिकायतें दूर करने का भी यत्न करेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): You should give them subsidy.

Shri Dinesh Singh : We are prepared to give subsidy provided this House gives money to us.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): I have come after touring the flood affected areas. You would distribute clothes in these areas.

श्री दिनेश सिंह : श्री तापड़िया ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं उसके लिये आभारी हूं। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे। निगम के गठन से पहले मैं श्री डांगे से मिलूंगा। हम चाहते हैं कि मजदूरों को निगम के प्रबन्ध में स्थान दिया जाये। श्री कछवाय ने मुख्य मंत्री के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं होगा कि जो लोग यहां सदन में नहीं उनके बारे में इस प्रकार नहीं कहना चाहिये। मुख्य मंत्री को तो सरकार की ओर से किराया मिलता होगा। इसलिये यह किसी मकान में मुफ्त रहना चाहें इसका कोई नाजायज़ फायदा उठाये, यह बात ठीक नहीं मालूम होती।

I am not in agreement with the contention of Shri Kachwai that Government should not take over sick mills. We must take over such as are likely to improve by our intervention in their affairs. Shri Banerjee referred to Lakshmi Rattan Mills. I have given reply to this in the morning. The Central Government has got only two mills under its control the remaining are under State Government. They are run with the consent of Central Government. We have no objection if U.P Government wants to run this particular mill. We cannot take over more mills at present. A corporation is to be set up. A bill in this respect is to be brought here. I do not know any justification for this resoulation here now.

श्री एस्थोस : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है और मूल्यवान सुझाव दिये हैं। मैं माननीय मंत्री की भी सराहना करता हूं कि जिन्होंने एक निगम बनाने का आश्वासन दिया है और मिलें सरकार निगम द्वारा लिये जाने की बात की है। मैं चाहता हूं कि हथकरघे के बारे में और कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि सभा इसको स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस संकल्प पर कुछ संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री उमानाथ, श्री यशपाल सिंह और श्री रामामी के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments know by Shri R. Umanath, Shri Yashpal Singh and K. Ramani were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कपड़ा उद्योग में विद्यमान संकट को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप मिलें बराबर बन्द हैं और बुनकर भारी संख्या में बेरोजगार हो गये हैं, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी बन्द मिलों का प्रबन्ध तुरन्त अपने हाथ में ले ले ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

इस्पात से नियन्त्रण हटाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: STEEL DECONTROL

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा सरकार द्वारा इस्पात से नियन्त्रण हटाये जाने का, जिसके फलस्वरूप इस्पात का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, निरनुमोदन करती है ।"

मुझे खेद है कि सरकार ने नियन्त्रण हटाने का निर्णय इतनी जल्दी में कर दिया है। इस निर्णय के तुरन्त बाद इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। इससे जनसाधारण को बहुत मुश्किल हो गई है। सरकार दावा करती है कि कीमतें बढ़ने नहीं दी जायेंगी परन्तु संयुक्त योजना समिति को यह काम क्यों सौंप दिया गया है। इस समिति में टाटा आदि बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो सिद्ध करते हैं कि नियन्त्रण हटने के बाद इस्पात के मूल्य में वृद्धि हुई है। इससे छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत हानि हुई है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई है और जिन्हें सरकार खरीदती है। ऐसी वस्तुएं रेलवे के प्रयोग की हैं। रेलवे स्लीपर खरीदती है। उनके मूल्य में लगभग 40 रुपये की वृद्धि हो गई है इस प्रकार टाटा की आय में वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार पहियों और टायरों की बात है। आप एक समिति के अध्यक्ष थे। उस समिति ने जब नियन्त्रण हटाने की सिफारिश की थी उन्होंने और कारणों से वह सिफारिश की थी। उस समिति का नाम खाडिलकर समिति था। आज देश को आर्थिक संकट में से गुजरना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार जून 5, 1967 जेष्ठ 15, 1889 शक के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, June 5, 1967 Jyaistha 15, 1889 (Saka)